सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

केवल आंतरिक परिचालन के लिए

सेन्ट्रलाइट
CENTRALITE

खंड / Vol. 42 - 2021, अंक - 4
दिसंबर / Dec. 2021

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा हमारे आंचलिक कार्यालय दिल्ली का निरीक्षण दि.25.10.2021

झलकियां

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही गृह-पत्रिका

A Quarterly House - Journal of Central Bank of India

• खंड / Vol. 42 - 2021 • अंक - 4 • दिसंबर / Dec, 2021

.. न हि ज्ञानेन सदृशं ..

संपादक
स्मृति रंजन दाश

संपादक मंडल
नमिता रॉय शर्मा
वास्ती वेंकटेश
एस. एच. अय्यूबी
राजीव वार्ष्णेय

संपादकीय सहायक
छाया पुराणिक
अभय कुलकर्णी

Editor
Smruti Ranjan Dash

Editorial Board
Namita Roy Sharma
Vasti Venktesh
S. H. Ayubi
Rajiv Varshney

Editorial Assistant
Chhaya Puranik
Abhay Kulkarni

ई-मेल / E-mail
centralite1982@gmail.com

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं से बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है.
Articles Published in this magazine does not necessarily contain views the Bank.

विषय-सूची / CONTENTS

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश / Message From Managing Director & CEO 4
कार्यपालक निदेशक का संदेश / Message from Executive Director 5
संपादकीय / Editorial.....6
आजादी का अमृत महोत्सव: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सफर..... 7
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 10
एक भूला बिसरा सेनानी - के केलाप्पन 12
आजादी के नायक - टंटया मामा भील 13
आजादी का अमृत महोत्सव: दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व 15
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा..... 17
भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष 18
कुशल कोंवर: अकीर्तित नायक 20
सेवानिवृत्ति / पदोन्नति 21
डिजिटल हिन्दी का भविष्य.....22
एक कहानी.....24
परिसर नीति - कुछ विधिक पहलू 26
भारतीय बैंकिंग - दिशा एवं दशा.....28
जंग-ए-आजादी में गोरखपुर की भूमिका.....32
काव्यकुंज 35-36
स्थापना दिवस 37
सतर्कता जागरूकता 38
आउट रिच कार्यक्रम 39
राजभाषा समाचार 40
बैंक के इर्द-गिर्द 41
भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष (75 पदचिन्ह) 42
आजादी के 75 वें वर्ष में राजभाषा हिन्दी - एक पुनरावलोकन 51
भागलपुर के वेदा बाबू 53
स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष - सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता 54
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था.....55
अपने बैंक को जानिए, दिसंबर 2021 59

डिज़ाइन, संपादित तथा प्रकाशित : श्री स्मृति रंजन दाश, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 001 के लिए तथा उनके द्वारा उचीथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड. आइडियल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरादास मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.
Designed, Edited and Published by Shri Smruti Ranjan Dash for Central Bank of India, Chandermukhi, Narimanpoint, Mumbai - 400 001
Designed and Printed by him at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. 65, Ideal Industrial Estate, Mathuradas Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश
Message from Managing Director & CEO

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

आज़ादी या स्वतंत्रता अथवा फ्रीडम अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ वाले शब्द होते हैं. जबकि हमारे जीवन में इन शब्दों की वास्तविकता इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है. हमारा प्रिय भारत देश कई सदियों तक विदेशी शक्तियों के अधीन रहा है. बहुत लम्बे समय तक चले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतत: 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी दासता से मुक्त हो सका. देश की स्वतंत्रता के लिये हजारों भारतीयों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया. जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लें एवं आज़ाद देश की खुली हवा में सांस ले सकें.

विगत स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त 2021 को देश की स्वतंत्रता को 74 वर्ष पूरे हुए हैं तथा 75वां वर्ष प्रारंभ हो गया है. इस क्रम में आगामी 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जायेंगे. इसी उपलक्ष्य में, इस अवधि में पूरे भारत में "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाया जा रहा है.

75 वर्ष की अवधि में भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अत्यधिक प्रगति की है. हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है. इस अवधि में, नियमित रूप से चुनाव हुए हैं. भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें बनी हैं. अलग-अलग दलों की मिली-जुली सरकारें बनी हैं. सरकारें बदली हैं, गिरी हैं. मध्यावधि चुनाव हुए हैं. मंत्री बदले, प्रधानमंत्री बदले. चुनाव के तौर तरीके बदले, ईवीएम आया. और इन सबके साथ-साथ हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होता गया.

इस 75 वर्ष की अवधि में बैंकिंग क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं. इस दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ. बैंकिंग सुविधायें विशिष्ट वर्ग के साथ-साथ सामान्य नागरिकों को मिलने लगी. गांव-गांव में बैंकों की शाखायें खुल गई. कंप्यूटर क्रांति ने बैंकिंग क्षेत्र को पूर्णत: बदला तो सीबीएस ने इसे और सरल बना दिया. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आये. एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, ई - लाबी, जैसी नई सुविधायें आई. डिजिटल बैंकिंग ने कभी भी, कहीं भी सहित 24X7 आधार पर ग्राहक के हाथ में ही बैंक पहुंचा दिया है. प्रधानमंत्री जनधन खातों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंची है.

हमारे बैंक ने भी बैंकिंग क्षेत्र में हुये इन सभी परिवर्तनों को अपनाकर अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक बैंकिंग संबंधी हर सुविधा प्रदान की है. हमने सरकार की सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है. हम समाज के हर वर्ग की सेवा में तत्पर हैं. हर वर्ग के लिये हमारे पास योजनाएं हैं. हमारा शाखा नेटवर्क गांव - गांव तक विस्तारित है. हम सेन्ट्रलाइट साथी "आज़ादी का अमृत महोत्सव" ग्राहकों के प्रति अपनी निष्ठा को और अधिक दृढ़ करते हुये मनायें. अपनी ग्राहक सेवा को सर्वश्रेष्ठ बनायें. जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए की स्थिति से बाहर निकलकर अपनी पुरानी गरिमापूर्ण स्थिति प्राप्त कर सके.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

(एम. वी. राव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रियजनों में बटा हुआ दुख सहने योग्य हो जाता है - कालिदास

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यपालक निदेशक का संदेश
Message from Executive Director

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

इस वर्ष हमारे देश में पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाया जा रहा है. इस अवसर पर हमारे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जा रहे हैं. हमारे प्रिय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई थी. इसकी स्थापना के पीछे भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन की भेदभावपूर्ण नीति ही थी. जिसके परिणामस्वरूप हमारे महान संस्थापक सर सोराबजी एन पोचाखानावाला ने पूर्णत: स्वदेशी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी. इसीलिये हमारा बैंक आज भी भारतीयता की भावना के साथ कार्य करता है. हमारा बैंक भारत के प्रत्येक वर्ग के लिये कार्य करता है. हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं कार्यान्वित करता है.

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि भारतीयों को स्वतंत्रता सहजता से नहीं अपितु दीर्घकालीन संघर्ष के बाद प्राप्त हुई थी. इसके लिये हमारे पूर्वजों द्वारा बहुत कुछ बलिदान किया गया था. प्राणों की आहुतियां दी गई थी. भारत की स्वतंत्रता के लिये अनेक वीर सेनानी हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गये थे. हमें इसका मूल्य समझना चाहिये. हमें इसका महत्व समझना चाहिये. हमें इसका सम्मान करना चाहिये. हमें यह भी समझना चाहिये कि नागरिकों की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत होती है. एकता कमजोर होने से शत्रु इसका लाभ उठाने लगते हैं.

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का अपना संविधान बना. भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, एक संप्रभु राष्ट्र बना. देश ने योजनाबद्ध तरीके से प्रगति की. भारत ने कृषि, वाणिज्य, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, विज्ञान, ऊर्जा, शिक्षा, सामरिक, आर्थिक, संचार, अंतरिक्ष एवं बैंकिंग इत्यादि सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. भारत की अर्थ व्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है. इसके परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है.

"आज़ादी का अमृत महोत्सव" हम भारतीयों के लिये राष्ट्र की असाधारण उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर है. सफलता के नये शिखर छूने के लिये आगे बढने का अवसर है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से देश सेवा का अवसर हमारे पास उपलब्ध है. हम अपने देशवासियों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें. हमारा शाखा नेटवर्क पूरे देश में है जिसमे लगभग दो तिहाई (64%) शाखायें ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं. इस तरह समाज के अंतिम व्यक्ति तक एवं दूरस्थ व्यक्ति तक हमारे बैंक की पहुंच है. हमें बैंक की योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचानी चाहिये जिससे वे उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें. इस तरह नये भारत के निर्माण के लिये हम अपना अधिक से अधिक योगदान प्रदान कर सकते हैं.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संपादकीय
Editorial

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

दीर्घकालीन स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को हमारा देश स्वाधीन हुआ था. इस तरह यह भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष (15.08.2021 से 15.08.2022 तक) चल रहा है. जिसे देशभर में "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के रूप में मनाया जा रहा है. सेन्ट्रलाइट का यह दिसंबर 2021 अंक "आज़ादी का अमृत महोत्सव" विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इससे संबंधित कुछ लेख इस अंक में प्रकाशित किये जा रहे हैं.

जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता अनमोल होती है. श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा लिखा गया है कि "पराधीन सपनेहुं सुख नाही" अर्थात दूसरे के आधीन रहने वाले को सपने में भी सुख नहीं मिलता है. पराधीनता की जंजीरों को तोडने के लिये हमारे पूर्वजों ने विदेशी शासकों के विरुद्ध बहुत लंबी लडाई लडी. अंतत: भारतीयों का दीर्घकालीन स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ. विदेशियों के शासन से मुक्त होकर, भारत स्वतंत्र हुआ. भारत भारतीयों का हुआ. सर्वप्रथम भारत के विद्वानों ने देश का अपना संविधान तैयार किया. जिसके अनुसार, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना. नये भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ. भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसरित हुआ.

स्वतंत्र भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है. भारत, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है. वर्तमान में भारत द्वारा कई कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है. इसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने अत्यधिक प्रगति की है. भारत अपने उपग्रह तो अंतरिक्ष में भेजता ही है, बल्कि अन्य देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर आय भी अर्जित करने लगा है. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों एवं भारतीय कम्पनियों का डंका पूरी दुनिया में सुनाई देता है. ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की प्रगति शानदार मानी जाती है.

"आज़ादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर हमें यह समझना चाहिये कि स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये राष्ट्र की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखना अति आवश्यक है. हर भारतीय का सपना है कि भारत विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो. हम समस्त भारतीय परस्पर एकजुट रहकर ही अपने महान भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सकते हैं और सफलता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित कर सकते हैं.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

स्मृति रंजन दाश

संपादक/महाप्रबंधक (मासंवि/राजभाषा)

समय पर वही सवारी कर सकता है जो समय की लगाम पकडे रहे - अमृता प्रीतम

आजादी का अमृत महोत्सव : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सफर

- के.एन. दूबे
मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा)
आंचलिक कार्यालय, पटना

आजादी के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ 'अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। इसका अर्थ है, आजादी के 75 साल पूरा होने पर उन उपलब्धियों और संकल्पों को आत्मसात करना जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के मोर्चे पर देखा जाये तो हमेशा राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरणा का इतिहास रहा है। सोराबजी पोचखानवाला इस बैंक की स्थापना से इतने गौरवान्वित हुए कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है।पिछले एक सौ से अधिक वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढाव देखे और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। बैंक ने प्रत्येक आशंका को सफलता पूर्वक व्यावसायिक अवसर में बदला और बैंकिंग उद्योग में राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि रखते हुये अपने समकक्षों से उत्कृष्ट रहा।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना स्वदेशी आन्दोलन से प्रभावित होकर सर सोराबजी पोचखानवाला द्वारा 1911 में की गयी थी। इसे पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबन्धन स्थापना के समय भारतीयों के हाथ में था। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया सही अर्थों में स्वदेशी बैंक है जिसके पहले अध्यक्ष फिरोजशाह मेहता थे।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बैंक ने बहुत सारे उतार-चढ़ाव का सामना करते हुये अपने सफर को जारी रखा।कई ऐसे अवसर आए जब बैंक को अंग्रेज़ो के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। तमाम चुनौतियों का सामना कराते हुये 1947 तक बैंक के शाखाओं का विस्तार आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा के शहरों तक हुआ। देश के बटवारे के बाद कई शाखाये पाकिस्तान के अधीन हो गये, काफी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। इसके बावजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आजादी के बाद आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए संकल्पों का अमृत महोत्सव का आगाज कराते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत। नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। इस अमृत महोत्सव का एक और मुख्य उद्देश्य विशेषकर युवाओं को देश के स्वर्णिम इतिहास और आजादी के नायकों की अमर गाथा के बारे में बताना भी है।

इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जाग्रत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परम्पराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल-पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आज़ादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा।

हमारे वेदों का वाक्य है- मृत्यो: मुक्षीय मामृतात्। अर्थात, हम दु:ख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का भी है और इसीलिए, ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव, सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव, वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है।

भारत में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के विकास पर नजर डाला जाये तो स्पष्ट होता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और संस्थापक सर सोराब्जी पोचखानावाला की भूमिका अग्रणी रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और आजादी मिलने के बाद, देश के आर्थिक विकास में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहल सराहनीय रही है। सेंट्रल बैंक ने कई अभिनव और अनुपम बैंकिंग गतिविधियों का शुभारम्भ किया। ऐसी ही कुछ सेवाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

1921-समाज के सभी वर्गों में बचत की आदत डालने के लिए घरेलू बचत सुरक्षित जमा योजना

1924-बैंक की महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करने लिए विशिष्ट महिला विभाग की स्थापना

1926-सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा और रुपया यात्री चेक

1929-निष्पादक एवं न्यासी विभाग की स्थापना

1932-जमाराशि बीमा सुविधा योजना

1962-आवर्ती जमा योजना

राष्ट्रीयकरण के बाद की योजनाएँ

वर्ष 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी सेंट्रल बैंक ने विभिन्न अभिनव बैंकिंग सेवाएँ आरम्भ कीं जिनमें प्रमुख हैं:

1976-मर्चेंट बैंकिंग कक्ष की स्थापना

1980-बैंक के क्रेडिट कार्ड सेंट्रल -कार्ड का शुभारम्भ

1986-प्लैटिनम जुबली मनी बैंक जमा योजना

1989-आवासीय सहायक कम्पनी सेण्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड का शुभारम्भ

1994-बाहरी चेकों की शीघ्र वसूली के लिए त्वरित चेक वसूली सेवा (क्यू.सी.सी.) तथा तत्काल सेवा आरम्भ की

अन्य क्षेत्रों में योगदान

इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कृषि तथा लघु उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ मध्यम एवं बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सेंट्रल बैंक लगातार सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। शिक्षित युवाओं में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने कई स्वरोजगार योजनाएँ भी आरम्भ की हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेंट्रल बैंक को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है क्योंकि देश भर में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थित अपनी 4500 से अधिक शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेंट्रल बैंक का एक अपना विशिष्ट स्थान है।

सेंट्रल बैंक की विस्तृत सेवाओं के प्रति ग्राहकों के विश्वास का अनुमान आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., यू.टी.आई., एफ.आई.सी., एच.डी.एफ.सी. जैसे कार्पोरेट गाहकों की सूची और देश के प्रमुख कार्पोरेट घरानों से भी लगाया जा सकता है जो बैंक के प्रमुख ग्राहकों में हैं।

1923 में, इसने एलायंस बैंक ऑफ शिमला की विफलता के मद्देनजर टाटा इंडस्ट्रियल बैंक का अधिग्रहण किया। 1917 में स्थापित टाटा बैंक ने 1920 में मद्रास में एक शाखा खोली जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मद्रास बन गई।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भारतीय एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1936 में लंदन में खुला। हालांकि, बार्कलेज बैंक ने 1938 में सेंट्रल एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण किया।

इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रंगून में शाखा की स्थापना की। 1963 में, बर्मा की क्रांतिकारी सरकार ने वहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संचालन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1969 में, भारत सरकार ने 19 जुलाई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका जग-जाहिर है। सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी शाखाओं का विस्तार कर आम जन-मानस तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई गई।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मास्टरकार्ड के सहयोग से वर्ष 1980 में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले भारत के पहले बैंकों में से एक था।

अपने 108वें स्थापना दिवस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रोबोटिक बैंकिंग की दिशा में अपना पहला कदम, मेधा नामक रोबोट लॉन्च किया।

कोई भी संस्था लंबे समय तक तब जीवित रहती है जब वह समय के अनुसार अपने आदर्श, उद्देश्य, संकल्प और देश तथा जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में परिवर्तन करती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने

हमेशा समय के साथ अपने को परिवर्तित किया जिसकी झलक उसके लोगो से ही मिल जाती है जो सफलता के सोपान को परिलक्षित करता है। लोगो किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है। उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के के परिप्रेक्ष में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है।

1911 - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह लोगो विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है।

1956 - बैंक की पहचान दर्शाने वाले आध्याक्षरों को चित्रित करने के लिये लोगो को संशोधित किया गया

1973 - लोगो को नया बनाया गया जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामयिक छवि प्रस्तुत की जा सके।

1982 - लोगो में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उदद्योग, एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर सम्बन्धों को उजागर कराते हुये बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है।

बैंक के वर्तमान लोगो में सशक्त राष्ट्र की संकल्पना अंतर्निहित है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य यह भी है कि अगले 25 वर्षों में अपने देश को आर्थिक, सामरिक, औद्ध्योगिक एवं सभी

क्षेत्रों में इतना सशक्त बनाना है कि जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाये तो भारत दुनिया के सबसे विकसित अग्रणी राष्ट्र की भूमिका में दिखे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट विजन,मिशन एवं सैद्धांतिक कथन को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि सर सोराजबी पोचखानावाला ने 1937 जो बातें कही थी कि सेंट्रल बैंक राष्ट्र की संपति है सेंट्रल बैंक आम जनता का बैंक है, वह आज आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भी प्रासंगिक है। इस कॉर्पोरेट विजन,मिशन

एवं सैद्धांतिक कथन पर अमल करते हुये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने में आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

कॉर्पोरेट विजन : सबकी बैंकिंग एवं वित्तीय जरूरतों का केंद्र बिन्दु बनना

कॉर्पोरेट मिशन : प्रभावी मानव संसाधन एवं प्रौधोगिकी के माध्यम से ग्राहक केन्द्रित उत्पाद एवं सेवायें उपलब्ध कराना

सैद्धांतिक कथन :

C - Consistency	: निरंतरता
E – Ethical Standards	: नैतिक मानक
N – Nurturing Potential	: संभाव्य क्षमताओं का पोषण
T – Transparency	: पारदर्शिता
R – Responsiveness	: अनुकूल प्रतिक्रिया
A – Accountability	: जवाबदेही
L – Loyalty	: निष्ठा

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सैद्धान्तिक मूल्यों के साथ देश के हरेक नागरिक के विकास को ध्यान में रखते हुये राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है.

आजादी का अमृत महोत्सव अपने उन पूर्वजों को याद करने का महोत्सव है जिन्होने राष्ट्र के लिये अपने जीवन को न्योच्छावर कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक सर सोराब्जी पोचखानावाला

वैसे राष्ट्र निर्माता थे जिन्होने आर्थिक मोर्चे पर विशाल ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दिया था। बैंक स्थापना के शताब्दी वर्ष में भारत सरकार द्वारा सर सोराब्जी पोचखानावाला के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। हम नमन करते है उन सभी को जिन्होने बैंक को कुशल नेतृत्व प्रदान कर बैंक को राष्ट्र की सेवा के लिये आगे बढ़ाया।

बैंक के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यकाल

फिरोजशाह मेहता	1912 - 1915	बी.वी.सोनालकर	1981 - 1985
ए.जे.बिलिमोरिया	1915 - 1921	एम.एन.गोईपोरिया	1986 - 1990
फिरोज सी.सेठना	1921 - 1937	एन.एम.मिस्त्री	1990 - 1991
एच.पी.मोदी	1938 - 1940 1942 - 1948 1952 - 1966	एस.सुब्रहमण्यम	1992 - 1993
हरिदास माधवदास	1941	एस.दोरेस्वामी	1993 - 1997
दिनशॉ डी.रोमर	1949 - 1951	के.सी.चौधरी	1997 - 2000
वी.सी.पटेल	1967 - 1968	डॉ. दलबीर सिंह	2000 - 2005
बी.एन.राव	1969	एच.ए.दारूवाला	2005 - 2009
बी.एन.अडारकर	1970 - 1974	एस.श्रीधर	2009 - 2011
डी.बी.तनेजा	1974 - 1975	मोहन बी.टांकसाले	2011 - 2013
पी.एफ.गटा	1975 - 1980	राजीव ऋषी	2013 - 2018
		पल्लव महापात्रा	2018 - 2021
		एम.वी.राव	20121-

देश के आर्थिक विकास में वर्ष 1911 से पूरी निष्ठा के साथ, देश के हरेक नागरिक के लिए प्रतिबद्ध सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान का साक्षी रहा है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के सपने को साकार करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दृढ़ संकल्पित है।

स्वच्छता अभियान

आज़ादी का अमृत महोत्सव

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

- सुश्री वृषाली एस. देवरे,
राजभाषा अधिकारी,
पुणे, सोलापुर, अहमदनगर क्षेत्र

भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। जबकि बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी से पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। भारत को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने में बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। आज 165वीं बाल गंगाधर तिलक जयंती 2021 के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम उनके सर्वोच्च साहस, बलिदान, निस्वार्थता और स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक के रूप में सामने आता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्कूली पढ़ाई और स्नातक करने के बाद, अपना पूरा समय सामाजिक सेवा और राजनीतिक समस्याओं को दूर करने में लगा दिया। वह अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहते थे और उन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षा के प्रसार के लिए एक समाज की शुरुआत की। लेकिन उनका बेचैन मन एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सका। उन्होंने जल्द ही पत्रकारिता में कदम रखा और एक मराठी अखबार 'केसरी' शुरू किया। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार के लिए जोश के साथ लिखा।

छुआछूत की समस्या पर उन्होंने लिखा कि मैं भगवान को भी नहीं पहचान पाऊंगा यदि उन्होंने कहा कि छुआछूत उनके द्वारा बनाया गया कोई नियम है। सामाजिक सुधारों की वकालत करते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान राजनीतिक समस्या - ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति की ओर दिलाया। उन्होंने केसरी में लेख लिखना शुरू किया, जिसमें प्रत्येक भारतीय के स्वतंत्र होने के जन्म के अधिकार पर जोर दिया गया। 'स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' यह उन दिनों प्रचारित किया जाने वाला एक क्रांतिकारी सिद्धांत था। इसने उन्हें साम्राज्य के साथ संघर्ष में ला दिया और उन्हें 1897 में राजद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास उनके लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ और बाद में लोकमान्य तिलक एक प्रांतीय नेता से राष्ट्रीय नेता बन गए। 1889 में (जिस वर्ष जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था), तिलक ने सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लिया। तिलक तब 33 वर्ष के थे। दो अन्य युवा कांग्रेसी, जो उनके समकालीन बनने वाले थे, भी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए - लाला लाजपत राय 34 वर्ष और गोपाल कृष्ण गोखले 33 वर्ष के थे। 1885 में कांग्रेस में नरमपंथियों का वर्चस्व था, जो न्याय और निष्पक्षता की ब्रिटिश भावना में विश्वास रखते थे और आंदोलन के संवैधानिक और वैध तरीकों में विश्वास करते थे। हालांकि बाद में लॉर्ड कर्जन के बंगाल राज्य के विभाजन के निर्णय के साथ यह बदल गया। भारत के युवा उग्रवादी राजनीति और सीधी कार्रवाई की ओर बढ़े। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ, तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ मोहभंग के अवसर को जब्त कर लिया और नरमपंथियों की 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' की निंदा की। अरबिंदो घोष के साथ बाल-पाल-लाल की तिकड़ी 'चरमपंथा' के रूप में लोकप्रिय हो गई, हालांकि वे खुद को 'राष्ट्रवादी' कहना पसंद करते थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू याद करते हैं, 'राष्ट्रीय कांग्रेस के आने के साथ, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, एक नए प्रकार का नेतृत्व प्रकट हुआ, छात्रों और युवाओं के रूप में अधिक आक्रमक और उदंड और निम्न मध्यम वर्गों की बहुत बड़ी संख्या का भी प्रतिनिधित्व करता था। बंगाल के विभाजन के खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन ने इस प्रकार के कई सक्षम और आक्रमक नेताओं को वहां खड़ा कर दिया था, लेकिन नए युग का असली प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व का प्रतिनिधित्व एक मराठा, एक बहुत ही सक्षम और एक युवा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया था। क्रांतिकारी नारे हवा में थे, गुस्सा बहुत तेज था और संघर्ष अपरिहार्य था। इससे बचने के लिए, कांग्रेस के पुराने पितामह दादाभाई नौरोजी, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से सम्मानित और देश के पिता के रूप में माना जाता था, को उनकी सेवानिवृत्ति से बाहर कर दिया गया था। राहत संक्षिप्त थी और 1907 में संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से पुराने उदारवादी वर्ग की जीत हुई। (लेकिन) इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में राजनीतिक विचारधारा वाले अधिकांश लोगों ने तिलक और उनके समूह का समर्थन किया। 24 जून, 1903 को, बॉम्बे में तिलक पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। राजद्रोह के आरोप में तिलक का ऐतिहासिक मुकदमा 13 जुलाई को शुरू हुआ। उन्हें दोषी ठहराया गया और मंडाले, बर्मा भेज दिया गया, जहां उन्हें अपने जीवन के अगले 11 साल बिताने थे। फैसला सुनाने पर तिलक ने निडरता से कहा:' मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जूरी के फैसले के बावजूद, मैं इस बात पर कायम हूं कि मैं निर्दोष हूं। ऐसी उच्च शक्तियाँ हैं जो चीजों की नियति को नियंत्रित करती हैं और यह भविष्य की इच्छा हो सकती है कि जिस कारण का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह मेरे मुक्त रहने की तुलना में मेरे दुख से अधिक समृद्ध हो। मंडाले में, तिलक ने जल्द ही खुद को लिखने और सोचने की दिनचर्या में स्थापित कर लिया। कर्मयोगी ने स्वयं को पढ़ने में, नई चीजों को सीखने में और गीता के सच्चे संदेश पर चिंतन करने में लीन कर लिया। इस निरंतर पठन और चिंतन का सबसे फलदायी परिणाम गीता रहस्य था। 8 जून 1914 को तिलक को सूचित किया गया कि उनका वनवास समाप्त हो गया है। वह तब 58 वर्ष के थे, और

उनका स्वास्थ्य टूट गया था, लेकिन उनकी आत्मा झुकी हुई थी। भारत लौटने पर, उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। तिलक के जीवनी लेखक डी वी ताम्हनकर के अनुसार, वर्ष 1916 तिलक के करियर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। वर्ष के प्रारंभिक भाग में होमरूल लीग की नींव, इसकी अभूतपूर्व सफलता, तिलक के 61वें जन्मदिन पर सार्वजनिक पर्स की प्रस्तुति, और लखनऊ कांग्रेस के अंतिम राजद्रोह में उनकी कानूनी जीत देखी गई, जो न केवल देश के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। तिलक का जीवन, लेकिन शायद, कांग्रेस के इतिहास का भी। तिलक, जो पहले राजनीति में अकर्मण्यता के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे, अब एक रचनात्मक और सुलह करने वाले राजनेता की भूमिका में दिखाई देते हैं। उग्र भाषणों और निंदा के दिन समाप्त हो गए हैं; समझौता और उत्तरदायी सहयोग का एक नया चरण शुरू होता है। उन्हें लखनऊ कांग्रेस में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में देखा जाता है जो भारत के राजनीतिक विकास में एक निश्चित चरण का प्रतीक है। तिलक की प्रेरणा से स्वराज की संयुक्त मांग उठी, पहला अवसर जब मुस्लिम और हिंदू, नरमपंथी और उग्रवादी, पारसी और अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण सुधारों की मांग के लिए एक स्वर में बात की। तिलक हिंदू-मुस्लिम एकता के मसीहा बनकर उभरे। इंडियन होम रूल लीग का गठन तिलक के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को ठोस आकार देने के लिए 35 वर्षों तक काम किया था, जो बड़े पैमाने पर अपने स्वयं के प्रयासों और कष्टों से प्रेरित और बनाए रखा था, और उनके श्रम ने आखिरकार फल दिया। देश अब खुलकर बोल सकता था और बिना किसी डर के अपने जन्मसिद्ध अधिकार की मांग कर सकता था। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे; उनकी आकांक्षाओं ने एक निश्चित आकार ले लिया था, और उन्होंने महसूस किया कि एक विदेशी नौकरशाही को संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अब समय निश्चित रूप से आ गया था, तिलक ने कहा, देश के मामलों पर नियंत्रण की मांग करना। लेकिन अगर स्वराज की मांग को प्रभावी होना है, तो इसे एक शक्तिशाली और संगठित निकाय के माध्यम से किया जाना चाहिए। होमरूल लीग को वह निकाय होना था। इसकी स्थापना 28 अप्रैल, 1916 को पुणे में मुख्यालय के साथ हुई थी। इसी तरह की होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेझण्ट (जो अगले वर्ष आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी) ने मद्रास में अपने मुख्यालय के साथ की थी। दोनों होमरूल लीग एक दूसरे के पूरक थे। होम रूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी।

नेहरू ने 28 जुलाई, 1956 को संसद में लोकमान्य तिलक के चित्र का अनावरण करते हुए, तिलक को अपनी शानदार श्रद्धांजलि का समापन किया। उन्होंने कहा कि तिलक के निकट संपर्क में आना मेरा सौभाग्य था। जब वह अपने करियर की ऊंचाई पर थे, मैं दूर देश में था, तब भी एक छात्र था। लेकिन वहां भी उनकी आवाज और उनकी कहानी हम तक पहुंची और हमारी कल्पना को हवा दी। हम जल्दी ही उस प्रभाव में पले-बढ़े और इसके द्वारा ढाले गए। एक मायने में, उस समय के युवाओं के लिए भारत वही था जो तिलक ने प्रस्तुत किया था, जो उन्होंने कहा था और जो उन्होंने लिखा था, और सबसे बढ़कर, उन्होंने जो झेला था। यही वह विरासत थी जिसके साथ गांधीजी को अपने विशाल आंदोलनों की शुरुआत करनी पड़ी थी। यदि लोकमान्य द्वारा भारतीय लोगों और भारत की कल्पना और भारत के युवाओं को ढाला नहीं गया होता, तो अगला कदम उठाना आसान नहीं होता। इस प्रकार, इस ऐतिहासिक चित्रमाला में, हम एक के बाद एक महान व्यक्ति को भाग्य और इतिहास के ऐसे कार्य करते हुए देख सकते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि का कारण बने हैं। हम यहां न केवल भारत की क्रांति के जनक, इस महान व्यक्ति की तस्वीर का अनावरण करने के लिए मिलते हैं, बल्कि उन्हें याद करने और उनसे प्रेरित होने के लिए भी मिलते हैं। तिलक अपनी पीढ़ी के उन नेताओं में सबसे बड़े थे जिन्होंने गांधीवादी युग के परीक्षणों और विजयों के लिए राष्ट्र को तैयार किया। गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक दिन पहले 1 अगस्त 1920 को, तिलक का निधन हो गया, इस प्रकार एक के अंत और दूसरे युग की शुरुआत हुई, जो उनके स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने में परिणत हुआ।

दि.11.10.2021 को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एल. बी. झा श्री एस.एन. पाण्डेय, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष, गीता प्रेस, गोरखपुर से वार्ता करते हुए

एक भूला बिसरा सेनानी- के केलाप्पन

- सोनम चन्द्रदास
प्रबंधक- मासंवि
क्षेका - तिरुवनन्तपुरम

हमारे देश भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतना विशाल था कि कई सेनानी ऐसे भी थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। ऐसे ही व्यक्ति हमारे केरल के के.केलप्पन थे, जिन्हें केरल प्रदेश में 'केरल गांधी' के नाम से जाना जाता है .

श्री केलप्पन का जन्म सन् 1889 में मुचूकन्नू नामक ग्राम में हुआ।

के. केलप्पन, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतन्त्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। ये महात्मा गाँधी से बहुत प्रभावित थे। जब गाँधी जी ने 'असहयोग आन्दोलन' प्रारम्भ किया तो के. केलप्पन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आन्दोलन में कूद पड़े। वर्ष 1930 में 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' के समय गाँधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही नामजद किया था। आज़ादी के बाद जब जे. बी. कृपलानी ने 'किसान मज़दूर प्रजा पार्टी' बनाई, तब के. केलप्पन पार्टी में सम्मिलित हो गए और फिर बाद में लोकसभा के सदस्य चुने गए।

उनकी प्राथमिक पढ़ाई कालिकट में हुई और उन्होंने स्नातक मद्रास विश्वविद्यालय से हासिल किया। उन्होंने शिक्षक की नौकरी चेंगनाशेरी के पाठशाला में किया। के. केलप्पन जब मुम्बई विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, इसी समय महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया। केलप्पन ने भी विश्वविद्यालय छोड़ दिया और आन्दोलन में योगदान देने के लिए उसमें सम्मिलित हो गए। इसके बाद उनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा में ही बीता।बाद के दिनों में के. केलप्पन मुम्बई से मालाबार चले गए। उस समय 'असहयोग आन्दोलन' और ख़िलाफ़त आन्दोलन' बड़े जोर-शोर से साथ-साथ चल रहे थे। के. केलप्पन केरल के पहले व्यक्ति थे जिसे आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ़्तार किया गया था। इसके बाद 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान के. केलप्पन गिरफ़्तार किये गए और तीन वर्ष तक जेल में बंद रहे।

के. केलप्पन, समाज सुधार और छूआछूत निवारण के क्षेत्र में भी अग्रणी व्यक्ति थे। मंदिर प्रवेश के 'वायकोम सत्याग्रह' में उनके ऊपर पुलिस की मार भी पड़ी। गुरुवायुर के प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी, इसके लिए उन्होंने 10 महीने तक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अन्त में भूख हड़ताल पर बैठे गए। महात्मा गाँधी के कहने पर के. कलप्पन ने भूख हड़ताल तोड़ दी। इसके बाद ही मद्रास की सरकार ने मंदिर प्रवेश का क़ानून बना दिया। वे अपने जीवन काल में सारे लोगों में समानता लाने के महत्व पर जोर देते रहे। वाइखम सत्याग्रह आंदोलन में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। इसी आंदोलन ने आगे चलकर सन् 1932 में गुरुवायूर सत्याग्रह आंदोलन का रूप लिया। गांधी जी के आदेशों का बड़ा आदर करते थे। उनका मानना था कि इंसान जाति धर्म आदि से परे हैं और सभी समान है। उन्होंने गांधीजी की आस्था एवं विचारधारा की खूब प्रचार किया और केरल में गांधीवादी सोच को सभी की आत्मा में बसाने का प्रयत्न किया। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने राजनीति से नाता तोड़कर सर्वोदय वर्कर बनने का निर्णय लिया केरल में भूदान आंदोलन में उनका मुख्य योगदान रहा है।

केलाप्पन जी ने 'मातृभूमि' अखबार का आरंभ करने में बहुत सहायता किया और वह कई वर्षों तक इस अखबार के संपादक भी रहे हैं। हमारे देश के लिए के केलपेपन जी ने जो योगदान दिया है वह सराहनीय है वे सन् 1971 में 82 वर्ष की आयु में हमें अलविदा कह गए। स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम भले ही कहीं खो सा गया है लेकिन आज भी केरल वासियों के दिलों में उनका नाम एवं अपने राज्य के प्रति दिया गया योगदान बसा हुआ है। उनके सम्मान में भारतीय पोस्ट में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यदि कभी किसी चिट्ठियां लिफाफे में उनका नाम लिखे तो हमें उनका योगदान को याद करके गर्व महसूस करना चाहिए।

सत्य को सूचक ही नहीं, प्रेरक भी होना चाहिए - रविन्द्रनाथ टैगोर

आज़ादी के नायक - टंट्या मामा भील

आज़ादी का अमृत महोत्सव

- प्रवीण ठाकुर
वरिष्ठ प्रबंधक
अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय

मध्यप्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में पातालपानी नामक एक रमणीक पर्यटन स्थल है. यह स्थान एक पहाड़ी पर स्थित है. एक जगह से एक साथ बहने वाली झरने की कई धराएं इस स्थान का मुख्य आकर्षण है. यहां के झरने देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं. यह स्थान इंदौर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. छुट्टी के दिनों में यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है जो यहां आकर प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद लेते हैं. इस स्थल के निकट से ही एक रेल की पटरी है जिस पर दिनभर में कई ट्रेन जुगरती हैं.

बचपन में एक दिन मैं अपने परिवार के साथ यहां आया था. हम लोग यहां सुबह जल्दी आ गए थे. दोपहर तक मैं वहां अपने परिवार के साथ खेलता रहा और जब थक गया तो मुझे हमारी बिछाई गयी चटाई पर बैठा दिया गया और समान की सुरक्षा की जिम्मेदारी का काम मुझे सौप दिया गया. बैठे-बैठे मैं वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को देखने लगा. वहां मुझे एक बात बहुत अजीब लगी की हर ट्रेन यहां रुकती और सिटी बजाती थी और फिर आगे चल पड़ती थी. पहले मुझे यह कुछ तकनीकी समस्या लगी. बाद में गौर किया कि यह प्रत्येक ट्रेन द्वारा किया जा रहा है. मेरी समस्या को पास मे बैठे एक बुढ़े दादा ने समझ लिया, वो भी शायद मेरी ही तरह थक कर अपने समान की सुरक्षा कर रहे थे. उन्होने मुस्कुरा कर कहा की यह ट्रेन टंट्या मामा के मंदिर के सामने रुक कर उन्हें सलामी दे रही. मेरे बाल मन ने ज़ोर से कहा- क्या ! यह कैसे हो सकता है, कोई ट्रेन किसी को सलामी देती है क्या? उन्होंने आगे बताया की टंट्या मामा स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे और निमाड़ क्षेत्र से आते थे, और इतना ही नहीं लोग उनकी तुलना रॉबिन हुड से करते थे. रॉबिन हुड तो मेरे शुरु से ही हीरो थे. यह यह सुनकर मेरा बाल मन और भी खिल उठा और मैंने यह निश्चय किया की इंदौर की लाइब्रेरी में जाकर उनके बारे और जानकारी प्राप्त करूंगा.

टंट्या जी को एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है. सन् 1857 के करीब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था. टंट्या जी क्रांतिकारी के रूप में सन् 1878 से 1889 के दौरान 12 वर्षों तक सक्रिय रहे. इस बीच उन्होंने कई जनसभा करके आदिवासी लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे आत्याचारों के बारे मे बताया और अपने उनके अत्याचारों को अपने आंदोलन से जोड़ा. अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ने के लिए वह अंग्रेज़ों के खज़ानों को लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे. इस कारण वहां के लोग उनकी तुलना रॉबिन हुड से करने लगे. आदिवासी समुदाय के लिए वह बहुत ही कम समय में वो एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आए. आदिवासी लोग प्यार से उन्हें मामा के नाम से पुकारने लगे.

टंट्या जी गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे. 12 वर्षों तक उन्होंने पुलिस को बहुत छकाया और कई बार जेल तोड़ कर भाग गए. ऐसा कहा जाता है कि पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत नामुमकिन सा लगने लगा था. वह अपना अधिकांश समय जंगलों और जंगलों में रास्ता बनाते हुए लंबी दूरियां तय करने में ही जाता था. कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि टंट्या मामा की ख्याति इतनी फैली कि वो महान क्रांतिकारी तात्यां टोपे की नज़र में आ गए और उन्होंने टंट्या मामा को प्रशिक्षित किया.

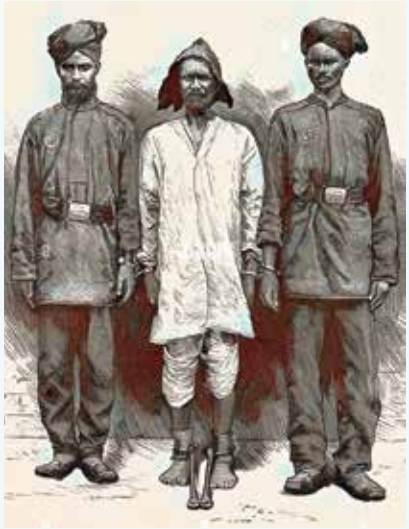

टंट्या जी का जन्म खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बडादा गांव में सन् 1840 में हुआ. उनके पिताजी का नाम श्री भाऊ सिंह था. बचपन में बहुत दुबले पतले होने के कारण लोग इन्हें टंटा कहते

थे. आदिवासी क्षेत्र में पैदा होने के कारण उन्हे युद्ध कला - जैसे तीर कमान, गोफन और लाठी आदि में महारथ हासिल थी. उनके पिता जी एक सच्चे देश भक्त थे. उन्होंने बालक टंट्या के मन में देश भक्ति की भावना बचपन से ही जगा दी थी. उन्होंने अंग्रेज़ों के चापलूस साहूकारों का आत्याचार बचपन से ही देखा था. भील समुदाय के प्रति पक्षपात और उनकी गरीबी उन्हें बहुत तकलीफ देती थी. टंट्या जी की तकलीफ़ें और भी बढ गयी जब उनके माता-पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया.

उनका क्रांतिकारी सफर तब शुरू हुआ जब उनकी जमीन वहां के साहूकार ने हड़प ली. टंट्या जी ने उस साहूकार पर कोर्ट केस किया. झूठी गवाही के कारण कोर्ट ने केस खारिज कर दिया. टंट्या जी ने गुस्से में आकर साहूकार के लोगों की पिटाई कर दी जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुना दी. जेल में आदिवासी लोगों पर अंग्रेज़ो के अत्याचार देखकर उनके मन बहुत द्रवित हो उठा. जेल से छूटने के बाद टंट्या जी पोखर में जाकर मजदूरी करने लगे पर वहां भी साहूकारों ने उन्हे चैन से नहीं रहने दिया. जहां कहीं भी चोरी या मारामारी की घटना होती वहां साहूकार उनका नाम लगा देते. पुलिस उन्हें पकड़ कर बार-बार जेल में डाल देती थी. तब टंट्या जी हीरापुर चले गए वहां उन्हे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. टंट्या भील और उनके एक साथी ने तलवार से सिपाहियों को घायल कर दिया. इस आरोप मे उन्हें तीन माह की जेल हुई. टंटया जी ने इसके बाद खरगोन जिले के झिरनिया गांव में अपना डेरा डाला. मुसीबतों ने उनका साथ वहां भी नहीं छोड़ा. उन पर वहां एक बार फिर चोरी का आरोप लगाया गया. इसी बात से परेशान होकर उन्होने तय किया कि अब वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेज़ सरकार और उनके चापलूस साहूकार, जो गरीबों को लूट कर अंग्रेज़ों का खजाना भर रहे हैं वे उनको चैन की नींद नहीं लेने देंगे.

पुलिस के हाथों में न आकर टंट्या मामा ने आपने साथियों को एकत्रित किया और अपना एक दल बनाया. वह लोगों की बीच जाते और अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को चेताते और अपने दल में शामिल होने कहते. मामा की ख्याति और लोगों में उनके प्रति विश्वास इस बात से पता चलता है कि वह अपनी जनसभा में आपसी मतभेद के मामले भी सुलझाते और लोग उनकी बातों को स्वीकार भी करते थे. आंदोलन को और उग्र रूप देने और अपने आदिवासी लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उन्होंने अग्रेंजी खज़ानों पर डाका डालना शुरु कर दिया. वह लोगों के हर सुख - दुख में साथ देते थे. गरीब लोगों की मदद करते. अपने जीवन काल में टंट्या मामा ने 400 डाके डाले. आमने-सामने की लड़ाई में अग्रेंज़ कभी भी टंट्या मामा को पकड़ नहीं पाये. अंग्रेज़ों ने टंट्या मामा को पकड़ने के लिए इनाम की भी घोसणा की थी.

टंटया मामा की प्रसिद्धि से साहूकार जलने लगे. उनकी उपलब्धियों के कारण उनके कई दुश्मन भी बन गए. ऐसा बताया जाता है कि उनकी मुंहबोली बहन के पति ने रक्षा बंधन पर उन्हें राखी बँधवाने और भोजन के लिए आमंत्रित किया और टंट्या मामा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर किया. दिनांक 11 अगस्त 1889 के दिन वे अपने कुछ लोगों के साथ अपनी मुंहबोली बहन के घर गए. उनके जीजा ने उन्हें और उनके साथियों को हथियार अलग रखने को कहा. जैसे की मामा ने अपने हथियार अलग रखे वहां पुलिस का दल आ गया और मामा को जंजीर में जकड़ लिया. टंट्या मामा को गिरफ्तार करके उन्हे इंदौर भेज दिया गया. उसके बाद उन्हें जबलपुर जेल में भेजा गया. टंट्या मामा ली लोकप्रियता के कारण लोग उनकी एक झलक़ पाने के लिए सड़कों पर खड़े हो गए. जबलपुर हाई कोर्ट में टंट्या मामा पर मुकदमा दायर किया गया. सेशन कोर्ट ने मामा को 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई. टंट्या मामा की लोकप्रियता के चलते लोग उनकी सजा के खिलाफ सड़क पर आ गए और बड़ी संख्या लोग जबलपुर पहुंचने लगे. अंग्रेंज़ सरकार ने आदिवासियों के आंदोलन के डर से टंट्या मामा को गोली मारकर उनके शव को पाताल पानी के जंगलों मे फेक दिया.

जिस जगह पर टंट्या मामा के शव को फेंका गया था आज भी उस जगह को टंट्या मामा की समाधि माना जाता है. इस जगह पर मामा को सम्मान देने के लिए प्रत्येक ट्रेन रुक कर सलामी देती है. आदिवासी समुदाय ने पातालपानी के निकट कालाकुंड नाम के गांव में टंट्या मामा का एक मंदिर भी बनाया है और वहां के लोग उनकी पूजा करते हैं.

टंटया मामा को पकड़ने की कवरेज को प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने 10 नवम्बर 1889 को प्रमुखता से प्रकाशित किया था जिसमें उन्हें रॉबिन हुड का नाम दिया गया था.

टंटया मामा का चिंतन अंग्रेज़ों के चाटुकार साहूकारों द्वारा सताये हुये लोगों की सुरक्षा के प्रति था. उन्होंने अग्रेंजी सरकार के शोषण का दमन करने हर संभव प्रयास किया. टंट्या मामा गरीब और कमजोर लोगों का सहारा बनकर उभरे. उन्होंने हजारों लोगों पर अपनी छाप छोड़ी और लोगों को आजादी की क्रांति के लिए प्रेरित किया. ऐसे वीर और क्रांतिकारी टंट्या मामा भील को शत शत नमन.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

- स्मिता कुमारी
संकाय सदस्य
सी.एल.डी. पटना

आजादी का अमृत महोत्सव: दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व

आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में भी प्रगतिशील है।

"आज़ादी का अमृत महोत्सव" की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह पहले शुरू की गयी और 15 अगस्त, 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। 2021 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने के पर आजादी के अमृत महोत्सव को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरुआत दिवस को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 'आजादी का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन किया था।

दांडी मार्च की तर्ज पर इस कार्यक्रम की शुरुआत फ्रीडम मार्च नामक पदयात्रा से की गयी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी के नवसारी तक जाएगी। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी सहित 80 स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था, इसी बात को ध्यान में रखकर इस फ्रीडम मार्च में भी 80 पदयात्रियों को शामिल किया गया है। 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल, 2021 को समाप्त होगी। दांडी के रास्ते में विभिन्न समूहों के लोग पदयात्रा में शामिल होंगे।

यात्रा में शामिल लोग महात्मा गांधी के दांडी मार्च में शामिल उन 80 अनुयायियों की याद में दो अतिरिक्त मार्गों के साथ उसी मार्ग (अहमदाबाद से दांडी) से गुज़रेंगे जिस मार्ग पर वर्ष 1930 की दांडी यात्रा निकाली गई थी। वर्ष 1930 के दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों के वंशजों को सम्मानित किया जाएगा।

वर्ष 1930 के दांडी मार्च के बारे में:

दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। 1930 में अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाला नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था। नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ-साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है इसलिए इस कर को हटाने के लिए गांधीजी ने यह सत्याग्रह चलाया था। महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा, इसलिए वह आंदोलन जन-जन का आंदोलन बन गया था। इसलिए आज ही के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके और भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिले।

- दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
- इसे 12 मार्च, 1930 से 6 अप्रैल, 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया।
- गांधीजी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर तक 80 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की गई, इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करना था।
- दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बंबई और कराची जैसे तटीय शहरों में नमक बनाने हेतु भीड़ का नेतृत्व किया गया।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया, जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000

से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मई को गांधीजी के गिरफ्तार होने के बाद भी यह सत्याग्रह जारी रहा।

- कवयित्री सरोजिनी नायडू द्वारा 21 मई को बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसना नामक स्थल पर 2,500 लोगों का नेतृत्व किया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न कर दिया।
- गांधीजी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज़ सम्मेलन (Round Table Conferences) में शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति दी गई।
- गांधीजी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बैठक निराशाजनक रही, लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने गांधीजी को एक ऐसी ताकत के रूप में स्वीकार किया जिसे वे न तो दबा सकते थे और न ही अनदेखा कर सकते थे। गांधीजी ने भारत के वायसराय (वर्ष 1926-31) लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनके न्यूनतम मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो उनके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।

आंदोलन का प्रभाव:

- सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग रूपों में शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष ज़ोर दिया गया।
- पूर्वी भारत में चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नो-टैक्स अभियान (No-Tax Campaign) बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।
- जे.एन. सेनगुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को खुलेआम पढ़कर सरकारी कानूनों की अवहेलना की।
- महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की गई।
- यह आंदोलन अवध, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांतों में आग की तरह फैल गया।

महत्त्व:

- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटेन का आयात काफी गिर गया। उदाहरण के लिये ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया।
- यह आंदोलन पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों तथा दुकानदारों जैसे शहरी तत्त्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। अत: अब कॉन्ग्रेस को अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्राप्त हो गया।
- इस आंदोलन को कस्बे और देहात दोनों में गरीबों तथा अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ, वह उल्लेखनीय था।
- इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी उनके लिये वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था।
- यद्यपि कॉन्ग्रेस ने वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में महत्त्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया।

दि. 26.10.2021 को श्रीमती नमिता रॉय शर्मा, महाप्रबंधक (रिटेल एवं कंज्यूमर लेंडिंग), केंद्रीय कार्यालय मुम्बई की विशिष्ट आतिथ्य में क्रेडिट आऊटरीच कार्यक्रम में स्वागत करते हुए श्री एल.बी. झा, क्षेत्रीय प्रबंधक. साथ में श्री देवी दयाल वर्मा, अपर जिला अधिकारी, कुशीनगर, श्री आर.एन. यादव, निदेशक, आर.सेट्टी, कुशिनगर, जिला अग्रणी प्रबंधक श्री सुनील त्यागी.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा

- विजय भूषण सिन्हा
वरिष्ठ प्रबंधक - राजभाषा
क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतभूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया. उनमें से एक झारखंड के गौरव विरसा मुडा का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के नायकों में अग्रिम पंक्ति में सुमार है. कहते हैं एक छोटी सी आवाज को नारा बनने में देर नहीं लगती बस दम उस आवाज को उठाने वाले में होनी चाहिये और इसकी जीती जागती मिसाल हैं विरसा मुंडा. भारतीय इतिहास में विरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दिशा और दशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया. उन्होंने अंग्रेजों के काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाल दिया. विरसा मुंडा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और झारखंड के समाजिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई. अपने इन्ही कार्यो और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं.

विरसा ने मुंडा विद्रोह पारंपरिक भू-व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था में बदलने के कारण किया. बिरसा मुंडा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया. उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म-सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया. उन्होंने ब्रिटिस सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुये अपने अनुयायियों को सरकार को लगान नही देने का आदेश दिया.

विरसा मुंडा का जन्म 15 सितम्बर 1875 में लिहतु गॉव, जो रॉची जिले में पड़ता है, में हुआ था. सालगा गॉव में प्रारंभिक पढ़ाई के पश्चात वे चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने गये. सुगना मुडा और कर्मी हातू के पुत्र विरसा मुंडा के मन में बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह था. बचपन से मुंडा एक चंचल बालक थे. वे अंग्रेजों के बीच रहते हुये बडे हुये. बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाडे में बिताया हालांकि गरीबी की बजह से उन्हें रोजगार के लिये समय समय पर अपना घर बदलना पड़ा. इसी भूख की दौड़ ने ही उन्हें स्कूल की राह दिखाई और चाईबासा इंग्लिश मॉडल स्कूल में पढ़ने का मौका मिला. चाईबासा में विताये 4 वर्षों ने बिरसा के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला. सन 1895 तक विरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे जो जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे.

सन 1894 में आये अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिये अंग्रेजों से लगान माफी की मॉग के लिये आंदोलन किया. सन 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई. लेकिन विरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीडित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और यही कारण रहा कि अपने

जीवनकाल में उन्हें एक महापुरूष का दर्जा मिला.

उन्हें इस इलाके के लोग 'धरती आवा' अर्थात धरती के पिता के नाम से पुकारा और पूजा करते थे. उनके प्रभाव की बृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुडाओं में संगठित होने की चेतना जगी.

सन 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे तथा विरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजो की नाक में दम कर दिया. अगस्त 1897 में विरसा के 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूँटी थाने पर धावा बोला. सन 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़त अंग्रेज सेना से हुई. इस युद्ध में पहले अंग्रेज सेना हार गई लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया गया. जनवरी 1900 में डोबाडी पहाडी पर विरसा जब अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक और संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गये बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई. अंत में 3 फरवरी 1900को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया. बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसे 9 जून 1900 में रॉची के कारागार में ली. आज भी बिहार, उडीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में विरसा भगवान की तरह पूजे जाते हैं.

विरसा मुंडा ने अपने अदम्य साहस की स्याही से पुरूषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची. विरसा ने अपने देश, अपनी प्रकृति, जंगल, एवं अपने जमीन की रक्षा के लिये हॅसते हॅसते अपने प्राण की आहुति दे दी. राष्ट्र हमेशा उनके इस योगदान को याद रखेगा. स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाये जानें की घोषणा की है.

भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष

- सी. सिवशंकरी
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय मदुरै

आजादी शब्द में संघर्ष की अनेक कहानी समाहित होती हैं। आजादी केवल चंद दिनों या फिर थोड़े ही प्रयास से नहीं मिलती है। आज़ादी एक सोच है जो आगे चल कर समाज की भौतिक बेड़ियों को तोड़ती है। आज़ादी सभी को प्रिय है परंतु इसके पीछे का बलिदान सभी को ज्ञात नहीं होता है। भारत को आज़ादी मिले आज वर्ष 2022 में 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता हेतु प्राण गवाने वाले शहीदों के बलिदान का फल आजादी स्वरूप भारत की आम जनता तक को मिला। आज इस वर्ष सम्पूर्ण भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां हो चुकी है। अबकी बार यह बेहद खास होगा, क्योंकि देश इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। भारत सरकार भी आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर इसे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाने जा रही है। 15 अगस्त का दिन उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। भारत अपनी आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इन 75 सालों में भारत ने हर मोर्चे पर विकास किया है। अगर हम बात करें आर्थिक विकास की तो पाते है कि भारत आज दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक है।

15 अगस्त 1947, पूरे देश द्वारा मनाया जाने वाला एक दिन और एक संघर्ष के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि पूरे देश के अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। इस वर्ष हम एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 74 गौरवशाली वर्षों को पूरा कर रहे हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता उसके आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। अंग्रेजों द्वारा किए गए विभिन्न हमलों और विमुद्रीकरण के कारण, देश बुरी तरह से गरीब और आर्थिक रूप से ध्वस्त हो गया था।

दरअसल, यह पंडित नेहरू की रणनीति थी कि भारत को शीत युद्ध के दौरान दोनों ओर से बड़ी मदद मिली। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप ने वस्तुओं और तकनीकी सहायता में लगभग उतना ही योगदान किया जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी ने किया था।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, भारतीय राजनीति के सभी नेता चिंतित थे कि व्यापार और निवेश के माध्यम से विदेशी शासन आर्थिक नियंत्रण के बहाने वापसी करेगा।

ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की पहल थी जो यूएसएसआर में मौजूद लोगों के साथ तैयार की गई थी।

1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, मुख्य रूप से कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था जिसने बचत और निवेश में वृद्धि के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि को गति दी। यह योजना सफल रही जिसने अर्थव्यवस्था को 3.6% की वार्षिक दर प्रदान की और 2.1% के लक्ष्य को भी पार कर गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और इस योजना ने एक तरह से आत्मनिर्भरता की नींव रखी।

जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। चीन के साथ युद्ध ने भोजन की कमी और बढ़ती कीमत को जन्म दिया था और उसे आश्वस्त करने के लिए भारत को कृषि पर ध्यान केंद्रित करने और निजी उद्यमों व विदेशी निवेशों के लिए अनुमति देने की आवश्यकता थी।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप 1978/79 में 131 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया था। शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में यह भी तय किया कि भारत के पास चाय व रबर और इंजीनियरिंग उत्पादों तथा कृषि वस्तुओं का निर्यात शुरू करने के लिए पूंजी और क्षमता दोनों हैं।

1960 का दशक भारत के लिए विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का एक दशक था। रुपये के अवमूल्यन ने सामान्य रूप से कीमतें बढ़ाई दी थीं। 19 जुलाई, 1969 को तत्कालीन प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अकेले बड़े व्यवसायों के विपरीत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण को बढ़ाना था।

जब पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला तब उन्होंने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया, जिससे भारत की विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा वहीं गावों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शहर व ग्रामीण अर्थव्वस्था को मजबूत किया।

बिना किसी गुण दोष का ध्यान रखें परोपकार करना सज्जनों का व्यसन होता है - बाण भट्ट

अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ़्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची. अटल जी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया।

आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुवात की।

जीएसटी भारत को उन कुछ देशों में से एक बनाता है जिनके पास कर कानून है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्यों के कर कानूनों को एकजुट करता है, सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना कर रही है।

भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। देश में पहली बार प्रतिदिन 37 किमी नेशनल हाईवे 6 से 12 लेन के बनाये जा रहे। आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाने के लिए "उड़ान योजना" अक्टूबर 2016 में शुरू की गई है। 5जी से जहां संचारक्रांति आई वहीं इसरो ने एक साथ 100 से ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड मोदी सरकार के कार्यकाल में ही बनाया है।

देश अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से 'मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर' की और बढ़ चुका है। 2014 और 2021 के बीच बहुत कुछ बदल गया है। लाल फीताशाही पद्धति को बदलते हुए पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रहा है।

आज विश्व भारत को अग्रणी राष्ट्र एक संभावित महाशक्ति के रूप में देखता है। भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अग्रसर है और एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है।

संदेह नहीं की देश निकट 7 दशकों में सामाजिक आर्थिक उन्नयन के नए प्रतिमान गढें है। शिक्षा चिकित्सा वाणिज्य कृषि रक्षा परिवहन तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में विपुल विकास हुआ है किंतु परिमाणात्मक विकास के इस पश्चिमी मॉडल में हमारी गुणात्मक भारतीयता को क्षत-विक्षत भी किया है।

जीवन में दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक रचनात्मक होना आवश्यक है। गिलास जल से आधा भरा है सकारात्मक दृष्टि कहीं जाती है और गिलास आधा खाली है यह नकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है किंतु इन मान्यताओं में सकारात्मकता नकारात्मकता समान रूप से विद्यमान है। वस्तुत दोनों दृष्टियां सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है।

गिलास जल से आधा भरा है यह दृष्टि आशान्वित करती है कुंठा अवसाद और निराशा से बचाती है इसलिए सकारात्मक है किंतु यह गिलास को पूरा भरने के लिए प्रेरित नहीं करती अवचेतन में कहीं या भाव भर्ती है की अभी तो अपने पास आधा गिलास जल शेष है। जरूरत होने पर प्यास बुझ ही जाएगी। गिलास पूरा भरने के लिए अभी और प्रयत्न की क्या आवश्यकता है इसलिए यही दृष्टि नकारात्मक भी है। इसके विपरीत नकारात्मक समझी जाने वाली दृष्टि गिलास आधा खाली है गिलास को पूर्ण भरने के प्रयत्न की प्रेरणा देती है इसीलिए सकारात्मक है।

दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के आधे भरे गिलास को की हम सकारात्मक दृष्टि मानकर भौतिक उपलब्धियों में ही स्वतंत्रता की सार्थकता समझ बैठे हैं और अपने पारंपरिक नैतिक जीवन मूल्यों की उपेक्षा करते हुए ऐसे अदृश्य बियाबान में आकर फस गए हैं साहस और संघर्ष की चेतना लुप्त है और मृत्यु का गहन अंधकार आकर्षक लग रहा है। इसी कारण आत्महत्या बढ़ रही है। एक स्वाधीन देश की सार्वभौमिक सत्ता व्यवस्था के लिए यह यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।

जामखेड तहसील के साथ-साथ अगल बगल के तीन तहसीलों को सेवा दे रही पहली कार्डिएक एम्बुलेंस को हमारे बैंक के अहमदनगर क्षेत्र की जामखेड शाखा द्वारा सेन्ट व्हीकल योजना के अंतर्गत डॉ. एकनाथ मुंढे को वित्तपोषित किया गया.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कुशल कोंवर : अकीर्तित नायक

- सुजीत कुमार सिंह
प्रबंधक-राजभाषा
क्षेत्रीय कार्यालय, बरपेटा रोड

सर्वविदित है, 75 वर्ष पूर्व भारत अंग्रेजों की क्रूर शासन सत्ता का गुलाम था. भारत का प्रत्येक निवासी अंग्रेजों की यातनाओं का शिकारी बन चुका था. ऐसे में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए अनेक देशवासी आगे बढ़कर आएं, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना गया. देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण ही आज हम सभी स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं. हालांकि देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम संपूर्ण भारतवर्ष जानता है. लेकिन कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है जो कि इतिहास के पन्नों में दब के रह गए. आज की भावी पीढ़ी को भारत के संपूर्ण इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि नामी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही कुछ ऐसे स्वतंत्रता नायक भी रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए समान त्याग तथा बलिदान किया था. गुमनाम नायकों ने देश की आजादी में अपना विशेष योगदान देकर आंदोलनों तथा अंग्रजों के खिलाफ बढ़ रहे विरोधों को एक नया आयाम दिया था. उनके प्रति सम्मान की भावना को भारतवासी के हृदय में स्थापित होनी चाहिए. उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम आता है कुशल कोंवर का.

भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, कुशाल कोंवर नामक एक असमिया युवक को 15 जून, 1943 की सुबह 38 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया. कुशाल कोंवर की कहानी अटूट देशभक्ति, त्याग और साहस की कहानी है. उन्हें 10 अक्टूबर, 1942 की आधी रात को हुई एक घटना में फंसाया गया था. असम के गोलाघाट जिले के सरूपथर रेलवे स्टेशन पर सैन्य उपकरणों के साथ ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी. इसमें अधिकारियों और कुछ सामान्य यात्रियों सहित कई हजारों सैनिकों की मौत हो गई.

कुशल कोंवर का जन्म 21 मार्च 1905 में गोलाघाट जिले (पूर्व में शिवसागर जिले के अंतर्गत आने वाले) के घिलाधारी मौजा के चौडांग चरियाली नामक गाँव में हुआ था. मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे, कुशल कोंवर अन्य युवाओं की तरह ही थे, अपने समय का, एक शांत पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए, लेकिन 1925 के बाद से वे महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए और इसने उनके जीवन की दिशा बदल दी. उन्होंने एक चाय बागान में क्लर्क की नौकरी छोड़ दी ताकि वे भारत की आजादी के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकें.

8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति ने बंबई में अपनी बैठक

में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में भारत की धरती से अंग्रेजों को पूरी तरह से हटाने की मांग की गई. महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का नारा दिया था. अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल कर प्रतिक्रिया व्यक्त की. भारत भर में, इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन को जन्म दिया. वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोग जाति, पंथ और धर्म को तोड़कर सड़कों पर उतर आए.

भारत के अन्य हिस्सों की तरह, असम में भी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कुशल कोंवर उस समय सरुपथर जिला कांग्रेस इकाई के प्रमुख नेता थे. पूरे राज्य में स्थापित किए गए शांति सेना (शांति-बल) के साथ, मृत्यु बाहिनी (आत्मघाती दस्ते) भी बनाए गए, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के संचार नेटवर्क को पंगु बनाने के लिए तोड़फोड़ के कुछ गंभीर कार्य किए. इस बीच, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए हिंसक उपायों का सहारा लिया.

सरूपथर मृत्यु वाहिनी के सहयोग से जिला कांग्रेस इकाई ने एक सैन्य ट्रेन में तोड़फोड़ करने की योजना बनाई. हालांकि कुशल ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह जिला कांग्रेस के सदस्यों को इस तरह की गतिविधि करने के लिए मनाने में नाकाम रहे. 10 अक्टूबर 1942 को सुबह के घने कोहरे में छिपकर कुछ लोगों ने गोलाघाट जिले के सरुपथर के पास रेलवे लाइन के कुछ स्लीपरों को हटा दिया. वहां से गुजर रही एक सैन्य ट्रेन पटरी से उतर गई और कई ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई. ब्रिटिश सेना ने जल्द ही पूरे सरुपथर क्षेत्र को घेर लिया. पुलिस द्वारा कई लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार किया गया और शारीरिक रूप से

धीर पुरुष कार्यसिद्धि में विलंब होने पर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते - अभिनंद

प्रताड़ित किया गया. 13 अक्टूबर, 1942 को ब्रिटिश पुलिस ने कुशल कोंवर को सरूपथर ट्रेन तोड़फोड़ की घटना के मुख्य मास्टरमाइंड का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था. कुशाल कोंवर को कई लोगों ने भूमिगत होने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया. अदालत में कुशल कोंवर को दोषी करार दिया गया था, हालांकि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था. कुशल को फांसी की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने गरिमा के साथ फैसले को स्वीकार किया. कुशल कोंवर के अलावा कनकेश्वर कोंवर, धर्मकांता डेका और घनश्याम साइकिया को फांसी की सजा सुनाई गई. उन पर औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, लेकिन कुशल को छोड़कर, अन्य तीन ने दया याचिका के माध्यम से अपनी सजा को 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया. जब उनकी पत्नी, प्रभावती जोरहाट जेल में उनसे मिलने गईं, तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें गर्व है कि भगवान ने उन्हें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हजारों कैदियों में से एकमात्र के रूप में चुना है. कुशल ने अपने शेष दिन जोरहाट जेल की डेथ रो सेल में प्रार्थना और गीता पढ़ने में बिताए.

कुशल कोंवर निर्दोष थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी पूछताछ के गैरकानूनी सजा को स्वीकार कर लिया. उन्हें 1943 में जोरहाट जेल में फांसी दी गई थी. फांसी से पहले, कोंवर ने हरि के नाम का जाप करते हुए भगवद गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक पढ़े. हालांकि वह कभी भी ट्रेन तोड़फोड़ की घटना में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन कुशल कोंवर की फांसी औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा मूल निवासियों के बीच अपनी पहले से ही घटती शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक और हताश करने वाला प्रयास साबित हुआ.

भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की लेकिन आज हम उन लोगों को भूल जाते हैं इसलिए इन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है. हम नमन करते हैं ऐसे शूरवीरों को जिन्होने अपने प्राणों की आहूति देकर, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाया.

सेवानिवृत्ति / RETIREMENT

सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद एवं दीर्घायु जीवन हेतु मंगलकामनाएं...!!

श्री एच एस गरसा
महाप्रबंधक

श्री आनंद मोहन
उप महाप्रबंधक

श्री विनोद पोफले
उप महाप्रबंधक

श्री एस के गर्ग
उप महाप्रबंधक

पदोन्नति /PROMOTION

सेन्ट्रलाइट परिवार की ओर से हार्दिक बधाई...!!

श्री संदीप कार
उप महाप्रबंधक

श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

डिजिटल हिन्दी का भविष्य

- नैन्सी केशरी
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

आज पूरी दुनिया में इन्टरनेट का उपयोग हो रहा हैं, भले ही कुछ देशों में यह प्रयोग कम हैं और कुछ में ज्यादा. भारत की 8% से भी कम आबादी इन्टरनेट का उपयोग करती हैं. यह अनुपात विकसित देशों में 90% आबादी की तुलना मे काफी कम हैं. सूचना प्रोद्योगिकी की शुरुआत भले ही अमेरीका में हुई हो, फिर भी भारत की मदद के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती थी. गूगल के एक वरिष्ट अधिकारी की ये स्वीकारोक्ति काफी महत्वपूर्ण हैं की आने वाले कुछ वर्षो में भारत दुनिया के बड़े कंप्यूटर बाजारों में से एक होगा और इन्टरनेट पर जिन तीन भाषाओं का दबदबा होगा वे हैं- हिंदी, मेंडरिन और अंग्रेजी. इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती हैं कि आज भारत में 8 करोड़ लोग इन्टरनेट का उपयोग करते हैं इस आधार पर हम अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4 वे नंबर पर हैं. जिस रफ़्तार से यह संख्या बढ़ रही हैं, वह दिन दूर नहीं जब भारत में इन्टरनेट उपयोगकर्ता विश्व में सबसे अधिक होंगे.

आज पूरा विश्व डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल टीवी, डिजिटल वॉच, डिजिटल क्लासेस आदि का चलन आम हो गया है। डिजिटलीकरण के इस युग में बैंक भी पीछे नहीं हैं। वो भी नई-नई तकनीक को अपना कर खुद को अधिक से अधिक डिजिटल करने में लगे हुए हैं। इसके कारण बैंकों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। बैंक किसी भी समय कहीं भी मौजूद ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने और इसका विस्तार करने में लगे हुए हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के जरिए बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाना डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। इसके माध्यम से आप उन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको किसी बैंक ब्रांच में मिलती हैं। डिजिटल बैंकिंग कागजी कार्रवाई जैसे चेक, पे-इन स्लिप, डिमांड ड्राफ्ट आदि से मुक्त होती है। डिजिटल बैंकिंग आपको सभी बैंकिंग गतिविधियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराती है तथा आप 24ङ7 किसी भी बैंक शाखा में जाये बिना अपना काम कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का उपयोग लैपटॉप, टैबलेट या अपने मोबाइल फोन के जरिए किया जा सकता है।

आज राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन बैंकिंग कारोबार की आवश्यकता बन गई है. इस भाषा के माध्यम से बैंक अपने ग्राहक वर्ग तक अपने उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी आसानी से पहुंचा सकते हैं. बैंकिंग व्यवसाय में विकास एवं लाभ तभी संभव है, जब बैंक अपने ग्राहकों को उनकी बोधगम्य, सरल, सहज भाषा यानी हिंदी से संतुष्ट कर सके. जिससे अधिक से अधिक ग्राहक बैंकों से जुड़ सकेंगे एवं लाभप्रदता बढ़ेगी. वस्तुत: हिंदी का प्रयोग ना केवल एक वैधानिक आवश्यकता है बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग के दृष्टिगत बैंक तथा ग्राहक के मध्य संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम भी है. आज बैंकिंग उद्योग में प्रभावी विपणन में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है. आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में बैंकों द्वारा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के विक्रय हेतु विपणन में हिंदी भाषा को एक खास औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है. बैंकों द्वारा श्रव्य तथा दृश्य दोनों तरह के विज्ञापनों में भी हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है. हिंदी भाषा आज बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करके उनकी खूबियों को लोगों तक पहुंचा कर बैंकिंग संस्थानों के लाभ तथा में बढ़ोतरी करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं. यही कारण है कि बैंकिंग व्यवसाय में हिंदी को प्रभावी प्रचार माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

आज कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा टैबलेट आदि डिजिटल उपकरण हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल लगभग इन सभी उपकरणों में हिन्दी में काम करना सम्भव है। भाषाई समर्थन ने तकनीकी विभाजन की दूरी को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यूनिकोड सिस्टम ने हिन्दी को सभी कम्प्यूटिंग डिवाइसों तक पहुँचा दिया है। यूनिकोड सिस्टम के कारण कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में काम करना अंग्रेजी जैसा ही सरल हो गया है। इसी कारण अब इंटरनेट पर हिन्दी चिट्ठों तथा वेबसाइटों की भरमार है।

ऑपरेटिंग सिस्टमों की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज़, लिनक्स तथा ऍपल के मॅक ओऍस आदि डैस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टमों के अतिरिक्त आइओऍस तथा ऍण्ड्रॉइड जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टमों में भी इण्डिक यूनिकोड का समर्थन आ गया है। कम्प्यूटर पर ऑफिस सुइट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रेऑफिस इत्यादि में भारतीय भाषाओं में ठीक उसी तरह काम किया जा सकता है जैसे अंग्रेजी में। फलस्वरूप कम्प्यूटर पर भारतीय भाषायें अब केवल टाइपिंग तक सीमित न रहकर शॉर्टिंग, इंडैक्सिंग, सर्च, मेल मर्ज, हैडर-फुटर, फुटनोट्स, टिप्पणियाँ (कमेंट) आदि सब कम्प्यूटरी कार्यों में सक्षम हो गयी हैं। यहाँ तक कि आप फाइलों के नाम भी हिन्दी (या किसी अन्य भारतीय भाषा) में दे सकते हैं।

इंटरनेट पर भी अब अन्तर्राष्ट्रीय वर्ण-कूट मानक यूनिकोड खूब लोकप्रिय हो रहा है और सभी प्रमुख वेबसाइटें जैसे गूगल, विकिपीडिया आदि इसे अपना चुकी हैं। यूनिकोड आधारित वेबसाइटों को देखने के लिये पाठक के पास सम्बन्धित फॉण्ट होने की अनिवार्यता भी नहीं है। अगर कोई वेबसाइट यूनिकोड में है तो उसे किसी भी यूनिकोड सक्षम कम्प्यूटर पर देखा जा सकता है। यूनिकोड की लोकप्रियता संसार भर में दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती जा रही है तथा इसके साथ ही हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी वेबसाइट, ब्लॉग, ऑनलाइन वेब आधारित औजारों/उपकरणों/सुविधाओं का प्रयोग धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है। ईमेल में सीधे हिन्दी में सम्प्रेषण किया जा रहा है। मोबाइल फोन

पर भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संक्षिप्त सन्देश (SMS) तथा इंटरनेट संचार किया जाने लगा है।

भूमंडलीकरण के कारण जनसंचार माध्यमों का दायरा व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इंटरनेट, अधिकांश जनसमुदाय द्वारा बोली एवं उपयोग में लायी जाने वाली हिंदी को अनेक लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है 'इंटरनेट को हिंदी में महाजाल कहते हैं।' यह महाजाल इंटरनेट उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वेब मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण दिनों दिन बड़ता जा रहा है, आज ये मनुष्य के जीवन मे प्रवेश कर उन्हें प्रभावित कर रहा है।

प्रौद्योगिकी का विकास भूमंडलीकरण का एक प्रभाव है। भारत देश भी प्रौद्योगिकी को उतनी ही तेजी और तन्मयता से अपना रहा है जिस तरह विश्व के अन्य उन्नत देश इसे स्वीकार कर रहे हैं। महज एक कंप्यूटर के द्वारा एक व्यक्ति अपनी लगभग सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर कथाओं में मशहूर अलादीन का चिराग हो गया है। यह स्थिति विश्व की एक समान्य प्रचलित स्थिति कही जा सकती है। इस उत्साहवर्धक स्थिति में दो स्थितियाँ कार्यरत हैं जिसमें प्रथम है उन्नत शहर और द्वितीय हैं विकास की ओर बढ़ाने को प्रयासरत कस्बे और गाँव। इन दो स्थितियों का यदि विश्लेषण किया जाये तो यह तथ्य स्पष्ट होगा कि भारत के अधिकांश कस्बों और गाँव में प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति प्राय: बाधित रहती है परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी की उपयोगितामूलक प्रगति बाधित होती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के द्वारा अपने आवश्यक कार्यों के निपटान के बजाय जनसम्पर्क के द्वारा कार्य करना देश के सामान्य व्यक्ति को अधिक संतोषजनक लगता है। राजभाषा और प्रौद्योगिकी के क्षितिज निर्माण के दो प्रमुख कारण अति महत्वपूर्ण हैं।

देश-विदेश के लोगों के बीच की जिस दूरी को इंटरनेट ने कम किया था, विभिन्न भाषाओं की खाई ने उसे फिर से बढ़ा दिया। दुनियाभर की अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग फॉन्ट और इनके लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर यानी ज्ञान व सूचना के महासागर के सामने होने के बाद भी 'निरक्षरता'।

अब कंप्यूटर पूरी तरह से 'स्वतंत्र' व 'स्वाधीन' हो गए हैं।यूनीकोड ने इंटरनेट को भी सही मायने में एक नई दिशा व गति दी है। अगर कोई वेबसाइट यूनिकोड पर आधारित है तो उसे संसार में कहीं भी आसानी से खोला जा सकता है और उसके 'टेक्स्ट' को अपने कंप्यूटर में मनचाही फाइल के रूप में 'सेव' और 'एडिट' भी किया जा सकता है।

यह आजकल प्रचलित लगभग सभी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। वेब जगत के लिए तो यह बहुत फायदेमंद है। कंप्यूटर (विशेष रूप से सर्वर) को विभिन्न प्रकार की 'प्रोग्रामिंग लैंग्वेज' और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठाना होता है। ऐसे में यूनिकोड से काम बहुत आसान हो जाता है।

यूनिकोड ने हिंदी में ईमेल, चैटिंग, सर्चिंग, सर्फिंग आदि को भी आसान बना दिया है। गूगल, विकीपीडिया, एमएसएन आदि इसके उदाहरण हैं। वैदिक संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तमिल, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, उड़ीया आदि का भी इसके जरिए इंटरनेट के माध्यम से विश्वपटल तक पहुँचना संभव हो सका है। इससे भारतीय भाषाओं का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा।

6 दिसंबर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय मुंबई की उप निदेशक सुश्री सुष्मिता भट्टाचार्या द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन का औचक और भौतिक निरीक्षण किया गया.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एक कहानी

- सुजीत कुमार
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

धीरेन और नलिनी राजस्थान के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 4 दिन का अवकाश था, वे पेशे से चिकित्सक थे। लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे। परंतु जब भी दो-तीन दिन का अवकाश मिलता, छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते।

आज उनका गाजियाबाद जाने का विचार था। दोनों जब साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ था,और बढ़ते - बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए, संतान कोई थी नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे।

विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया, बैंक से लोन लिया। नलिनी स्त्री रोग विशेषज्ञ और धीरेन डाक्टर आफ मेडिसिन थे। इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला था.

यात्रा पर रवाना हुए, आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। दिल्ली की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी।

गाजियाबाद सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया।

भोजन तो दिल्ली में जाकर करने का विचार था। परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर से चार पांच किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। धीरेन ने वहां पर गाड़ी रोकी, दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर के आई।

उसने पूछा क्या चाहिए?

धीरेन ने दो पैकेट वेफर्स के लिए, और कहा दो कप चाय बना देना। थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है।

पैकेट लेकर के गाड़ी में गए। नलिनी और दोनों ने पैकेट के वैफर्स का नाश्ता किया।

चाय अभी तक आई नहीं थी।

दोनों कार से निकल कर के दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे। धीरेन ने फिर आवाज लगाई।

थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोली-बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बन रही है।

थोड़ी देर बाद एक प्लेट में दो मैले से कप ले करके वह गरमा गरम चाय लाई।

मैले कप को देखकर धीरेन एकदम से अपसेट हो गए, और कुछ बोलना चाहते थे। परंतु नलिनी ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया।

चाय के कप उठाए। उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई।

उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा कितने पैसे ?

महिला ने कहा - बीस रुपये

धीरेन ने सौ का नोट दिया।

महिला ने कहा कि छुट्टा नहीं है। 20 छुट्टा दे दो। धीरेन ने बीस रु का नोट दिया। महिला ने सौ का नोट वापस किया।

धीरेन ने कहा कि हमने तो वैफर्स के पैकेट भी लिए हैं !

महिला बोली यह पैसे उसी के हैं। चाय के पैसे नहीं लिए।

अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए ?

जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं। यह होटल नहीं है।

- फिर आपने चाय क्यों बना दी ?

- अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते। इसलिए इसके दूध की चाय बना दी।

- अभी बच्चे को क्या पिलाओगे?

- एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं वह शहर जा करके दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे।

धीरेन उसकी बात सुनकर सन्न रह गये। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, अतिथि रूप में आकर के।

संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे हैं।

उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहां हैं बताएं। महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे। बहुत दुबले पतले थे।

धीरेन ने जाकर उनका मस्तक संभाला। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे, और कांप रहे थे धीरेन वापस गाड़ी में, गए दवाई का अपना बैग लेकर के आए। उनको दो-तीन टेबलेट निकालकर के दी, खिलाई।

फिर कहा- कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा।

मैं पीछे शहर में जा कर के और इंजेक्शन और इनके लिए बोतल ले आता हूं। नलिनी को उन्होंने मरीज के पास बैठने का कहा।

गाड़ी लेकर के गए, आधे घंटे में शहर से बोतल, इंजेक्शन, ले कर के आए और साथ में दूध की थैलीयां भी लेकरआये।

मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई, और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं ही बैठे रहे।

एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी।

दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की।

जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुए, तब वह दोनों वहां से आगे बढ़े।

3 दिन गाजियाबाद-दिल्ली में रहकर, जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने, और दूध की थैली लेकर के आए।

वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज लगाई, तो दोनों बाहर निकल कर उनको देख कर बहुत खुश हो गये।

उन्होंने कहा कि आप की दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया।

धीरेन ने बच्चे को खिलोने दिए। दूध के पैकेट दिए। फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। धीरेन ने अपना एड्रेस कार्ड दिया। कहा, जब भी आओ जरूर मिले, और दोनों वहां से अपने शहर की ओर, लौट गये।

शहर पहुंचकर धीरेन ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला लिया।

अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि,अब आगे से आप जो भी मरीज आयें, केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे। फीस मैं खुद लूंगा।

और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होते तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया।

केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते।

धीरे-धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डाक्टरों ने सुना। उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा।

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ धीरेन से मिलने आए , उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो?

तब धीरेन ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी उद्वेलित हो गया।

धीरेन ने कहा कि मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा। एमबीबीएस में भी, एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है, वह मुझसे आगे निकल गयी। तो मैं अब पीछे कैसे रहूं?

इसलिए मैं अतिथि सेवा में मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की। और मैं यह कहता हूं कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें। गरीबों की निशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं।

परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है,

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने धीरेन को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर के चिकित्सकीय करूंगा।

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में दिनांक 30.12.2021 को राजभाषा पुस्तक प्रदर्शनी, राजभाषा संदेश, राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा आंतरिक कामकाज (कुल 4) प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिसमें बैंक नराकास जयपुर के सचिव की आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही स्टाफ सदस्यों हेतु अभिप्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

परिसर नीति - कुछ विधिक पहलू

- ए. के. बंसल
सहायक महाप्रबंधक
- विधि (सेवानिवृत्त)

पूरे भारतवर्ष में सभी बैंकों की करीब 90000 शाखाएं हैं. सभी शाखाओं का स्वामित्व होना लगभग असंभव है. अत/ बैंकों ने अधिकतर शाखाएं किराए पर ली हुई हैं. यह शाखाएं महानगरीय, अर्द्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई हैं.

पिछले करीब दो दशक से बैंकिंग तकनालॉजी में अत्यधिक बदलाव आए हैं. कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) तथा इन्टरनेट बैंकिंग के प्रचलन में आने से शाखाओं की मूलभूत आवश्यकताओं में बहुत बड़ा अन्तर आया है. 'एकल खिड़की' व 'कही भी कभी भी बैंकिंग' के अस्तित्व में आने से परिसर नीति में काफी बदलाव आए हैं. करीब तीन दशक पूर्व शाखाओं के लिए काफी बड़े परिसर की आवश्यकता महसूस होती थी. पूर्व में स्टाफ-सदस्य भी काफी संख्या में होते थे. परंतु शाखाओं के कम्प्यूटरीकृत हो जाने के पश्चात, बहुत बड़ परिसर की आवश्यकता नहीं रह गई है.

साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में नये आयाम आने से भू-स्वामी अपने परिसरों को तोड़कर मॉल व बड़े-बड़े शो-रूम बना रहे हैं जिनसे उनको अधिक आमदनी हो रही है. इसके चलते बैंकों हेतु उपयुक्त परिसरों में निश्चित रूप से कमी आई है. इसके साथ ही विभिन्न राज्यों मे लागू किराया कानूनों में संशोधन के चलते, नए नियमों के आने व महंगाई में बढ़ोत्तरी के चलते भवन-स्वामियों द्वारा किराए में अत्यधिक बढ़ोत्तरी की अपेक्षा की जा रही है. पूर्व में शाखाओं हेतु परिसर काफी कम किराए पर लिए गए थे. परंतु वाणिज्यिक गतिविधियों में बदलाव होने व नए व्यापारिक केन्द्र बनने से सम्पत्तियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है. इसके चलते भूस्वामी पुराने किराए या किराए में मामूली बढ़त से परिसर को पट्टे पर देने को तैयार नहीं है. इन परिस्थितियों के चलते बैंकों को अपनी परिसर नीति में उपयुक्त बदलाव लाना होगा. लेखक की राय में परिसर किराए पर लेते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए तो परिसर से संबंधित काफी विवादों को रोका जा सकता है :

1) शाखा खोलने हेतु परिसर ढूंढते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण, लक्षित ग्राहक तथा आगामी 10 से 15 वर्षों की व्यावसायिक संभाव्यता को मद्देनजर रखा जाना चाहिए इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित परिसर सुरक्षा की दृष्टि से उचित है तथा ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है. इस कार्य में संबंधित सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करना आवश्यक हो जाता है.

2) प्रस्तावित परिसर का बैंक के वास्तुविद द्वारा भी निरीक्षण आवश्यक है ताकि कम से कम जगह का अधिक से अधिक उपयोग हो सकें और बैंक को बड़ी शाखा चलाने हेतु भी कम से कम किराया व्यय करना पड़े. वैसे भी अब 'एकल खिड़की बैंकिंग' व एटीएम तथा इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा के उपरांत बहुत बड़े परिसर की आवश्यकता नहीं रह गई है.

3) यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है परिसर स्वामी का स्वामित्व. परिसर किराए पर लेते समय परिसर स्वामी का स्वामित्व सुनिश्चित करना अति आवश्यक है. यदि परिसर के स्वामी एक से अधिक हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन स्वामियों में आपस में कोई विवाद नहीं हो. ऐसी स्थिति में किराया व अन्य शर्तें सभी स्वामियों की मौजूदगी में तय करना बैंक के लिए हितकर होगा. यदि परिसर स्वामी एक से अधिक है और अलग-अलग स्थानों में रहते हैं तथा पट्टा निष्पादन हेतु सभी स्वामी इकट्ठे नहीं हो सकते तो यह विधिक रूप से आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी एक स्वामी के पक्ष में पट्टा निष्पादन हेतु पावर ऑफ अटार्नी प्रदान करें ताकि वह स्वामी, जिसके पक्ष में पावर ऑफ अटार्नी प्रदान की गई है, अपने व दूसरे स्वामियों की ओर से पट्टे का निष्पादन कर सके. ऐसे केस में परिसर का किराया भी सभी के संयुक्त खाते में अंतरित किया जाना चाहिए. ऐसे ही एक केस में एक परिसर के दो स्वामी थे. एक स्वामी ने पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर बैंक के पक्ष में पट्टे का निष्पादन किया. शाखा ने परिसर का किराया उनके संयुक्त खाते में अंतरित कर दिया. जिस स्वामी के पक्ष में पावर ऑफ अटार्नी थी उसने आग्रह किया कि क्योंकि पट्टे का निष्पादन उसने किया है, अत: किराए का भुगतान उसके पक्ष में होना चाहिए. शाखा के मना करने पर उसने न्यायालय में वाद दायर किया ताकि किराया उसके खाते में जमा हो. न्यायालय ने वाद यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर स्वामित्व नहीं बदल सकता और पावर ऑफ अटार्नी मात्र पट्टे के निष्पादन हेतु थी.

4) पट्टे हेतु किराया व अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से निश्चित होनी चाहिए किराये के साथ करों (टैक्स) जैसे म्युनिसिपल टैक्स, सम्पत्ति टैक्स, जलकर, जीएसटी इत्यादि को बारे में निश्चित किया जाना चाहिए कि यह सभी टैक्स भवन मालिक अदा करेगा या बैंक. इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में यदि टैक्स में कोई बदलाव होता है तो उसका वहन कौन पक्ष करेगा. इसके साथ -साथ पट्टे को अवधि, भवन का क्षेत्रफल, पार्किंग हेतु उपयुक्त स्थान जेनरेटर रखने हेतु सुविधा (स्थान) इत्यादि का स्पष्ट रूप से पट्टे में लिखित वर्णन होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो. यदि शाखा आवासीय क्षेत्र में है तो भूस्वामी को परिसर को बैंक के उपयोग हेतु नगरपालिका / संबंधित अधिकारी से पट्टा निष्पादन से पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिए. इस संबंध में यदि बाद में किसी प्रकार

भी कोई आपत्ति या प्रभार किसी अधिकारी द्वारा लगाई जाती है तो उसका दायित्व भवन स्वामी का होना चाहिए.

5) एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है कि पट्टा में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि भवन बैंक की शाखा या अन्य प्रशासनिक दफ्तर हेतु उपयोग किया जा सकता है. ऐसा न लिखना विवाद का विषय हो सकता है. ऐसे ही एक केस में बैंक ने शाखा हेतु परिसर 15 वर्ष हेतु किराए पर लिया करीब पांच वर्ष बाद वह शाखा बंद कर दी गई तथा बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय वहां स्थापित कर लिया भूस्वामी ने इस पर आपत्ति जताते हुए वाद दायर कर दिया कि यह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है. केस अभी कोर्ट में लंबित है. तात्पर्य है कि यदि सभी तरह की संभावनाओं की मद्देनजर रखा जाए तो बिना वजह के विवादों से छुटकरा मिल सकता है.

6) पिछले कुछ वर्षों से तकनीकी विकास के कारण बैंकों को अपनी शाखाओं में कई तरह के उपकरण लगाने पड़ रहे हैं. यह देखा गया है कि भवन स्वामी इनको लगाने हेतु या तो मना कर रहे हैं या अपनी है अनावश्यक शर्तें थोप रहे हैं. यह देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि पट्टा विलेख में इस बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए कि बैंक, शाखा चलाने हेतु आवश्यक उपकरण जब भी जहां भी आवश्यकता हो, लगानेहेतु स्वतंत्र होगा व इस संबंध में भवन-स्वामी कोई आपत्ति नहीं करेंगे.

7) यह भी देखा गया है कि पट्टा विलेख के अंत में सम्पत्ति की सूची (Schedule of Property/ Premises) का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहले है. इसलिए सूची में किराए पर लिए भवन का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए जैसे : भवन का क्षेत्रफल, हॉल, स्ट्रांग रूम, स्टोर, प्रसाधन, बरामदा, सीढियां इत्यादि, और यदि भवन उपरी मंजिल पर है तो यदि लिफ्ट की व्यवस्था है तो इसका जिक्र भी किया जाना चाहिए. साथ ही जेनरेटर रखने हेतु स्थान तथा स्टाफ व ग्राहकों हेतु पार्किंग की व्यवस्था का स्पष्ट रूप से जिक्र किया जाना चाहिए. ऐसे ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा ने पट्टे में पार्किंग का भी जिक्र किया लेकिन कुछ समय पश्चात भवन मालिक ने शाखा के विरूद्ध कोर्ट में दावा दायर किया कि पार्किंग स्थल मात्र स्टाफ सदस्यों के एक दो वाहनों हेतु है न कि बाहर के लोगों यानि बैंक के ग्राहकों हेतु. बैंक ने अपना उत्तर दायर करते हुए कोई को निवेदन किया कि बैंक एक व्यावसायिक संगठन है इसलिए यहां ग्राहकों का आना जाना व अपने वाहनों की पार्किंग स्वाभाविक है. अंत में कोर्ट ने भवन-मालिक का दावा खारिज करते हुए निर्देश दिया कि भवन मालिक पार्किंग हेतु कोई आपत्ति न करें. इसलिए ऐसी स्थिति से बचने हेतु पट्टा पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए.

8) पट्टा-बिलेख निर्धारित स्टाम्प पेपर पर स्पष्ट रूप से लिखा या टंकित किया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि पट्टे में भवन-स्वामी / स्वामियों के नाम व पूरा पता, पट्टे की अवधि,देय किराया, सम्पत्ति का ब्यौरा तथा अन्य सभी शर्तों, जैसा उपरोक्त वर्णन है, का पूर्ण जिक्र किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सकें. पट्टे संबंधी एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पट्टे में तारीख वगैरह उसी समय व उसी दिन की हो जब पट्टा विलेख उप निबंधक के समक्ष, पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा हो. अन्यथा इसमें विधिक समस्या आ सकती है. लेखक के समक्ष इस संबंध में एक दिलचस्प केस आया. एक शाखा के परिसर का पट्टा-विलेख पंजीकृत होना था. पट्टा पूरी तरह तैयार था व उस पर तारीख भी वर्णित थी, परंतु किसी कारण से उक्त पट्टा पंजीकृत नहीं हो सका व कई महिनों तक उस पर वांछित कार्रवाई नहीं हुई. जब लेखक, शाखा प्रबंधक के साथ दोबारा उसे पंजीकरण हेतु उप निबंधक के समक्ष, पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया तो उप निबंधक महोदय ने पट्टा-विलेख का पंजीकरण करने से मना कर दिया क्योंकि पट्टा विलेख का निष्पादन (यानि दोनों पक्षों के हस्ताक्षर) किए हुए चार महिने से अधिक हो गए हैं अत: इस विलेख का पंजीकरण अधिनियम के तहत जब्त (impound) किया जाएगा. लेखक ने पट्टा विलेख का दोबारा निरीक्षण किया और पाया कि पक्षों के हस्ताक्षरों के नीचे काई तारीख नहीं लिखी थी. उप निबंधक महोदय को निवेदन किया कि यदि सभी पक्ष अपने हस्ताक्षरों के नीचे उस दिन की तारीख लिख दें तो विलेख का निष्पादन आज की तिथि से माना जा सकता है. लेखक के इस तर्क से उप निबंधक सहमत हो गए और पट्टा-विलेख का निष्पादन हो गया. इसी तरह की कई अन्य विधिक व दूसरी दिक्कतों पट्टा विलेख के संबंध में अक्सर आती है जिन्हें वक्त रहते व उचित विधिक परामर्श से सुलझाया जा सकता है.

9) अक्सर यह स्थिति भी सामने आती है कि पट्टा अवधि के दौरान पट्टाकर्ता / परिसर स्वामी की मृत्यु हो जाती है. ऐसी परिस्थिति में नवीन पट्टे की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उसी पट्टे को जारी रखा जा सकता है. पट्टा विलेख में यह व्यवस्था होती है कि पट्टाकर्ता के साथ उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, न्यासी,वारिस, निष्पादक एवं समनुदेशिति भी सम्मिलित होंगे. ऐसी स्थिति में पट्टाकर्ता के उत्तराधिकारी इत्यादि से एक शपथ पत्र लिया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से पट्टाकर्ता की मृत्यु का दिनांक लिखा हो, यह कि हम अमुक व्यक्ति उनके उत्तराधिकारी हैं तथा हमें पट्टे की सभी शर्तों व नियम स्वीकार्य हैं अत: भविष्य में किराया उनके खाते में अदा किया जाए. शपथ पत्र के साथ पट्टाकर्ता का मृत्यु-प्रमाणपत्र भी लिया जाए व इन दस्तावेजों को मूल पट्टे के साथ ही रखा जाए. इसके उपरांत किराया पट्टाकर्ता के उत्तराधिकारियों को दिया जा सकता है. इस संबंध में किसी प्रकार के संदेह या विवाद को बैंक के अधिवक्ता या विधि विभाग को सौंपा जाना चाहिए ताकि उचित परामर्श मिल सकें.

भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बैंक की कोई भी शाखा या अन्य कार्यालय बिना पंजीकृत पट्टे के किराए पर नहीं ली जानी चाहिए. ऐसी व्यवस्था, शाखा परिसरों के संबंध में बढ़ते हुए विवादों को देखते हए की गई है. यह देखा गया है कि शाखा परिसर के उत्तरोत्तर बढ़ते विवादों के कारण शाखा प्रबंधकों का काफी समय बर्बाद होता है जिसके कारण वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने में अपना पूरा समय नहीं दे पाते यदि पट्टा विलेख में उपरोक्त सावधानियां बरती जाएं तो परिसर संबंधी काफी विवाद उत्पन्न ही नहीं होंगे. इससे बैंकों का बहुमूल्य समय भी बचेगा व विवादों पर होने वाला व्यय भी.

भारतीय बैंकिंग - दिशा एवं दशा

- अनुश्री मालवीय
शाखा प्रबंधक
शाखा - पैकोली, क्षेत्र - देवरिया

बैंकिंग : आज वैश्विक उन्नति अपने चरम पर है और आने वाले समय में किसी भी हद में यह उन्नति बंध नहीं पाएगी. परंतु विश्व और समाज को उन्नत बनाता कौन है ?

एक उन्नत और प्रगतिशील समाज के कई कारक होते हैं. बैंकिंग उनमें से एक अति महत्वपूर्ण कारक है.

बैंकिंग का सीधा संबंध पूंजी से होता है. जब तक समाज में पूंजी का सही प्रबंधन, सूदखोरों से मुक्ति एवं बचत की भावना नहीं आएगी, समाज कभी प्रगति नहीं कर पाएगा.

भारतीय बैंकिंग : भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरूआत 18वीं शताब्दी में ही हो गई थी. बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी. जनरल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1791 में हुई थी, ने बैंकिंग की नींव डाली थी. यद्यपि ये बैंक असफल रहे और दिवालिया भी घोषित हो गए परंतु एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरूआत हो चुकी थी. इसके बाद जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना बैंक है जो अभी तक क्रियाशील है. हालांकि भारत का पहला स्वदेशी बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - हमारा अपना बैंक बना. इसकी स्थापना 1911 में श्री सोराबजी पोचखानवाला द्वारा प्रमुख रूप से भारतीयों के लिए की गयी थी. यह बैंक आज भी क्रियाशील है एवं देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुखता से योगदान दे रहा है.

पूर्व में कई बैंक भारत में अस्तित्व में आए. परंतु इनको विनियमित करने के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई. अत: 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई. 18 वीं शताब्दी से आज 21 वीं शताब्दी तक भारत में बैंकिंग का चेहरा काफी बदल गया है.

भारत के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग के कई पहलू देखे जा सकते हैं. इसका मुख्य कारण है भारत का फैला हुआ क्षेत्रफल, भिन्न क्षेत्र के भिन्न प्रकार के लोग एवं लोगों के जीवन स्तर में सामाजिक असमानता. अलग-अलग क्षेत्र में अलग मानसिकता के लोग होते है और उनकी अलग-अलग आवश्यकताएं.

जहां शहरी क्षेत्र के लोग काफी जागरूक, पढ़े-लिखे एवं बैंक से भली-भांति परिचित है वहीं अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपेक्षाकृत कम जागरूक होते है. अलग-अलग प्रकार के क्षेत्र के लोगों के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं होती है. जहां तक भारत में बैंकों की बात करें तो आज भारत में कुल 34 बैंक क्रियाशील है जिनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 22 निजी क्षेत्र के बैंक है. यहीं नहीं, मार्च 2019 तक भारत में 120000 से अधिक बैंक शाखाएं एवं 200000 से ज्यादा ए टी एम खोले जा चुके है.

भारत की जनसंख्या की बात करें तो यहां 50% से अधिक आबादी (मार्च 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 65.53% लोग गांवों में रहते है) इसका अर्थ यह है कि आबादी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक आवश्यकता है. मार्च 2019 के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 35649 बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है. यहां से ग्रामीण बैंकिंग का महत्व बढ़ जाता है.

ग्रामीण बैंकिंग : भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं जानकारी के अभाव में अनेक कुरितियों ने जन्म ले लिया है. जैसे- सूदखोरों से पैसा उधार लेना, जमींदारों के पास जमीन गिरवी रखकर भारी ब्याज पर पैसा लेना एवं खेती के लिए पैसा न होने पर अपने से मजबूत किसानों द्वारा ठग लिया जाना बहुत ही सामान्य सी बात है. परंतु इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा ने एक उज्जवल बदलाव की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है. ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों ने किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं को खाली मदद पहुंचाई है. भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण निवासियों की सुविधा के लिए अनेक स्कीम निकाली है. जैसे - किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन एवं मत्स्य पालन ऋण आदि. इन स्कीमों के अंतर्गत न सिर्फ किसानों को कम ऋण पर खेती के लिए पूंजी दी जाती है बल्कि समय पर ऋण चुकाने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है. यू.पी. में वर्ष 2020-21 में 1.60 लाख से ज्यादा लोगों को के सी सी का लाभ मिला.

पूर्व में भोले किसानों के पास भारी सूद पर जमींदारों से पैसे लेने और खेत गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था. परंतु भारतीय बैंकिंग की सुविधा से छोटे किसान न सिर्फ सूदखोरों के चुंगल से मुक्त हो रहे है. बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं. यही नहीं इन स्कीमों के इस्तेमाल किसान घरेलु आवश्यकता हेतु, फसलोत्तर खर्च, फार्म आस्तियों के रखरखाव के लिए भी कर सकते हैं.

शहरों की तरफ पलायन : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न होने के कारण युवाओं का शहर की ओर पलायन भी भारत की एक बड़ी समस्या रही है. इससे न सिर्फ शहरों पर भार बढ़ता है, बल्कि शहर के संसाधनों का भी अंधाधुंद उपयोग जीवन एवं पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ता है. इस समस्या को काफी हद तक बैंकिंग ने कम करने का प्रयास किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवसाय के लिए बैंक ऋण दे रहे है जैसे - पशुपालन ऋण, मुर्गी, मछली पालन ऋण, सोलर एनर्जी ऋण आदि. इससे ग्रामीण युवक युवतियां विभिन्न व्यवसाय करके न सिर्फ अपना जीवनयापन कर सकते है. बल्कि दूध, दही, गोबर आदि शहरों में निर्यात भी कर सकते है. अर्थात् भारत के एक छोटे से गांव का

आदमी भी अपना खुद का व्यवसाय करके एक बड़ा उद्यमी बन जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं.

शहरी एवं अर्द्धशहरी स्थानों में बैंकिंग : ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच ने लोगों के कार्य का खासा आसान बना दिया. बैंकों द्वारा ऋण पर शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को गति दी है. चेक क्लियरिंग के माध्यम से लोगों के कार्य को, लेन-देन को और सरल बना दिया है. यही नहीं शहरों में अपना घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो या खुद का व्यवसाय करना हो - लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बैंक ऋण देने के माध्यम से मदद कर रहा है. यदि बैंक न हो तो क्या किसी व्यक्ति की पैसे की आवश्यकता को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सकता है ? नहीं. या तो उन्हें जरूरत के अनुसार धनराशि नहीं मिलेगी और मिल भी गयी तो ब्याज दर आम आदमी को लुटने के लिए पर्याप्त होगा.

यहीं नहीं बैंकिंग से लोगों में पैसे की बचत को लेकर भी उत्साह रहता है. जो भी बचत का पैसा खाते में जमा होता है उस पर बैंक आमजन को ब्याज देती है जिससे न सिर्फ लोगों को फायदा होता है बल्कि बचत की भावना भी बढ़ती है.

भारत में डिजिटल बैंकिंग : समय के साथ कदम न मिलाने पर इंसान बाकी दुनिया के कट जाता है. पूरी दुनिया आज कैशलेस बैंकिंग की ओर अग्रसर है जिससे कम कठिनाई और कम समय में अधिक से अधिक लेनदेन हो सकता है. भारत सरकार कैशलेस बैंकिंग की महत्ता को पहचान कर ही डिजिटल बैंकिंग पर विशेष दबाव बना रही है. 2014 के बाद से लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एवं गूगल पर आदि माध्यमों से पैसे के लेन-देन पर विशेष स्थान आकर्षित किया जा रहा है. इस प्रकार के डिजिटल बैंकिंगसे जाली नोट एवं चेक द्वारा फ्राड की समस्या तो खत्म होगी ही बल्कि समय की भी खासी बचत होगी. उदाहरण - जो नेफ्ट बैंक आकर करने में भीड़ एवं अन्य समस्याओं के कारण 2-3 घंटा लग जाता था वहीं कार्य डिजिटल बैंकिंग से चंद मिनटों में हो जाता है.

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जनवरी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ भारत में पिछले 5 सालों में डिजिटल ट्रांसेक्शन 55% यही नहीं पूरे विश्व में साल 2020-21 में 97% ट्रांजेक्शन डिजिटली हुए. एन पी सी आई द्वारा जारी किये हुए आंकड़ों के अनुसार सितम्बर 2020 में लगभग 3.29 लाख करोड़ रुपए 1.80 बिलियन यू.पी.आई. ट्रांजेक्शन द्वारा ट्रांसफर किये गए.

रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सितम्बर 2020 में कुल 1.66 बिलियन लेन-देन जो कि कुल रुपए 5.99 लाख करोड़ का था सिर्फ मोबाइल बैंकिंग द्वारा किया गया.

अत: भविष्य में संपूर्ण लेनदेन डिजिटल बैंकिंग द्वारा ही होने की पूरी उम्मीद है. भारत में अधिकतर आबादी युवाओं की है जिनकी उम्र 35 साल से कम है. ऐसे युवाओं के लिए मोबाइल लैपटॉप आदि तकनीकी चीजें चलाना कोई मुश्किल नहीं है. यही नहीं, यह पीढ़ी न सिर्फ टेक्नो फ्रेंडली है बल्कि कम समय में ज्यादा काम मानी स्मार्टवर्क को प्राथमिकता देती है. ऐसे लोगों के लिए डिजिटल बैंकिंग काफी मददगार होती है. ये न ही गैस, बिजली बिल जमा करने लाइन में लगना पसंद करते है न ही बाजार में धूम-धूम कर पैसा देकर सामान खरीदना. अत: ऑनलाइन बैंकिंग से बेहतर विकल्प इनके लिए और कोई नहीं. नई-नई तकनीकी उन्नयन के कारण अग लोन के लिए आवेदन करने से लेकर एक छोटे से गांव में किराना की दुकान पर भुगतान करने तक सब काम डिजिटली संभव है. भारत सरकार, रिज़र्व बैंक एवं एन.पी.सी.आई. द्वारा नए-नए और आसान एप्स भी लांच किये जा रहे है जिससे एक अनपढ़ आदमी भी आराम से इनका इस्तेमाल कर सकें. भीम एप, गूगल पे आदि इसका उदाहरण है;

यहीं नहीं, अब दुकानों आदि पर पॉस मशीनों को भी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. जिससे की सामान की खरीद फरोख्त कैशलेस हो. इससे कई प्रकार की जालसाजी से भी आदमी बच जाता है.

कोरोना काल और बैंकिंग : कोरोना काल से भयंकर समय शायद आज की पीढ़ी ने नहीं देखा होगा. इस कोरोना काल में जहां लोगों को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं लगता होगा, वहीं डिजिटल बैंकिंग ने उनकी दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति जैसे खाना (आनलाइन), रिचार्ज, बिजली-गैस बिल का भुगतान घर बैठे किया. इससे न सिर्फ लोग सुरक्षित रहे बल्कि कोई भारी समस्या भी नहीं हुई.

पूरे कोरोना काल में सभी बैंक शाखाएं खुली रही. बैंक कर्मियों ने इस खतरे में भी नियमित लोगों को नकदी उपलब्ध करायी. यही नहीं इस कोरोना काल में बैंकिंग सेवा देते देते कितने ही बैंकर्स काल के जाल में समा गए. बैंकों में रखा पैसा और बैंकों द्वारा की गयी कर्तव्य परायणता ने ही न सिर्फ लोगों को परेशानी (नकदी संबंधी) से बचाया बल्कि अर्थव्यवस्था को भी संभाले रखा.

भारत को महाशक्ति बनाने में बैंकों का योगदान : भारत का 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जो भारत सरकार देख रही है उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारतीय बैंकिंग ही है. जब तक प्रत्येक भारतीय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा. भारत एक मजबूत देश नहीं बन सकता है. भारत की जी.डी.पी. को अन्य विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए पूंजी का उचित प्रबंधन एवं आम जन को बैंकों से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है. इस दिशा में भारत सरकार के अधिकतर प्रयास बैंकों से होकर जाते हैं.

जन-धन खाते : प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ने के लिए उसका बचत खाता होना अनिवार्य है. इसी दिशा में भारत सरकार ने जन-धन खाते यानि न्यूनतम बैलंस की अनिवार्यता को खत्म करके भारत के सबसे निचले और कमजोर तबके के व्यक्ति के खाते खुलवाए एवं उनको देश की मुख्यधारा में लाया गया. इस अभियान तहत भारत में अब तक कुल 42 करोड़ जनधन खाते मार्च 2020 तक खोले जा चुके हैं. इनमें कुल 139864 रुपए जमा हो चुके हैं. इस अभियान को भारत सरकार की पहल एवं बैंक कर्मियों की जिजीविषा और मेहनत के बूते पर ही संभव किया जा सका है. इन खातों के खुलने से अब इनमें होने वाले सभी लेनदेन भारती की जी.डी.पी. को मजबूत करने में प्रभावी होगे. यही नहीं प्रत्येक व्यक्ति के बचत खाते होने से भारत सरकार द्वारा दी

जाने वाली आर्थिक सहायता जैसे गैस सब्सिडी, वृद्ध पेंशन, डायरेक्टर बेनेफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आने वाले सभी लेनदेन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जाएंगे. इससे न सिर्फ आम जनता को बिचौलियों और घूसखोरी से मुक्ति मिलेगी बल्कि यह प्रक्रिया और पारदर्शी भी होगी.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को ऋण : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में टूटने से बचाया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का क्षेत्र भारत के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका है. इसकी उपयोगिता समझ कर भारत सरकार भिन्न-भिन्न योजनाओं के तहत इस क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा रही है ताकि पूंजी के अभाव में कोई उद्योग दम न तोड़े. इसलिए बैंक भी इस क्षेत्र में मुद्रा योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंदर ऋण उपलब्ध करा रहा है. इस पूंजी निवेश से यह क्षेत्र न सिर्फ व्यवसाय, आयात-निर्यात, माल का उत्पादन में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी दिखा रहा है बल्कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर तेज दौड़ा रहा है. सर्वज्ञात है कि भारत की जी.डी.पी. में इस क्षेत्रका 30% योगदान रहा है कुल निर्यात में 48% निर्यात इसी क्षेत्र से है. सरकार द्वारा 48% निर्यात को 60% एवं 30% योगदान को 40% करने का लक्ष्य रखा है. ऐसा करने से पूरे विश्व में भारत की स्थिति उद्योग के क्षेत्र में मजबूत होगी एवं विकासशील से विकसित देशों में भारत जा पाएगा. परंतु इसके लिए सबसे अहम भूमिका भारतीय बैंकिंग व्यवस्था होगी. बैंकों के ही माध्यम से इन उद्योगों को किसी भी प्रकार का ऋण या आर्थिक सहायता दी जा सकती है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में सरकारी बैंकों द्वारा 3.92 लाख करोड़ का ऋण (मुद्रा) वितरित किया गया. यह विशालकाय कार्य सिर्फ बैंक एवं बैंक कर्मियों के ही कारण संभव हो पाया.

आधारित संरचना में बैंकों का योगदान : विश्व शक्ति बनाने के लिए आधारित संरचना अर्थात् इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है. ऋण के रूप में जरूरतमंदी को देती है. इस ऋण पर ब्याज से बैंकों को फायदा होता है एवं बाकी राशि जमाकर्ताओं को बैंक वापस कर देता है. परंतु यदि ऋण की राशि (असल एवं ब्याज) बैंक को वापस ही न मिले तो बैंक दिवालिया भी घोषित हो सकता है. विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अनिल अंबानी - यह सब वे नाम है जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए बैंकों से करोड़ों रुपए कर्ज लिए और चुका न पाए. कई तो विदेश फरार हो गए. यह अरबों की रकम यदि बैंकों को वापस मिल जाए तो भारत, बैंकों के माध्यम से इस पूंजी का उत्पादक इस्तेमाल कर सकता है. रिज़र्व बैंक के 2020 के आंकड़े कहते है कि वित्तीय वर्ष 2018-20 में भारत के सरकारी बैंकों का कुल एन.पी.ए. लगभग 6.8 ट्रिलियन रुपए है. अकेले सच तो यही है कि आम जन में लोन न चुका पाने का डर है ही नहीं. कुछ लोग ऋण को अपना अधिकारी समझते हैं. वे यह भूल जाते हैं कि ऋण चुकाना उनकी जिम्मेदारी है. अत: सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे ऋण वापसी के प्रति लोगों में जिम्मेदारी का भाव आए एवं बैंक दिवालिया होने से बचे.

जालसाजी : भारतीय बैंक जहां लोगों को नकदी, लाकर सुविधा, क्लियरिंग ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वहीं इस प्रक्रिया में कई बार खुद जालसाजी का शिकार हो जाते है. कई बार ऋण देने की प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज आदि के कारण लोन खराब हो जाते हैं जिसके लिए बैंक कर्मियों को जिम्मेदार माना जाता है और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है. यही नहीं कैश के लेन देन में कुछ लोग बैंक में फर्जी नोट भी शाखा में जमा कर देते हैं जिसके लिए भी कर्मचारी को जिम्मेदार माना जाता है.

इसके लिए बैंक की प्रत्येक शाखा में नोट चेकिंग मशीन व चेक के जांच के लिए यू.वी. लैम्प उपलब्ध कराना चाहिए.

जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है ये लोगों को डिजिटल बैंकिंग में मदद तो कर ही रही है, पर इस तकनीक से जालसाजी के तरीके भी बढ़ गए है. जैसे- ऑनलाइन खातों से पैसा निकाल लेना, ए.टी.एम. क्लोन करके पैसे का हेर-फेर आदि.

इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करना भारत के आई.टी. प्रोफेशनल्स को इस तरह की जालसाजी के तरीके को रोकने के लिए अलग विभाग भी बनानाचाहिए.

बैंक कर्मियों में असंतुष्टि : किसी भी व्यवस्था को सफल बनाने में सबसे अहम होता है. उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी. यदि कर्मचारी खुशी और संतुष्टि के साथ काम करेंगे तो निस्संदेह वह व्यवस्था सफल रहेगी. परंतु हाल के दिनों में बैंक कर्मियों में व्याप्त असंतुष्टि खतरे की घंटी है. चाहे जन-धन खाते खुलवाना हो, आधार लिंक करना हो, लोगों का जीवन बीमा करना हो, ऋण वितरित करना हो या अन्य कोई भी कार्य हो, बैंकों ने काफी हद तक और पूरी मेहनत से किया है. इस कार्य की प्रगति देश की जी.डी.पी. और मजबूत होती अर्थव्यवस्था में सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में झलकती भी है. लेकिन बैंक आज स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. देखा जा रहा है कि बैंक शाखाओं खासकर ग्रामीण शाखाओं में जहां 200-300 लोगों की भीड़ नियमित आती है वहां मात्र 3-4 स्टाफ कार्यरत है. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के ऊपर काम की अधिकता का दबाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है. कहने को बैंक का समय 9.45 से 4.45 है परंतु शायद ही कोई शाखा 4.45 पर बंद होती हो. कई बार काम की अधिकतम एवं लंबित कार्यों के कारण अवकाश के दिन भी कर्मियों को शाखा आना पड़ता है. ऐसी स्थिति में बैंक कर्मचारियों का न ही कोई व्यक्तिगत और न ही पारिवारिक जीवन रह पाता है. सबसे दुख की बात तो यह होती है कि उच्च अधिकारियों द्वारा कभी-कभी बहुत ही बुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है; अपमानित करना और अपने से कनिष्ठ के ऊपर काम और जिम्मेदारी का बोझ लाद देना आज कल बैंकों में सामान्य बाता है. किसी महिला कर्मचारी की अस्मिता के यह और भी असहनीय है.

सिर्फ उच्चाधिकारी ही नहीं सामान्य जन भी शाखा में कम स्टाफ व अन्य दिक्कतों के कारण अपना कार्य तुरंत न हो पाने कारण बैंक कर्मचारियों से उलझता है व गाली गलौज तक कर लेता है.

ऐसी स्थिति में बैंक का कार्य सुचारू रूप से करना असंभव हो जाता है.

न कोई किसी का मित्र है ओर न शत्रु. संसार में व्यवहार से ही लोग मित्र ओर शत्रु होते रहते हैं - नारायण पंडित

प्रबंध तंत्र को एक ऐसी विशेष व्यवस्था व आचार संहिता बनानी चाहिए जिससे कि कोई भी कर्मचारी अपने कनिष्ठ कर्मचारी सं बुरी तरह व्यवहार न कर सकें व सबको समान इज्जत मिले. नैतिक रूप से यही सही है. इतिहास गवाह रहा है कि जिस व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है वे सफल रही है. अत: भारतीय बैंकिंग को सफल बनाने के लिए पहले उसको नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना होगा.

भाषा संबंधी समस्या : भारत के विस्तृत क्षेत्रफल में अनेक भाषाएं बोली जाती है. अलग-अलग क्षेत्रों की भाषा और रहन-सहन अलग-अलग होता है. ऐसे में यदि उदाहराणार्थ - यू.बी. के हिन्दी भाषी व्यक्ति को आंध्रप्रदेश के तेलगु भाषी क्षेत्र में भेज दिया जाए तो क्या वो काम कर पाएगा. न ही वह लोगों से वार्तालाप कर पाएगा और न ही उनकी बात समझ कर उनकी समस्या का निस्तारण कर पायेगा. इसीलिए अलग-अलग क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में नियुक्ति वहां की भाषा के जानकार को ही रखना चाहिए.

भारतीय बैंकिंग का भविष्य : भारतीय बैंकिंग सरकार, प्रशासन और आम जनता के बीच पुल का कार्य करती है. सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अधिकतर कदम बैंक से होकर ही यथार्थ में उतरते हैं. बैंकिंग के कारण जो सहायता सरकार निचले तबके के लोगों तक पहुंचाती है वह बिना किसी बिचौलिए के सीधे पब्लिक के खाते में और खाते से जेब में जाता है. यदि भारतीय बैंकिंग में कुछ जरूरी सुधार किये जाए और उसकी जटिलताओं का उचित समाधान किया जाए तो निस्संदेह भारतीय बैंकिंग विश्व की सबसे मजबूत व्यवस्था बन कर उभरेगी.

विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में करोड़ों लोगों के खाते का संचालन, करोड़ों लोगों को पूंजी उपलब्ध कराना एवं उन खातों में वसूली करना कोई मामूली संस्था नहीं कर सकती. भविष्य में बैंकिंग को और आसान करने के लिए और जन-जन तक पहुंचाने के लिए अब डिजिटल बैंकिंग पर विशेष महत्व देना होगा. सरकार को अब अनिवार्य रूप शहर के 80% लेनदेन और अर्द्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के 50% लेनदेन को डिजिटल करने का लक्ष्य रखना चाहिए. इसके लिए हाई स्पीड नेट व भारतीय एप्स को बढ़ावा देना चाहिए. इससे न सिर्फ बैंकों में भीड़ कम होगी बल्कि कम समय में बड़े-बड़े लेनदेन हो जाएंगे. लोन को भी ऑनलाइन करके जनता के लिए आसान करना चाहिए. अनिवार्य न करने के कारण अभी भी अधिकतर बैंकों में भीड़ रहती है व काम का बोझ बढ़ता है.

भारतीय बैंकिंग को अब एक और छलांग लगाकर विश्व के दूसरे देशों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए. सरकार को ऐसी वित्तीय संस्था खोलनी चाहिए जो सिर्फ विदेशों मे चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भागीदारी सुनिश्चित करें और दूसरे देशों के मजबूत बैंकों के साथ साझेदारी में नए औद्योगिक उपक्रम को बढ़ावा दें.

परंतु यह सब कदम उठाने के साथ सरकार और रिज़र्व बैंक को जालसाजी रोकने के लिए और बैंक कर्मचारी को बैंक की कार्य प्रक्रिया एवं एक अच्छा माहौल देकर संतुष्ट भी रखना चाहिए.

यदि इस तरह के कदम सरकार और प्रशासन तंत्र उठाए तो भारतीय बैंकिंग पूरे विश्व में न सिर्फ अग्रणी रहेगी बल्कि पूरे विश्व की वित्तीय संस्थाओं का मार्गदर्शन भी कर पाएगी.

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना

जंग-ए-आजादी में गोरखपुर की भूमिका

- शुभ लक्ष्मी शर्मा
राजभाषा अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

"वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं,
वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं।
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है,
जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है"

गोपाल प्रसाद व्यास जी की ये पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि भारत की आजादी के लिए 1857 से 1947 के बीच स्वतंत्रता का सपना सँजोये क्रांतिकारियों और शहीदों ने अपना तन-मन-धन सर्वस्व न्योछावर कर दिया और देश को आजाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत की धरती पर जितनी देशभक्ति और मातृ-भावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। देश के उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में देश के इतिहास के साथ-साथ चलता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, नेपाल की सीमा के पास, गोरखपुर जिला है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। गोरखपुर जिले की सीमाएं पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर से, पश्चिम में संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर से तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ तथा अंबेडकरनगर से लगती है। गोरखपुर का नाम जंग-ए-आजादी में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यहां के लोगों ने 1857 की क्रांति से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक में देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। तरकुलहा देवी मंदिर में 1857 की क्रांति से जुड़े शहीद बंधु सिंह की वीरता के किस्से गूंजते हैं तो चौरीचौरा शहीद स्थल ने स्वतंत्रता संग्राम की एक बारगी दिशा ही बदल कर रख दी थी। डोहरिया कलां में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोरखपुर के आजादी के दीवानों ने ब्रिटिश हुकूमत से सीधा मोर्चा लिया और देश के लिए शहीद हो गए थे। महान क्रांतिकारी पं. राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत इसी गोरखपुर में हुई थी। खूनीपुर मोहल्ले का तो नाम ही आजादी के लिए खून बहाने से मिला। आज हम आजादी के 75 वर्ष अर्थात अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस सुअवसर पर हम अपने देश की आजादी की स्वतंत्रता क्रांति में अपने योगदान द्वारा आजादी हासिल कराने में गोरखपुर की भूमिका को याद करें और उन आजादी के परवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अपनी जान न्योछावर करके हमें गर्व की अनुभूति कारवाई।

चौरीचौरा (स्वतंत्रता आंदोलन का रुख मोड़ दिया)

गोरखपुर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चौरीचौरा, जहां घटी एक घटना ने एक बार में ही स्वतंत्रता आंदोलन का रुख मोड़ दिया था। दो वर्ष से चल रहे असहयोग आंदोलन को इसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। पांच फरवरी, 1922 को गोरखपुर के चौरीचौरा में होने वाला यह कांड शायद देश का पहला ऐसा कांड है, जिसमें पुलिस की गोली खाकर जान गंवाने वाले आजादी के परवानों के अलावा गुस्से का शिकार बने पुलिस वाले भी शहीद माने जाते हैं। पुलिसवालों को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए शहीद माना जाता है तो आजादी की लड़ाई में जान गंवाने वालों को सत्याग्रह के लिए।

सन 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए असहयोग का बिगुल फूंक दिया। गांधीजी की शर्त थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। आंदोलन पूरे रौ में था, उसी दौरान पांच फरवरी, 1922 को चौरीचौरा के भोपा बाजार में सत्याग्रही इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे थे। तत्कालीन थानेदार ने जुलूस को अवैध घोषित किया और उसे रोकने के क्रम में एक सिपाही ने एक सत्याग्रही की गांधी टोपी को पांव से रौंद दिया। उसके बाद सत्याग्रही आक्रोशित हो गए। विरोध हुआ तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 11 सत्याग्रही शहीद हो गए जबकि चार

पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो - शब्सतरी

दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। गोली खत्म हुई तो पुलिसकर्मी थाने की ओर भागे। साथियों पर गोली चलने से नाराज सत्याग्रहियों ने उन्हें थाने में जाते देखा तो पूरे थाने को ही घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इससे थाने में मौजूद 23 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। बाद में इसके लिए 19 सत्याग्रहियों को दोषी करार देते हुए फांसी दी गई। घटना की जानकारी जब गांधीजी को मिली तो उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का फैसला ले लिया। उसके बाद यह स्थल इतिहास के पन्ने में इस तरह दर्ज हो गया कि आजादी की लड़ाई की चर्चा इसके बिना पूरी ही नहीं होती।

चौरी-चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। इनमें से 151 लोग फांसी की सजा से बच गये। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई, 1923 के दौरान फांसी दे दी गई। इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई।

स्मारक

- अंग्रेज सरकार ने मारे गए पुलिसवालों की याद में एक स्मारक का निर्माण किया था, जिस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जय हिन्द और जोड़ दिया गया।
- स्थानीय लोग उन 19 लोगों को नहीं भूले जिन्हें मुकदमे के बाद फाँसी दे दी गयी थी। 1971 में उन्होने 'शहीद स्मारक समिति' का निर्माण किया। 1973 में समिति ने झील के पास 12.2 मीटर ऊँची एक त्रिकोणीय मिनार निर्मित की जिसके तीनों फलकों पर गले में फाँसी का फन्दा चित्रित किया गया।
- बाद में सरकार ने उन शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनवाया। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम खुदे हुए हैं जिन्हें फाँसी दी गयी थी (विक्रम, दुदही, भगवान, अब्दुल्ला, काली चरण, लाल मुहम्मद, लौटी, मादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रूदाली, सहदेव, मोहन, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम)। इस स्मारक के पास ही स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी बनाया गया है।
- क्रांतिकारियों के याद में कानपुर से गोरखपुर के मध्य में 'चौरी-चौरा एक्सप्रेस' नामक एक रेलगाड़ी चलाई गई।

डोहरिया कलां (में नौ रणबांकुरों ने सीने पर खाई थी गोलियां)

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ऐलान पर 'करो या मरो' का नारा लगाते हुए 23 अगस्त, 1942 को सहजनवां के डोहरिया कलां में आजादी के दीवानों ने ब्रिटिश हुकूमत से सीधा मोर्चा लिया था। नौ रणबांकुरों ने सीने पर गोलियां खाई थी और देश के लिए शहीद हो गए। 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका आह्वान सहजनवां के डोहरिया कलां तक भी पहुंचा। आजादी के दीवानों ने भारत माता का नारा लगाते हुए आंदोलन से सीधे जुड़ने की तैयारी शुरू कर दी। 23 अगस्त की तारीख मुकर्रर हुई, क्षेत्र में इसके लिए बिगुल फूंकने की। तय समय पर भारी तादाद में लोग जुटे। जब लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाना शुरू किया तो तत्कालीन कलेक्टर एमएस मास और उनके अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने इस आंदोलन पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की। बावजूद इसके जब विरोध का सिलसिला आगे बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ ने उसका जवाब ईंट-पत्थर से दिया। ऐसे में पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसका शिकार होकर नौ लोग वहीं शहीद हो गए जबकि 23 गंभीर रूप से घायल हुए। सिर्फ इतना ही नहीं अंग्रेजों ने पूरे डोहरिया गांव में आग लगा दी और गांव वालों पर जमकर जुल्म ढाया। देश आजाद हुआ तो यह स्थल आजादी की लड़ाई के इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया।

गोरखपुर जेल

आजादी की जंग के इतिहास में गोरखपुर का नाम जिन घटनाओं के लिए दर्ज है, उनमें पं. राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत प्रमुखता से शामिल है। 19 दिसंबर, 1927 को गोरखपुर जेल की कोठरी नंबर सात में उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। वह फांसी घर तो जेल में आज भी मौजूद है ही, लकड़ी का फ्रेम और लीवर भी आज तक सुरक्षित है। बिस्मिल से जुड़े जेल के दस्तावेज और बिस्मिल के सामानों की सूची भी जेल में संरक्षित है। जेल के अंदर बनाया गया बिस्मिल स्मारक और स्मृति उपवन उनके प्रति राष्ट्र के समर्पण की तस्दीक है। शाहजहांपुर के रहने वाले पंडित बिस्मिल को फांसी काकोरी में खजाना लूटने को लेकर हुई।

मोती जेल (क्रांतिकारियों को सजा के लिए बनी थी)

बसंतपुर मोहल्ले में लालडिग्गी के सामने मौजूद एक जर्जर इमारत वहां

जाने वाले हर उस व्यक्ति का ध्यान खींचती है, जिन्हें अपनी विरासत से लगाव है। कम ही लोगों को पता होगा कि वह जर्जर इमारत कभी मोती जेल के नाम से मशहूर थी, जिसका इस्तेमाल अंग्रेज क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए किया करते थे। इस परिसर में एक कुआं भी है, जिसे कभी खूनी कुआं कहा जाता था। बताते हैं कि अंग्रेज कुएं का प्रयोग फांसी देने के लिए करते थे। इसका सर्वाधिक प्रयोग अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दौरान किया। क्रांतिकारी शाह इनायत अली को फांसी इसी कुएं में दी गई थी।

घंटाघर (क्रांतिकारियों की शहादत का गवाह)

शहर के व्यस्ततम उर्दू बाजार में खड़ी मीनार सरीखी इमारत घंटाघर अपने-आप में तमाम क्रांतिकारियों की शहादत और उनकी गौरव-गाथाओं को समेटे हुए है। इसके निर्माण के इतिहास में जाएं तो आज जहां घंटाघर है, 1857 में वहां एक विशाल पाकड़ का पेड़ हुआ करता था।

इसी पेड़ पर पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अली हसन जैसे देशभक्तों के साथ दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। 1930 में रायगंज के सेठ राम खेलावन और सेठ ठाकुर प्रसाद ने पिता सेठ चिगान साहू की याद में इसी स्थान पर एक मीनार सरीखी ऊंची इमारत का निर्माण कराया, जो शहीदों को समर्पित थी। उस इमारत की पहचान आज घंटाघर के रूप में है।

खूनीपुर (में बहा था सैकड़ों क्रांतिकारियों का खून)

उर्दू बाजार के दायरे में आने वाले मोहल्ले खूनीपुर का नाम ही इस बात की तस्दीक है कि यह महज एक मोहल्ला ही नहीं बल्कि तारीख है जंग-ए-आजादी की। इस इलाके में रहने वाले बुजुर्गों के मुताबिक हिंदुस्तान की पहली जंग-ए-आजादी 1857 में इस मोहल्ले के लोगों ने बढ़चढ़ भागीदारी की। जब अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने वहां जमकर खून-खराबा किया। मोहल्ले में इतना खून बहा कि मोहल्ले की पहचान ही खून शब्द से जुड़ गई। यहां शहीदों की मजारों की बड़ी तादाद में मौजूदगी मोहल्ले के नाम की पीछे के ऐतिहासिक तथ्य की गवाही है।

तरकुलहा देवी (को चढ़ती थी अंग्रेजों की बलि)

शहर से 20 किलोमीटर दूर देवरिया रोड पर फुटहवा इनार के पास मंदिर मार्ग का मुख्य द्वार है जहां से लगभग डेढ़ किमी पैदल, निजी वाहन या ऑटो से चलकर मंदिर है। मौजूद तरकुलहा देवी मंदिर में जंग-ए-आजादी की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की बलि चढ़ती थी। दरअसल डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह मां के बहुत बड़े भक्त थे। जब पूरे देश में आजादी की पहली हुंकार उठी, गुरिल्ला युद्ध में माहिर बाबू बंधू सिंह उसमें शामिल हो गए। वह अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध लड़ते और मां के चरणों में उनकी बलि चढ़ा देते थे। जल्द ही एक गद्दार ने बंधु सिंह के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद अंग्रेजों ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया और 12 अगस्त, 1857 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया।

बाबू बंधु सिंह

जनश्रुति के अनुसार अंग्रेजों ने बंधु सिंह को जैसे ही फांसी के फंदे पर लटकाया, फासी का फंदा टूट गया। यह क्रम लगातार सात बार चला, जिसे देख कर अंग्रेज आश्चर्यचकित रह गए। तब बंधु सिंह ने तरकुलहा माँ से अनुरोध किया कि हे माँ! मुझे अपने चरणों में ले लो। आठवीं बार बंधु सिंह ने स्वयं फांसी का फंडा अपने गले में डाला। इसके बाद उन्हें फांसी दी गयी। कहा जाता है कि जैसे ही बंधु सिंह फांसी पर लटके, उसी समय तरकुलहा देवी के पीछे स्थित तरकुल के पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट कर गिर गया, जिससे खून के फव्वारे निकलने लगे। बाद में भक्तों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया।

आजादी का अमृत महोत्सव

अमृत समान है उत्सव अपना, क्यों है नूतन क्यों है खास ?
आजादी के पचहत्तर वीं वर्षगांठ पर, सहसा याद आया इतिहास।

बनियाँ बनकर गोरा आया, जयचंदों ने उसे बसाया
फूट डाल शासन करने में तेज, कहते हैं उसको अंग्रेज।
बिखरा राष्ट्र, बिखरा समाज, बिखर गये सब भाई-भाई,
खो गया पुरुषार्थ अवाम का, "राष्ट्रवाद" की सुध बिसराई
"राजवंशों" में युद्ध करवाकर, देश पर "लोमड़ी-दृष्टि" गड़ाकर,
गर्भित लक्ष्य था "उपनिवेश", गुलाम बना गया भारत देश।

दो सौ वर्ष शोषण देश का, पराधीन नकाब भेष का
दासत्व जब जान पर बन आई, जनता को अब समझ में आई
जनता गयी अब नींद से जाग, सुलग उठी स्वाधीनता की आग
बढ़ने लगी सत्ता का अभिद्रोह, अंकुर बना १८५७ का सैनिक विद्रोह
भूले नही भूलती जालिंवाला बाग, जहाँ हुआ था नर-संहार
सन् बयालीस में आया सन्देश, फिरंगी छोड़ दो भारत देश।

गाँधी,सुभाष ने की अगुआई, सम्पूर्ण क्रांति की राह दिखाई
दंश-विभाजन का झेलकर, सन् सैंतालिस में आज़ादी पाई।

आज वक्त है गुणन-मनन का, "राष्ट्र भावना" पर चिंतन का
कैसे कल थे कैसा हैं आज, कितना बदला देश, कितना सामाज ?
कितना चढ़ा "विकास का सूरज, कितना बढ़ा समाज में "धीरज" ?
क्या जाति-धर्म की खाई पाट चुके हम,
बेरोज़गारी का आकार हुआ कम ?
क्या नारी का समाज में है सम्मान, बच्चों के मुख पर है मुस्कान ?
जनता सुखी हो और देश सबल, वरना आज़ादी है निष्फल।

आएं आजादी के इस अमृत उत्सव पर, अंतर्मन में यह विधान करें हम
आत्मनिर्भर का संकल्प से लेकर,
एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संधान करें हम।

- किशोर कुमार दास
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

धुल नहीं पाते मन के मैल

धुल नहीं पाते हैं मन में बैठे मैल
गंगा-जमुना के स्वच्छ धार से

मन के मैल धुल जाते हैं
अंतर्मन के पश्चाताप से

मन में झाँक के देख लो
मिलेंगे ज्ञान प्रकाश और उजाला
फिर उस प्रकाश में छाये न अन्धेरा
कुटिलता को हटाकर पी लो स्नेह का प्याला

बैठे हैं मन में जो अहम, अहंकार का मैल
वह मीठी वाणी से धुल जाती है
खुल जाए जब मन की आँखें तो
हृदय में दिव्य ज्योति जगा जाती है

किसी से हो न तुम्हें शिकवा शिकायत
ले लो तुम सबके मन की दुआएं
धुल जायेंगी तेरी सारी गुनाहें
तेरे हर पथ पर सफलता के फूल खिल जाएँ

- आभा सिन्हा
वरिष्ठ प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय, पटना

काव्यकुंज

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कोरोना

कोरोना के डर से
न निकलो तुम घर से
मन तुम बलवान हो
पर इस वायरस से तुम अंजान हो
पूरी दुनिया हिल गया है इसके कहर से
कोरोना के डर से
न निकलो तुम घर से

ये दुश्मन बड़ा घातक है
ये फैला रहा चारो ओर आतंक है.
ये आता कहीं भी अचानक है
कोई देख न पाया है इसे अपनी नज़र से
कोरोना के डर से
न निकलो तुम घर से
ये बीमारी नहीं महामारी है
ये बड़ा कठोर बड़ा अत्याचारी है
ये फैलता है बस छूने भर से
कोरोना के डर से
न निकलो तुम घर से

मुंह पर मास्क हाथों को सेनेटाइज करें
इससे बचने के लिए यही एक्सरसाइज करें
वरना ये जलाके रख देगा अपनी लहर से
कोरोना के डर से
न निकलो तुम घर से

- शंभू प्रसाद वर्मा
एसडब्ल्यूओ
चौधरी टोला शाखा

तू ज़रूरी है

तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है
दिल के लिए तो धड़कनों से ज़्यादा,
तू ज़रूरी है.....

एक हंसीं, एक मुस्कराहट, एक ख़्वाब है तू
मेरी ज़िंदगी, मेरी आसमां, मेरा महताब है तू

तेरे बिना मेरी हर मन्नत अधूरी है
दिल के लिए तो धड़कनों से ज्यादा
तू ज़रूरी है.....

ज़िंदगी बेरंग है एक तेरे न होने से,
हर खुशी कहीं खो सी गयी, एक तेरे ही खोने से

आँखों को सूना कर गए अब तो हर चीज़ अधूरी है
दिल के लिए तो धड़कनों से ज्यादा
तू ज़रूरी है.....

- शिल्पी कुमारी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

स्थापना दिवस

बैंक के 111 वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम वी राव, साथ में हमारे बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला की सुपौत्री सुश्री पीलू हकीम, श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक तथा श्री राजीव पुरी, कार्यकारी निदेशक.

बैंक के 111वें स्थापना दिवस के अवसर आयोजित कार्यक्रम में फील्ड महाप्रबंधक श्री जे.एस.साहनी, उप आंचलिक प्रबंधक श्री आर.जयकृष्णन एवं मुख्य लेखा परीक्षक श्री चौहान सहित अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

बैंक के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर फील्ड महाप्रबंधक श्री जे. एस.साहनी अहमदाबाद के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एल.एन. सुरेश उपस्थित थे.

स्थापना दिवस 2021 चिचोंडो पाटील शाखा, अहमदनगर क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक की 111वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की कुछ झलकियां

बैंक के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर लाल दरवाजा, अहमदाबाद शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में फील्ड महाप्रबंधक श्री जे.एस.साहनी द्वारा केक काटकर कार्यक्रम का उदघाटन किया. इस अवसर पर उप आंचलिक प्रबंधक श्री आर.जयकृष्णन एवं अहमदाबाद के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एल. एन. सुरेश सहित शाखा के समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दि.21.10.2021 को सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक देवरिया श्री सुशील कुमार उपाध्याय, की अध्यक्षता में आयोजित सतर्कता जागरुकता सप्ताह कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों एवं स्टाफ सदस्यों को सतर्कता का महत्व बताते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक. साथ में श्री मनोज कुमार सिन्हा, मु.प्र. एवं अन्य स्टाफ सदस्यगण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाडा में आयोजित कार्यक्रम मुख्य अतिथि सीएसपी श्री मोतीलाल कुशवाह, साथ में नगर निगम आयुक्त, छिंदवाडा, श्री देबजीत मित्रा, मुख्य प्रबंधक, श्री प्रकाश भंडारे अग्रणी जिला प्रबंधक, श्री सी.नंदेश्वर, मुख्य प्रबंधक

सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्षे.का.जयपुर

क्षे.का.जयपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ लेते हुए स्टाफ सदस्य

सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अमृतसर क्षेत्र की तरणतारण शाखा के तत्वावधान में स्थानीय कॉलेज में विद्यार्थियों हेतु निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्षे.का.जयपुर

दि. 28.10.2021 को सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एल.बी. झा की अगुवाई में क्षेत्रीय कार्यालय के सभी स्टाफ सदस्य मुख्य शाखा के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय से विजय चौरहा होते हुए गणेश चौराहे से टाउन हॉल होते हुए पुन: क्षेत्रीय कार्यालय तक आयोजित रैली में सहभागिता की.

क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा आयोजित सतर्कता जगरुकता सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में शुभ लक्ष्मी शर्मा को प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री परविंदर सिंह भाटिया, मुख्य प्रबंधक, साथ में श्री विनोद कुमार तिवारी एवं अन्य अधिकारी गण.

आउट रीच कार्यक्रम

हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम वी राव महोदय का जयपुर क्षेत्र को भेंट दौरान आयोजित आउटरीचकार्यक्रम का आयोजन

हमारे माननीय कार्यकारी निदेशक महोदय श्री आलोक श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में छिंदवाडा क्षेत्र द्वारा आउट रिच कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

क्रांती चौक औरंगाबाद शाखा के मुख्य शाखा प्रबंधक श्री संजय कुमार को पुणे अंचल की व्यवसाय समीक्षा बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए हमारे माननीय कार्यकारी निदेशक महोदय श्री राजीव पुरी जी के करकमलों से प्रमाणपत्र प्रदान किया गया.

दिनांक 08 नवंबर 2021 को छिंदवाडा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय कार्यपालक निदेशक श्री आलोक श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में एवं श्री सौरभ सुमन, कलेक्टर छिंदवाडा के मुख्य आतिथ्य में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये.

पुणे अंचल द्वारा हमारे माननीय कार्यकारी निदेशक महोदय श्री राजीव पुरी जी की अध्यक्षता में आयोजित ग्राहक बैठक, साथ में फील्ड महाप्रबंधक श्री मुटरेजा जी.

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दि. 25.11.2021 को श्रीमती नमिता रॉय शर्मा, महाप्रबंधक (रिटेल एवं कंज्यूमर लेंडिंग), केंद्रीय कार्यालय मुम्बई की विशिष्ट आतिथ्य में क्रेडिट आऊटरीच कार्यक्रम में रु.20.14 करोड़ का ऋण वितरण एवं स्वीकृति जनप्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को देते हुए श्री सुशील कुमार उपाध्याय, क्षेत्रीय प्रबंधक, देवरिया. साथ में हैं श्री मनोज सिन्हा, मुख्य प्रबंधक, श्री राकेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक श्रीमती रजनी व अन्य अधिकारीगण.

हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानियों ने जो विरासत हमें प्रदान की है उसे हम अगली पीढी को सुरक्षित प्रदान करें.

राजभाषा समाचार

माननीय श्री राजीव पुरी जी, कार्यकारी निदेशक महोदय, श्री वी वी नटराजन, फील्ड महाप्रबंधक तथा श्री रजनीश शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा राजभाषा पुस्तिका का विमोचन.

ई पत्रिका सेन्ट्रल वाणी को वर्ष 2019-20 के लिए नराकास दिल्ली द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया

दिनांक 23.12.2021 को आयोजित नोयडा बैंक नराकास बैठक में हमारी नोयडा सेक्टर 15 शाखा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को 2020-21 के लिए नराकास जयपुर द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया

दिनांक 22.12.2022 को आयोजित दिल्ली बैंक नराकास की बैठक में आंचलिक कार्यालय की ई पत्रिका सेंट्रल वाणी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ

बैंक नराकास,अहमदाबाद द्वारा आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. प्रथम पुरस्कार अहमदाबाद अंचल के फील्ड महाप्रबंधक श्री जे. एस.साहनी को नराकास अध्यक्ष एवं उपनिदेशक सुश्री सुस्मिता भट्टाचार्य द्वारा प्रदान किया गया.

कल बैंक नराकास की बैठक में अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय को वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उप निदेशक सुश्री सुस्मिता भट्टाचार्य से शील्ड ग्रहण करते हुए अंचल के फील्ड महाप्रबंधक श्री जे. एस. साहनी.

नराकास आगरा (बैंक) के तत्वाधान में क्षेत्रीय कार्यालय आगरा द्वारा स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 2 दिसम्बर 2021 को किया गया.

सभी उच्चतम सनातन सत्य आत्मा के सत्य हैं - अरविंद

बैंक के इर्द-गिर्द

हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम वी राव महोदय का सांभर क्षेत्र में ग्राहक संपर्क कार्यक्रम के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम.

दिनांक 08 नवंबर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाडा में आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय कार्यपालक निदेशक श्री ए.के.श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ई.दिवी कुमार

व्यवसाय समीक्षा बैठक के दौरान माननीय श्री राजीव पुरी जी, कार्यकारी निदेशक महोदयद्वारा पुरस्कार वितरण, साथ में श्री वी वी नटराजन, फील्ड महाप्रबंधक चंडीगढ तथा क्षेत्रीय प्रबंधक अमृतसर उपस्थित है.

ग्राहक बैठक के आयोजन पर लिए गए छाविचित्र में माननीय श्री राजीव पुरी जी, कार्यकारी निदेशक महोदय के साथ श्री वी वी नटराजन, फील्ड महाप्रबंधक चंडीगढ उपस्थित है.

21.10.2021 को शाखा इंदुपुर, क्षेत्रीय कार्यालय देवरिया में कियोस्क पासबुक प्रिंट मशीन का उद्घाटन करते हुए श्री सुशील कुमार उपाध्याय, क्षेत्रीय प्रबंधक, देवरिया, श्री मनोज कुमार सिन्हा, मुख्य प्रबंधक, श्री गौरव राय, शाखा प्रबंधक, इंदुपुर व शाखा के स्टाफ

दुर्गापुर क्षेत्र द्वारा आयोजित ऋण मेला में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री महेंद्र सिंह हितग्राही को संस्कृति पत्र प्रदान करते हुए

अहमदनगर क्षेत्र की संगमनेर शाखा में पासबुक प्रिंटींग मशीन का लोकार्पण

भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष

भारत की आजादी का अमृत महोत्सव – पचहत्तर (1 से 75 तक) पदचिन्ह...

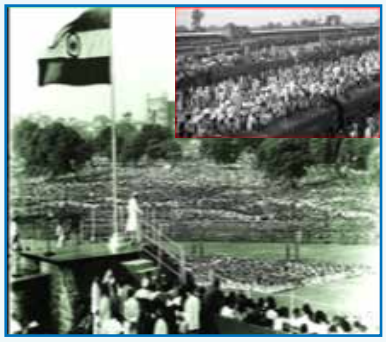

1947 - स्वतन्त्रता का प्रात:काल

भारत डेढ़ सौ वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन के प्रकोप से आजाद हुआ. स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के सपने साकार हुए. हालांकि इस सपने के पूरा होने के साथ ही देश को विभाजन के बुरे सपने का भी सामना करना पड़ा. भारत-पाकिस्तान के बाद की हिंसा में दो लाख से अधिक लोगों की जान चली गई और 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए.

1948 - गांधी जी की हत्या

एक तरफ जहां बंटवारे के घाव भर रहे थे वहीं कश्मीर समेत देश की कुछ संस्थाओं के विलय का कार्यक्रम भी चल रहा था. उसी तरह महात्मा गांधी की हत्या से देश शोक के सागर में डूब गया था.

आई आई टी की स्थापना

तत्कालीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), तकनीकी शिक्षा के लिए देश की अग्रणी संस्था, तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय (IIT रुड़की) में सिविल इंजीनियरिंग के थॉमसन कॉलेज में परिवर्तन.

1950 - भारतीय संविधान

भारतीय संविधान का निर्माण, जो ऐसे खंडित भारत के एकीकरण के लिए संविधान की रूपरेखा निर्धारित करता है. सही मायने में भारत एक गणतंत्र बन गया.

1951 - पहला चुनाव

पहला लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आजादी के बाद और भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुआ था. पहले चुनाव में 45.7 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया.

रेलवे का राष्ट्रीयकरण

रेलवे का राष्ट्रीयकरण, जिसके पास देश में सार्वजनिक परिवहन का एक विशाल नेटवर्क है और अभी भी आम आदमी को मुफ्त यात्रा की गारंटी देता है, भारतीय रेलवे आज दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है.

प्रथम पंचवर्षीय योजना

देश के आर्थिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, मुख्य रूप से सिंचाई एवं ऊर्जा, कृषि, परिवहन की प्रगति के लिए प्रावधान.

1952 पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक

मराठमौला पहलवान खाशाबा जाधव ने इस साल हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था. यह भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था.

पहली टेस्ट जीत, सीरीज जीत

टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद पहली बार भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट जीता है. उसी वर्ष, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली श्रृंखला जीती.

परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना

मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना, जो देश के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है. बाद में उसी संस्थान का नाम बदलकर 'BARC' कर दिया गया. केवल दो वर्षों में, भारत ने एशिया में पहला अप्सरा रिएक्टर बनाया.

1955 एलआईसी और स्टेट बैंक

भारतीय बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना, उसी वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तन.

1956 - बौद्ध धर्म दीक्षा

घटना और सामाजिक स्वतंत्रता सूर्य डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सहित लाखों अनुयायियों द्वारा नागपुर में बौद्ध धर्म की शुरुआत. उसी साल 6 दिसंबर को बाबासाहेब का निधन हो गया.

राज्य पुनर्गठन अधिनियम

श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिनियम बनाया गया, जो आंध्र राज्य की मांग के लिए भूख हड़ताल पर रहते हुए मारे गए थे.

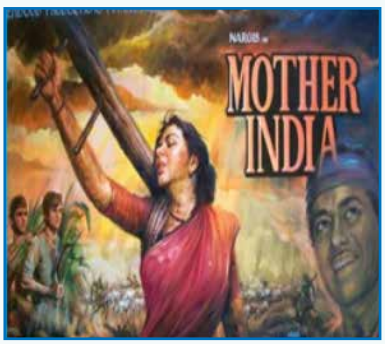

1958 - भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कार

महबूब खान निर्देशित 'मदर इंडिया' ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित, किसी भारतीय फिल्म की पहली ऑस्कर हिट जिसने दुनिया को अपने आसपास की वास्तविक दुनिया के बारे में भूल जाने पर मजबूर कर दिया.

1960 - महाराष्ट्र राज्य की स्थापना

बॉम्बे प्रांत में मराठी भाषियों के एक स्वतंत्र राज्य के लिए कई वर्षों के लंबे संघर्ष की सफलता. 106 शहीदों के बलिदान के बाद मुंबई शहर सहित महाराष्ट्र राज्य की स्थापना.

हरित क्रांति

भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

1961-62 - गोवा, पांडिचेरी

गोवा और पांडिचेरी, भारत का हिस्सा, जो ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था, क्रमशः पुर्तगाली और फ्रेंच नियंत्रण में थे. वे दोनों भारत का हिस्सा बन गए.

भारत-चीन युद्ध

सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के बीच युद्ध. मैकमोहन रेखा और प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखा को मान्यता देने से चीन का इनकार. एक महीने बाद चीन से शस्त्र प्रतिबंध. 1300 भारतीय सैनिक मारे गए और 1047 घायल हुए.

1965 - भारत-पाकिस्तान युद्ध

पाकिस्तान के 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' के कारण अप्रैल और सितंबर के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध. कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए 26,000 से 33,000 पाकिस्तानी सैनिकों के प्रयासों को भारत ने विफल कर दिया. पाकिस्तानी सेना का समर्पण.

1966 - पहली एशियाई और भारतीय मिस वर्ल्ड

भारत की रिता फारीयाने मिस वर्ल्ड का किताब जिता. पेशेसे डॉ. रिता फारीया मॉडेलिंगभी कर रही थी. उनका जन्म मुंबई मे हुआ था.

प्रथम ग्रैमी पुरस्कार

पंडित रविशंकर ने भारत को पहला ग्रैमी पुरस्कार दिया.

1969 - बैंकों का राष्ट्रीयकरण

अब बैंकों के निजीकरण की प्रवृत्ति है लेकिन उस समय 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. इसके बाद 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण आया.

इस्त्रो की स्थापना

भारत ने आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी प्रगति की है. उनका श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को जाता है. संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी.

1971 - बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष

शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का संघर्ष. मुक्ति वाहिनी की ओर से भारत ने इस संघर्ष में भाग लिया. भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया. पाकिस्तान की हार हुई और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ.

1973 - चिपको आंदोलन

देश के वन संसाधनों को बचाने के लिए यह अभिनव आंदोलन शुरू किया गया था. यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव से सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से शुरू हुआ था.

पोखरण परीक्षण
जब बुध्द मुस्कुराए .....

1974 - पोखरण 1

भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया. परीक्षण 'स्माइलिंग बुद्धा' कोड नाम के तहत आयोजित किया गया था. नतीजतन, भारत दुनिया की अग्रणी परमाणु शक्तियों में से एक बन गया है.

जयप्रकाश नारायण का आंदोलन

बिहार में छात्रों ने भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. वरिष्ठ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया.

भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर शांत रहनेवाला ही प्रसन्न रहता है - विश्वबंधु शास्त्री

1975 - भारत का पहला उपग्रह

भारत ने पहला अंतरिक्ष उपग्रह विकसित किया. महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था.

इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द

1971 के लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था. इसके चलते आपात स्थिति पैदा हो गई. आंतरिक अस्थिरता का हवाला देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी. आगामी चुनावों में, जनता पार्टी, गैर-कांग्रेसी दलों का गठबंधन, केंद्र में सत्ता में आई.

1976 - सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम

इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की पहल पर पूरे देश में सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया. इनमें से 62 लाख पुरुषों की साल के दौरान सर्जरी हुई. इन जबरन सर्जरी में दो हजार लोग मारे गए थे.

1979 - मंडल आयोग की स्थापना

देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्ययन के लिए मंडल आयोग - बी.बी. की स्थापना. मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था.

1982 - 'रंगीन' एशियाई खेल

नई दिल्ली में एशियाई खेलों का सफल आयोजन. भारत ने अपनी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की. इस प्रतियोगिता के मौके पर देश में कलर टीवी आ चुका था.

1983 - क्रिकेट विश्व कप

कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता. इस जीत के बाद भारत और विश्व क्रिकेट ने एक अलग मोड़ ले लिया.

अंतरिक्ष में भारतीय

अंतरिक्ष में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा. रूस समर्थित संयुक्त मिशन में शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला.

ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या

स्वर्ण मंदिर में छिपे सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान. स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई के प्रतिशोध में इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में पांच हजार सिख मारे गए थे.

भोपाल दुर्घटना -

भोपाल में यूनियन कार्बाइड से हवा का रिसाव. इस दुर्घटना में लगभग 3,000 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए. कई स्थायी रुप से विकलांग हो गए.

1985 शाहबानो केस

सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम धर्म के मामलों में दखल देने का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए संसद में एक कानून पारित किया था.

1986 बोफोर्स घोटाला -

स्वीडिश मीडिया की रिपोर्ट है कि भारत सरकार द्वारा स्वीडिश कंपनी से खरीदी गई बोफोर्स तोपों की खरीद में कुछ भारतीय गणमान्य व्यक्तियों को रिश्वत दी गई थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का राजनीतिक विरोध बोफोर्स कांड पर चर्चा की शुरुआत से ही शुरू हो गया था. विपक्षी समूहों ने रैली का बहिष्कार करने का आह्वान किया.

1988 - युवाओं के लिए मतदान का अधिकार -

मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है. युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था.

1989 - अयोध्या में पत्थर की नींव रखना -

तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को अयोध्या मंदिर में पत्थर रखने की अनुमति. यहीं से शुरू हुई अयोध्या की राजनीति. लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, भाजपा की हिंदुत्व केंद्रित राजनीति की शुरुआत.

वी. पी. सिंह और मंडल -

बोफोर्स कांड के बाद कांग्रेस छोड़कर जनता दल बनाने वाले वीपी सिंह ने सहयोगी दलों से लोकसभा चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने. सत्ता में आने के बाद दूसरे वर्ष में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की. इसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी.

1991 - भारत का सोना विदेश में गिरवी

तत्कालीन प्रधान मंत्री चंद्रशेखर ने भारत के सोने को विदेशों में गिरवी रखकर धन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी क्योंकि यह वित्तीय संकट के कारण भारत के खजाने को खाली करने का समय था.

राजीव गांधी की हत्या -

21 मई 1991 को भारत के सातवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आतंकवादी घटना में हत्या कर दी गई थी. इस हत्या की जिम्मेदारी श्रीलंका में सक्रिय आतंकवादी लिट्टे ने ली थी. इस घटना के बीज श्रीलंका के आंतरिक संघर्ष में छिपे हैं जो कई साल पहले से चल रहा था.

आर्थिक उदारीकरण का युग शुरू -

1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और पी.वी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया.

1992 सुरक्षा स्कैंडल -

अप्रैल में स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता के सिक्योरिटी स्कैंडल ने भारत के पूंजी बाजार पर प्रभाव को उजागर किया, जो आर्थिक उदारीकरण की राह पर है। इससे देश के पूंजी बाजार की कमियों को दूर करने के लिए एक सख्त नियामक प्रणाली की स्थापना हुई.

बाबरी, दंगे, बम विस्फोट -

6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था. इससे देश के शहरों में धार्मिक दंगे भड़क उठे. दंगे कम नहीं हुए, लेकिन मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों ने खलबली मचा दी.

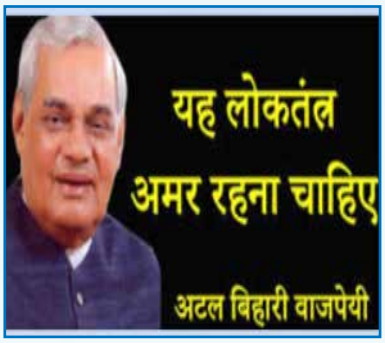

1996 - रालोआ, 13 दिन फिर वाजपेयी

1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी. लेकिन बहुमत के बिना, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 13 दिनों में ही सत्ता में आ गई.

1999 - कारगिल युद्ध

पाकिस्तान ने कश्मीर में कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की, आतंकवादियों को आगे बढ़ाया और हंगरी को भारतीय सीमा पर कब्जा कर लिया. उन्हें बेदखल करने के लिए ऑपरेशन विजय के तहत मई से जुलाई तक कारगिल युद्ध लड़ा गया था.

विमान अपहरण -

दिसंबर 1999 में, पाकिस्तान ने आतंकवादियों के माध्यम से नेपाल में एक इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया और उसे कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया. भारत सरकार द्वारा कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और अन्य कश्मीरी आतंकवादियों को कंधार को सौंपने के बाद विमान को छोड़ दिया गया था.

2001 - संसद पर हमला

लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमले किए, जिसमें दिल्ली के छह पुलिसकर्मियों सहित नौ लोग मारे गए.

2002 - गुजरात दंगे

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे. भारत के इतिहास में सबसे खराब जातीय दंगों में से एक. इस दंगों में 1044 मृत, 2500 घायल और 223 लापता पाए गए.

2005 - सूचना का अधिकार, मनरेगा

देश में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था जिसके माध्यम से नागरिक कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उसी वर्ष, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी.

2006 - परमाणु समझौता

भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण परमाणु समझौता. संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए.

2007 - पहली महिला राष्ट्रपति

देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभाताई पाटिल का चुनाव किया गया. उन्हें देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का सम्मान प्राप्त हुआ.

2008 - चांद्रयान -1

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का महत्वाकांक्षी 'चांद्रयान -1' मिशन, इस मिशन के माध्यम से देश के अंतरिक्ष मिशन को एक बड़ी प्रेरणा मिली.

अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण पदक

बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण पदक. ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय थे.

मुंबई आतंकवादी हमला

पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तोयबा से मुंबई में आतंकवादी हमला. इस हमले में कम से कम 166 लोग मारे गए थे. आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और कसाब को मौत की सजा दी गई.

2009 - आधार और शिक्षा का अधिकार

देश में लागू आधार योजना, प्रत्येक भारतीय नागरिक को बायोमेट्रिक और अन्य विवरण वाले आधार कार्ड की मुहर. उसी वर्ष, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो छह से चौदह वर्ष की आयु में शिक्षा का अधिकार देता है, लागू हुआ.

2010 - दिल्ली में राष्ट्र मंडल खेलों का आयोजन

इसका अधिकारिक बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया था. इस प्रतियोगिता में भारत ने 101 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया.

2011 - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शताब्दी

दिनांक 21.11.2011 को स्थापित देश के प्रथम स्वदेशी बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शताब्दी वर्ष.

2013 - लोकपाल आंदोलन

भ्रष्टाचार विरोधी भारत आंदोलन 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुआ. लोकपाल बिल के लिए पूरे भारत में आंदोलन चल रहे थे. दस प्रयासों के बाद बिल 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

इसे उस समय देश की 120 मिलियन की लगभग दो तिहाई आबादी को आत्मनिर्भर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था. यह 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ.

मंगल अभियान

5 नवंबर 2013 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगल पर एक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. भारत एशिया में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है.

वह मूर्खों में बड़ा मूर्ख है जो यह मानता है कि इस संसार में भारी सुख ही सुख है - समर्थ रामदास

2014 - पोलियो मुक्त

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित किया. पोलियो से पीड़ित आखिरी लड़की 2011 में पश्चिम बंगाल में पाई गई एक नाबालिग लड़की थी.

नरेंद्र मोदी नाम की आंधी

लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है. किसी गैर- कांग्रेसी पार्टी के मामले में ऐसा पहली बार हुआ है.

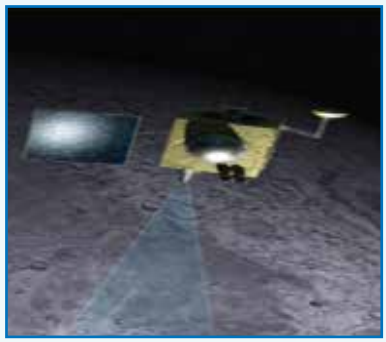

2016 - GPS सिस्टम

भारत ने अपना स्वतंत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NAVIC (भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन) लॉन्च किया.

नोटबंदी

भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की. रु.500/- और रु.1000/- के नोट रद्द कर दिए गए. उस समय करेंसी में इन नोटों की हिस्सेदारी करीब 86 फीसदी थी.

2017 - गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे देश के लिए एकमात्र अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था.

ट्रिपल तलाक प्रणाली का निरसन

23 अगस्त 2017 को, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में 'तलाक-ए-बिद्दत' की प्रथा को समाप्त कर दिया जो तत्काल तलाक देती है.

गोपनीयता एक मौलिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को इसका फैसला सुनाया.

2018 - समलैंगिकता अपराध नहीं है

समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखा था.

2019 - जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का निरसन

6 अगस्त को संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया. उसके बाद, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था.

राम मंदिर परिणाम

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि विवादित भूमि राम जी की है, इसलिए इसे राम मंदिर के लिए दिया जाना चाहिए और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ मंडल को वैकल्पिक पांच एकड़ जमीन देनी चाहिए.

पूर्णत: लॉक डाऊन

दिनांक 22 मार्च 2020 से 21 दिन के लिए पंतप्रधान महोदय ने पूर्ण भारतभर में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सख्त एवं पूर्णत: लॉक डाऊन की घोषणा की.

2021 - नीरज का गोल्ड थ्रो

टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता. इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने सर्वाधिक सात पदक जीते.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

-सुश्री मधुलिका कांबले
वरिष्ठ प्रबंधक,
केंद्रीय कार्यालय

राजभाषा गतिविधीयाँ

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पश्चिम एवं मध्य क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में हमारे मुंबई अंचल की गृहपत्रिका यशस्करम का विमोचन किया गया.

दि. 13-14 नवम्बर 2021 को राजभाषा विभाग, द्वारा वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देवरिया का प्रतिनिधित्व करती हुई श्रीमती शुभ लक्ष्मी शर्मा, राजभाषा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, नराकास, देवरिया, साथ में हैं श्री सुरेंद्र यादव, रा.अ. अयोध्या/वाराणसी, श्री संजय गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, लखनऊ, श्री अशोक तनेजा, मुख्य प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली व अन्य.

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में दिनांक 30.12.2021 को राजभाषा पुरस्कार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

बैंक नराकास, अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सदस्य बैंकों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के अहमदाबाद अंचल के श्री विजय नामदेव एवं श्री संजय श्रीवास्तव को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया.

आजादी के 75वें वर्ष में राजभाषा हिन्दी - एक पुनरावलोकन

- राजीव तिवारी
मुख्य प्रबंधक(राजभाषा),
आंचलिक कार्यालय, पुणे

हिंदी को संविधान में राजभाषा का स्थान प्राप्त हुए 73 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अगर हम गंभीरता से इस बार विचार करें तो ये पायेंगे कि इतने वर्षों में अगर इस लक्ष्य की समर्पण के साथ कार्य किया गया होता तो राजभाषा हिन्दी का स्वरूप और विराट होता. हमने इतने वर्षों में राजभाषा हिन्दी को सितम्बर माह की 14 तारीख, प्रथम पखवारा, अंतिम पखवारे तक प्रयोग करने के लिए सीमित कर दिया है. प्रयास चाहे सरकारी हों या संस्थानीय. अगर निरंतर प्रयास किए जाएं तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. हिंदी भाषा की प्रगति और उसे गतिमान बनाये रखने की दिशा में अभी भी बहुत कार्य किया जाना शेष है.

राजभाषा हिन्दी की सांविधिक स्थिति

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर 1945 को स्वीकार किया गया. इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गयी. केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी सह-राजभाषा अंग्रेजी है. सरकार ने नीतियां बनाई लेकिन राजभाषा के साथ अंग्रेजी को हमेशा जोड़े रखा. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर समस्त राज्यों से अधिकारी बनते हैं परंतु अन्य विषयों के साथ राजभाषा की परीक्षा अनिवार्य नही की गई जिसके कारण नौकरशाही और राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिंदी को उसका समुचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध नही हो पाई.

हालांकि आजादी के 75 साल बाद भी कई लोगों को यह नहीं पता कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है. भाषा महज संपर्क या संवाद का जरियाभर नहीं होता. यह किसी देश के संस्कार और संस्कृति का आधार भी होता है. अब चूंकि किसी देश का संस्कार या संस्कृति महज सरकारें तय नहीं कर सकती. किसी देश की संस्कृति व्यापक सामाजिक गतिविधियों से निर्मित होती है. इसमें समूचे समाज की भागीदारी होती है. इसलिए अगर पिछले 75 सालों में भी हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, तो यह महज विभिन्न सरकारों और उनके प्रशासनिक अमलों की ही असफलता नहीं है बल्कि एक समाज के नाते इसमें हम सबकी असफलता सम्मिलित है. हिंदी अगर इतने सालों बाद ही देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनी तो इसकी एक वजह यह भी है कि एक नागरिक होने के नाते हमने के लिए कुछ भी नहीं किया.

ऐतिहासिक तथ्य

1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का आह्वान किया था.उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाता और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, तब तक स्वराज्य की सभी बातें निरर्थक होंगी. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था. सात दशक बाद, भारत में हिंदी के 551 लाख वक्ता हैं, जो इसे सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बनाता है. हालांकि, एक लोकप्रिय संचार माध्यम के रूप में इसके विकास ने अक्सर अन्य भारतीय भाषाओं पर अपने वर्चस्ववादी शासन को थोपने के कथित प्रयासों पर विवादों को जन्म दिया है.

भाषा के प्रति संवेदनशीलता जरूरी

किसी किसी समाज को जब अपनी भाषा से जबरदस्त प्यार और लगाव होता है, तो उस समाज की शैली में प्रत्येक स्तर पर यह परिलक्षित होता. यह देखा गया है कि अगर कोई एक फ्रांसीसी नागरिक फ्रेंच भाषा का कोई शब्द गलत बोलता है, तो वहां के लोग उसे टोकते होते हैं, सिर्फ टोकते नहीं नहीं उसे सही बोलना भी सिखाते हैं. यह भी बताते हैं कि सही बोला जाने क्यों जरूरी है. भाषा में आज मुंह से निकली धोनी नहीं है, वह भाव भी है, एक विचार भी है. उसमें हमारी सोच, समझ, सपने और भविष्य की दृष्टि से सब कुछ समाहित होता है. इसलिए राष्ट्रभाषा के एक संवेदनशील सार्थक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जब भी जहां भी भाषा के साथ विसंगति देखें तो अपना हस्तक्षेप अवश्य दर्ज कराएं. हम यह तो चाहते हैं कि सरकार की कोशिश से हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने में हमारी भी कोई जिम्मेदारी हो सकती हैं, हमारा भी कोई योगदान हो सकता है.

बैंकों में राजभाषा हिन्दी का स्वरूप

वर्ष 1969 एवं 1980 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत अधिकांश बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में परिवर्तित हो गए थे तथा इस प्रकार उन बैंकों पर राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व आ गया था. प्रारंभ में अनेक कागजात एवं विवरणियां के द्विभाषीकरण का कार्य प्रमुखता के साथ किया गया. बैंकों के नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिंदी का उपयोग राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) और राजभाषा नियम, 1976 (गृह मंत्रालय, आधिकारिक विभाग द्वारा अधिनियम के तहत तैयार) द्वारा नियंत्रित होता है. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग व्यापक दिशानिर्देश तैयार करता है और हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम भी तैयार करता है. हिंदी के उपयोग में प्रगति की निगरानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग संचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है.

प्रारंभिक स्तर पर बैंकों में किए गए राजभाषा संबंधी कार्य निम्न प्रकार उल्लेखित हैं :

- भाषाई क्षेत्रों के अनुरूप बैंकों के नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड, काउंटर बोर्ड, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी एवं त्रैभाषी तैयार कराना
- हिन्दी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की आपूर्ति
- रबर की मोहरें द्विभाषी/त्रैभाषी का प्रयोग किया जाना
- प्रपत्रों की छपाई और कोड, नियमावली आदि का अनुवाद
- लेज़रों और रजिस्टरों में हिन्दी में प्रविष्टियाँ करना
- द्विभाषी स्टेशनरी सामग्रियों जैसे लेटर हेड्स, फाइल कवर, लिफाफे, सील, स्टैम्प, नेमप्लेट, आदि का मुद्रण
- हिन्दी में हस्ताक्षर करना
- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में तैयार कराना
- लिफाफों पर पता एवं विवरण हिन्दी में लिखवाना
- उपस्थिति पंजिका में नाम एवं विवरण हिन्दी अथवा द्विभाषी लिखवाना
- सभी रजिस्टर, फाइल कवर इत्यादि हिन्दी में तैयार कराना
- डायरी, वॉल-कैलेंडर, डेस्क-कैलेंडर आदि द्विभाषी रूप से मुद्रित करना
- कोड, मैनुअल, फॉर्म, रबर स्टैंप, सील, साइन बोर्ड आदि का हिंदी में अनुवाद
- आंतरिक परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, आमंत्रण पत्रों आदि के लिए हिन्दी का प्रयोग
- उपहार चेक, यात्री चेक, नकद प्रमाण पत्र आदि द्विभाषी रूप से मुद्रित करना

हिन्दी विभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों आदि की स्थापना तथा हिंदी संवर्ग का गठन.

भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों पर बैंकों के कार्यालयों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, लिपिक कर्मचारी, हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी आशुलिपिक आदि तैनात किए गए तथा हिन्दी प्रकोष्ठों में पर्याप्त संख्या में हिंदी टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए. सभी राजभाषा अधिकारियों को उचित द्विभाषी सॉफ्टवेयर के साथ पीसी उपलब्ध कराए गए. प्रधान कार्यालयों और अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में राजभाषा विभागों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए गए. बैंकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विभिन्न स्तरों पर राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित कराई गई.

कंप्यूटरीकरण के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन का स्वरूप

बैंकों में राजभाषा हिन्दी का महत्व कंप्यूटरीकरण युग के साथ और प्रबलता के साथ बढ़ा. बैंकों में आंकड़ों के आदान प्रदान में हुई सुविधा का लाभ हिन्दी भाषा को भी मिला तथा इस प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यों का स्वरूप निम्न प्रकार परिवर्तित हुआ :

- विभिन्न पोर्टलों पर राजभाषा आंकड़ों/ तिमाही प्रगति रिपोर्ट का आदान प्रदान
- विविध राजभाषा कार्यानवयन समितियों की बैठकों में प्रोजेक्टर एवं अन्य डिजिटल संसाधनों द्वारा प्रदर्शन
- राजभाषा सम्मेलनों में राजभाषा के विकसित टूलों का प्रयोग एवं वर्चस्व
- मशीनीकरण अनुवाद प्रक्रिया का आविर्भाव
- बैंकों द्वारा डिजिटल गृह पत्रिकाओं प्रकाशन
- प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा हिंदी माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण दिया जाना
- उच्चतम प्रशासनिक बैठकों में हिंदी में चर्चा करना और ऐसी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में करना
- वित्तीय, बैंकिंग और आर्थिक विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिखना
- बैंकों की कॉर्पोरेट योजनाओं में हिंदी के उपयोग से संबंधित विषय शामिल करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हिंदी में भाषण दिया जाना
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग करना
- कम्प्यूटरीकृत शाखाओं द्वारा खाताधारकों को खातों के विवरण हिंदी में उपलब्ध कराना
- सभी पर्सनल कंप्यूटरों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना और अधिकतम वर्ड प्रोसेसिंग हिंदी में किया जाना
- शाखा बैंकिंग के लिए द्विभाषी डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्थापित करना
- केवल द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना
- हिंदी के लिए केवल मानक एन्कोडिंग (यूनिकोड फ़ॉन्ट / सॉफ्टवेयर) का उपयोग करना
- बैंकों को अपने प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में हिंदी को एक विषय के रूप में शामिल करना

हिंदी कैसे बनेगी राष्ट्रभाषा

सारांश यह है कि हिंदी अगर पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी तो इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, हम सब लोग इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हैं. हिंदी के प्रति हमारी उदासीनता भाषा संस्कृति को लेकर आसंवेदनशीलता और अंग्रेजी के प्रति आकर्षण जैसे कारणों से ही हिंदी आज भी अपने अपेक्षित प्रतिष्ठित स्थान पर नहीं पहुंच पाई है. ऐसे में आवश्यक है कि हम सब मिले और दोषारोपण करने के बजाए इस दिशा में यथासंभव प्रयास करें. अगर हम चाहते हैं कि हिंदी बहुत ज्यादा उन्नति करें, देश की राष्ट्रभाषा हो तो हमें इन चाहतों का बोझ किसी और पर नहीं डालना होगा, बल्कि हमें खुद भी इसके लिए नागरिक होने के नाते अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है.

आपके भीतर प्रेम भरा है या घृणा, इसे आपकी भाषा तत्काल बता देती है - काका कालेलकर

भागलपुर के वेदा बाबू

- विभूति बी. झा
क्षेत्रीय प्रबंधक, कूचबिहार,
कोलकाता अंचल, पश्चिम बंगाल

अपने देश भारत की भूमि को आजादी दिलाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग और समर्पण से आम जनता को मुख्य धारा में लाकर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था। स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी हेतु तन, मन, धन, सब कुछ देश के नाम कर दिया था। अनेक सेनानियों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन सबके सामूहिक प्रयास से अपना देश आजाद हुआ और हम सब आज एक आजाद देश के नागरिक हैं।

हम सबों को इन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन सब महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके रक्त ने हमें आजादी दिलवायी। उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो प्रसिद्ध हो गये और कुछ सेनानियों के नाम गुमनाम ही रह गये। कुछ ऐसे हुए जिन्हें कभी कभार याद किया गया लेकिन सुर्खियों में नहीं रहे।

ऐसे ही एक व्यक्ति थे हमारे चचेरे दादाजी स्वर्गीय वेदानन्द झा। ये पूरे बिहार में " भागलपुर के वेदा बाबू " नाम से प्रसिद्ध थे। मैं अपने बचपन में उनसे स्वतंत्रता संग्राम की अनेक कहानियाँ सुनता था। आ. वेदा बाबू का जन्म 6 मार्च, 1901 को भागलपुर जिलान्तर्गत, नवगछिया से सटे गोपालपुर थाना के गोसाईं गाँव में हुआ था। इनके पिता वासुदेव झा चाहते थे कि ये भी एक सामान्य ग्रामीण बालक की तरह किसान बने या फिर कहीं सरकारी कार्यालय में कोई लिपिकीय कार्य कर ले। चूँकि खेती बहुत ज्यादा नहीं थी तो चार- पाँच गायें और कुछ बकरियाँ घर में थीं। खेती और पशुपालन से जीवन यापन चल रहा था लेकिन ईश्वर ने नियति में कुछ और सोच रखा था। देश भर में भीतर ही भीतर स्वतंत्रता प्राप्ति की एक लहर चल रही थी। युवकों को जोड़ा जा रहा था। आसपास के कुछ छात्रों ने मिलकर एक समूह बनाया जो आम लोगों को स्वतंत्रता के बाद के जीवन के बारे में बताता था। देश भर में स्वतंत्रता हेतु आवाजें अलग-अलग कोनों से आती ही थीं। गाँधीजी के बिहार दौरे के बाद इनका लोगों को जागरूक करने का प्रयास काफी बढ़ गया। ये घर से बाहर रहने लगे। नारेबाजी और पाँच-दस को जमाकर रैली करना प्रमुख कार्य हो गया। इन लोगों का एक कार्य पुलिस को रोकना भी था जब वो किसी सेनानी को पकड़ने जाये। तंग होने पर पुलिस आकर इनके घर के सामानों को ट्रैक्टर पर उठाकर ले जाती। पुलिस गाय और बकरियों को थाने ले जाते समय रास्ते में कहीं भी दौड़ा देती कि वापस नहीं मिले। इनकी गतिविधियों के कारण 1940 में पटना के कैंप जेल में इन्हें बंद किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में ये एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन को पता चला तो थानेदार ने पकड़कर तीन छात्रों को जमकर पीटा। इनका सिर फट गया था तो एक सिपाही ने छिपाकर बाँधने हेतु एक गमछा दिया और कान में कहा कि सही काम कर रहे हो, डरना नहीं। 1942 में ही इन्हें पकड़कर हजारीबाग कैंप जेल में दो वर्षों तक रखा गया। जेल में इन्हें अन्य सेनानी मिले जिनके साथ मिलकर इन्होंने आगे की योजना बनायी। जेल से निकलने के बाद पुन: भागलपुर में सक्रिय हो गये। पुलिस आकर घर के बचे चौखट और चौकी-बिस्तर ले गयी। गाय और बकरियाँ कब की छीन ले गयी थी। परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। 1945 की एक घटना के बारे में उन्होंने बताया था। उन्हें जिला पुलिस ने पूरे समूह के साथ पकड़ लिया। थानेदार इनसे पहले से ही बहुत परेशान था। सबकी अचेत अवस्था होने तक भरपूर पिटाई की गयी। जमीन पर औन्धे पड़े थे। थानेदार ने अपने एक सिपाही को कहा कि आज इसको छुपाकर जान से मार दो, बार-बार परेशान नहीं करेगा। मारने की कोई तरकीब नहीं सूझी तो साईकिल में हवा भरने वाले पम्प से कान में हवा देने को कहा। कुछ देर कान में हवा दिलवाने के बाद मृत समझ शाम में ट्रैक्टर से गंगा नदी के पास बालू पर फेंकवा दिया। हवा देने वाला सिपाही सहृदय व्यक्ति था, जान बच गयी। इसके बाद पुन: घर से भागते, पुलिस से बचते इन्होंने अपना कार्य जारी रखा। 1946 में पुन: पकड़ में आ गये। इस बार एक वर्ष एक महीने भागलपुर केन्द्रीय कारा में बंद रहे।

1947 में देश के आजाद होने के बाद और गाँधीजी की हत्या के उपरान्त ये एकदम शान्त हो गये। गुमनामी में जीने लगे थे। इनके साथ के अन्य सेनानियों ने इनकी पूरी कहानी बिहार सरकार को बतायी। राज्य सरकार पेन्शन की अनुशंसा हेतु कुछ प्रपत्र माँग रही थी। इन्होंने गृह विभाग को कहा कि पेंशन लेने हेतु स्वतंत्रता संग्राम में नहीं पड़े थे। बाद में अन्य सेनानियों ने भारत सरकार को इनके बारे में बताया। 15 अगस्त, 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गाँधी द्वारा इन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। रेल, बस में आने जाने की सुविधा के साथ पेन्शन भी दी गयी। पुन: 1985 में कांग्रेस स्थापना दिवस पर उन्हें सम्मनित किया गया। वे बहुत चर्चा और सुर्ख़ियों में नहीं रहना चाहते थे। लोग चाहते थे कि वे चुनाव में किसी ख़ास पार्टी के लिए प्रचार करें लेकिन उन्होंने अपने को वर्तमान राजनीति से बिलकुल अलग कर लिया था। उन्हें विश्व राजनीति की बातें पसन्द थीं। वे बहुत कम मात्रा में भोजन करते थे वह भी खासकर रोटी-दाल या रोटी-दूध। राज्य भर के लोग उन्हें 'भागलपुर के वेदा बाबू' बुलाते थे। 93 वर्ष की अवस्था में 24 फरवरी, 1994 को वे परलोक सिधार गये।

आज भी हमलोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष - सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

- छाया पुराणिक
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा),
केन्द्रीय कार्यालय

15 अगस्त, 1947 को शताब्दियों पुरानी विदेशी शासकों के दास्ता के बंधन से हम मुक्त हुए. मानों दासता के अंधकार में शहीदों के बलिदान के जो उल्कापात हुए, अनेक देशभक्तों, स्वातंत्र्य सेनानियों ने अपने सर्वस्व की होली जलाई, सत्याग्रहियों ने जो जनजागरण की मशाल जलाई, उन सबके तेज से विदेशी दासता का अंधकार नष्ट हुआ. कई सदियों के बाद मानों सहस्त्ररश्मी दिवाकर ने भी एक प्रफुल्लित प्रात:काल देखा.

इस हर्ष और उल्हास में भी एक चुभता हुआ काँटा था. अखंड हिंदुस्तान को दो भागों में बांटा गया. भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश भाई-भाई का रिश्ता बदल कर पड़ोसी शत्रु के रूप में खड़े हो गए. अनेक लोग निर्वासित होकर लौटे. शुरु से ही समस्याओं का जन्म हुआ.

अब भारत देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो रहे हैं. स्वतंत्रता के पश्चात भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में उभरा. अपने विचार, संस्कृति, कला और परंपरा से भारत ने विश्व में अपना अलग स्थान निर्माण किया. आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सुधारों के कारण भारत आज विकासशील राष्ट्रों में अग्रसर है.

देश में जन-जन के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयी. पंचवार्षिक योजनाएं बनी. देश में हुई हरित क्राति और श्वेत क्रांती के साथ अनाज तथा दुध में देश आत्मनिर्भर बना. आगे चल कर कई विकास योजनाएं बनी, कार्यान्वित हुई. हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, आदि योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके तक बैंकिंग तथा वित्तेय सेवाएं पहुंचाने के प्रयास जारी है. समाज के हर तबके तक आरोग्य सेवाएं पहुंचाने हेतु 'आयुष्मान भारत' योजना लागू की गयी. सभी के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान अभी भी जारी है. इन 74 वर्षों में देश के कोने कोने में सभी मूलभूत सेवाएं पहुंचाने के प्रयास किए गए जो अभी भी जारी हैं. अब "मेक इन इंडिया" के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यूँ न हो क्या वे जन सामान्यों तक वैसी ही पहुँचती हैं? जनता को इनका लाभ प्राप्त करने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या इन योजनाओं के लिए लगने वाला पैसा जो जनता के कर से सरकार को प्राप्त होता है, सही प्रकार से उपयोग में लाया जाता है? कई बार इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक होते हैं.

बुनियादी सुविधाओं के लिए बनाई गई योजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी नहीं होती और उनकी संकल्पित व्यय राशि दोगुनी हो जाती है. भ्रष्टाचार के कारण योजना की गुणवत्ता में गिरावट होती है.

प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए कि देश की प्रत्येक संपत्ति सार्वजनिक होने के नाते हम उसके मालिक नहीं परंतु संरक्षक हैं. उस संपत्ति का सही उपयोग किया जाना देश के अर्थात हमारे हित में है. सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण हम सबका दायित्व है.

भारत एक विशाल, बहु भाषिक और बहु धार्मिकदेश है. देश की एकता और अखंडता अबाधित रखने के लिए हमें परस्पर सम्मान एवं सहयोग रखना चाहिए. हमें यह भी आत्मसात करना चाहिए कि धर्म और जाति को अपनी वैयक्तिक सीमा के बीच ही रखना चाहिये.

भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण के कारण विकास में बाधाएं आती हैं. शिक्षा क्षेत्र से लेकर आरोग्य विषयक सेवाओं तक सभी क्षेत्रों में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है. इसी कारण उत्पाद तथा सेवाओं की गुणवत्ता में त्रुटि है. हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेनी होगी और उसे निभाना होगा. सभी के सहयोग एवं विश्वास के साथ भारत को स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर बनाने में अपना भी बहुमूल्य योगदान देना होगा.

कृषि, विज्ञान, उत्पाद, सेवा, शिक्षा आदी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हमें सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए तब हमारे उत्पाद या सेवाओं में गुणवत्ता के साथ - साथ बाजार में स्थिर रहने हेतु आवश्यक किफायती दाम भी होगा जिससे जन-जन तक यह पहुंचाया जा सकेगा.

आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें भारतीय भाषाओं पर भी ध्यान देना होगा. स्थानीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान उपलब्ध होने से वह समाज के सभी तबकों तक पहुंच सकेगा. जिससे सम्पूर्ण समाज शिक्षा प्राप्त कर सकेगा. अपनी कला को बढ़ावा देगा.

अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नियम तथा कानून का पालन करने की आदत हमें आत्मसात करनी होंगी. कतारों का पालन करना, शिक्षा के प्रवेश के लिए डोनेशन ना देना, सरकारी या अर्द्ध सरकारी कामकाज करवाने के लिए सूद न देना, सूद न लेना, अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखना, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, परस्पर सहयोग तथा सर्व धर्म समभाव की भावना रखना आदी.

आज हम आदर्शवादिता से दूर जा रहे हैं. हमारे देश को एक महान आध्यात्मिक परंपरा है. पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के कारण हम इस नीतिमान परंपरा से दूर जा रहे हैं. हम पैसा और संपत्ति को ही महत्व दे रहे हैं नीतिमानता को नहीं. यहीं भ्रष्टाचार की जड़ है. आज अधिकतर लोग कर्तव्य की उपेक्षा और अत्यधिक फल की अपेक्षा रखते हैं.

श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 एवं 8 में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है:

यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य दुरात्मानं सृजाम्यहम।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।

जैसा कि हमारी संस्कृति में ही कहा गया है कि "सर्वाभूति परमेश्वर". अत: हम सब में इश्वर का अंश बसा हुआ है. यदि हम सब अपने अंतस्थ परमेश्वर को जगाकर परस्पर सम्मान के साथ कर्तव्यनिष्ठा का निर्वहन करते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर भारत का सपना वास्तव में सच हो जाएगा और भारत विश्व में एक बलवान और नितीमान राष्ट्र माना जाएगा.

आइए हम सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता का दृढ़ संकल्प लें. अपना कार्य करते समय स्वयं को जागरूक रखें. स्वार्थ भाव का त्याग करें और देश को विकास की ओर ले चलें.

तभी हम गर्व से कह सकेंगे "मेरा भारत महान".

गुण से रुप की, सदाचार से कुल की, सफलता से विद्या की तथा भोग से धन की शोभा होती है - चाणक्य

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था

- कुणाल चटर्जी
सहायक प्रबंधक
मासंवि विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे

हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सितारमण ने अपने पिछले बजट के भाषण में संसद के पटल पर भाषण के प्रारंभ में ही ठाकुर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहें गये एक छन्द का प्रयोग किया :-

"आस्था वह चिडिया है जो प्रकाश को महसूस करके
भोर होने से पहले के अंधकार में ही गाना गाती है।"

आज कोविड -19 महामारी ने पृथ्वी के हर कोने में उथल-पुथल मचा रखा है. मानव जाति इस भयावह बीमारी से अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास कर रही है. समस्त डॉक्टर, वैज्ञानिक अथवा नीतिकार इस महामारी का समाधान निकालने में लिप्त है. केवल हमारी आस्था, विश्वास और दृढ़ता ही आज हमें इस विषम परिस्थिति से पार होने में मदद कर सकती है.

भारत की अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ सदियों में अनेक परेशानियों के सम्मुखीन होना पड़ा है. अंग्रेजी सरकार के विभेदक एवं अनिष्टकारी आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया था. उसके साथ ही भारतीय समाज में भेदभाव और कु-संस्कारों को बढ़ावा देकर, अंग्रेजी सरकार ने भारत को गरीबी और भुखमरी के श्रृंखालाओं में बांधे रखने का जाल बुना. इतिहासकारों ने ब्रिटिश राज के दौरान कम से कम 8.5 करोड़ भारतीयों को भुखमरी के कारण मृत्यु होने का आंकड़ा बताया है.

इनके अलावा भारत ने विश्व के अन्यत्र देशों के साथ प्रथम विश्व युद्ध, स्पैनिश फ्लू, द्वितीय विश्व युद्ध, दि ग्रेट डिप्रेशन जैसे अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं का सामना किया है. हालांकि, हम यह कह सकते हैं कि उस काल में देश सभी विषयों में आपस में इतने जुड़े हुए नहीं थे. परंतु आयात-निर्यात एवं आपसी व्यवसाय देशों के मध्य में सशक्त था. स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्र भारत के संस्थापकों ने एक जीर्ण अर्थव्यवस्था को जीवंत करने हेतु अनेक कदम उठाये. एक तोड़े-मरोड़े हुए देश को, उसकी विविधता को एक धागे में पिरोया.

हमारी अर्थव्यवस्था के तीन अहम् भाग :

कृषि: सन 2020-21 के वित्तिय मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार, कृषि वर्ग ने हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जी.डी.पी. में लगभग 20% का योगदान किया है. चूंकि जी.डी.पी. किसी भी देश या अर्थव्यवस्था के अंदर निर्मित चिज़ों के मौद्रिक भाव को दर्शाती या बताती है, कृषि वर्ग भारत की 50% रोजगार योग्य जनसंख्या को रोजगार भी प्रदान करता है. लगभग 70% ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार कृषि से ही गुज़र-बसर करते है. भारत पूरे विश्व में दाल, चावल, गेहूं एवं मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है. इन सभी तथ्यों का एक ही अभिप्राय है कि कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न और अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है, इसके बढ़ोत्तरी या नुकसान से हम देश की समृद्धि का अनुमान लगा सकते है.

उत्पादन/औद्योगिकी वर्ग : भारत की उत्पादन के क्षेत्र में शुरूआत अन्य युरोपियन अथवा अमरिकी देशों के मुकाबले थोड़ी देर से हुई. परंतु हमारे देश ने औद्योगिक क्रांति लाकर अर्थव्यवस्था को अत्याधिक सशक्त किया है. भारतीय औद्योगिकी क्षेत्र उसकी जी.डी.पी. में आज 17-20% का योगदान देता है. भारत स्टील एवं सिमेंट जैसी प्राथमिक उत्पादों में विश्व श्रेणी में दूसरे स्थान पर स्थित है. इसके साथ ही साथ भारतीय औद्योगिक क्षेत्र तमाम वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं. कृषक वर्ग और उसके भरोसे जीवन-पाला करने वाले मजदूर आज छोटे-छोटे फैक्ट्रियों में काम करके अपने परिवार को सम्मानीय जिंदगी देने में सक्षम हुए है. औद्योगिक विकास ने निस्संदेह ही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक रीढ़ की हड्डी की तरह बल प्रदान किया है.

सेवा उद्योग : सेवा उद्योग क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का तृतीयक (टर्शीयरी) वर्ग कहा जा सकता है. टेलीकॉम, हॉस्पिटालिटी, रियल इस्टेट, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र इत्यादि सेवा उद्योग के अंदर गिने जाते हैं. सेवा वर्ग का भारतीय जी.डी.पी. में लगभग 55-60% का योगदान है. यह वर्ग ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल चालक है. सेवा उद्योग भारत से होने वाले विकसित देशों में निर्यात का अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके अलावा बैंकिंग एवं इंश्योरेंस, जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को सेवा प्रदान करते है, इसी उद्योग का हिस्सा है. सेवा उद्योग दूसरे सभी के मुकाबले सबसे ज्यादा रोज़गार प्रदान करता है.

कोविड - 19 से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था की सक्षमता :

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1991 के उदारीकरण के पश्चात, तीव्र गति से प्रगति की है. कुछ विशेष रचनात्मक बदलावों के साथ ही भारत में विदेशी कंपनियों का सीधा निवेश लगभग 300% के दर से विस्तारित होने लगा. नये रोज़गार एवं बेहतर आय होने पर लोगों की प्रयोज्य आय (डिसपोजेबल इन्कम) में वृद्धि हुई, जिससे लोगों ने बचत कर तरह-तरह के क्षेत्रों में भरपूर निवेश किया. हमारी अर्थव्यवस्था के इसी सकारात्मक चक्र में प्रवेश होने पर, भारत का जी.डी.पी. एवं वे प्रत्येक पैरामीटर जिससे अर्थव्यवस्था का मापदंड समझा जा सकता है, तेज़ी से बढ़ने लगें.

कोविड - 19 के आक्रमण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7-8% के दर से वर्ष-दर-वर्ष जी.डी.पी. में विकास कर रही थी. आर्थिक रूप से भारतीय बाज़ारों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाने हेतु व्यापक गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स को कार्यान्वित किया गया. जी.एस.टी. में लगभग सारे ही अप्रत्यक्ष टैक्स जो ग्राहकों, निर्माताओं,आदि को देने पड़ते थे का विलय कर दिया गया है. यह टैक्स रिजिम ने भारतीय बाज़ार जो कि विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में अलग-अलग टैक्स लगाते थे, को अब एक बा. जार बना दिया है, इस कदम से विदेशी निवेशकों को भी व्यवसाय करने में अत्यंत आसानी होगी.

इसके अलावा भारत सरकार ने एक अग्रगामी सोच के साथ 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं का उद्घाटन किया. 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं द्वारा एविएशन, फार्मा और अन्य अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेशों के द्वार खोल दिये. भारत की अर्थव्यवस्था जीर्णाशय से एक स्वस्थ्य रूप लेने लगी थी. समाज कल्याण एवं अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ता के लिए सरकार ने 'स्किल इंडिया' जैसे अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया. कौशल और उद्यमशीलता नव-निवेश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य आधारभूत सुविधाएं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा अन्य कई योजनाओं ने युवाओं, घरेलु महिलाओं तथा सभी वर्ग और क्षेत्रों के लोगों के कौशल विकास में योगदान दिया.

कोविड-19 के प्रहार से पहले, कृषि और एम.एम.एस. ई. क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की, सिंचाई से लेकर निर्यात तक तथा कृषि और कृषि उत्पाद उद्योगों ने हमारे जी.डी.पी. में प्रतिवर्ष के योगदान में बढ़त दिखाई है. इसके साथ ही साथ एम.एस.एम.ई. उद्योग अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी सरकार से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलने के कारण, इन्ही उद्यमियों ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है. पिछड़े और ग्रामीण इलाके के द्वारा भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रदान किये गये अवसरों का भरपूर रूप से उठाया गया है. विभिन्न योजनाएं जैसे कि महिला उद्यमियों को ऋण की व्यवस्था से लेकर, निर्यात उपयुक्त सटीक गुणवत्ता वाले माल का उत्पाद इन सभी तरह से पुख्ता कदमों ने उद्योग वर्ग को मजबूत बनाया है.

भारत ने सेवा उद्योग में सबसे ज्यादा एवं सबसे तीव्र गति से प्रगति हासिल की है. भारत के सेवा उद्योग को कुल 83.14 बिलियन यू.एस. डॉलर का विदेशी निवेश सन 2000 से 2019 तक प्राप्त हुआ है. भारत सम्पूर्ण विश्व में व्यापक रूप से सॉफ्टवेयर सर्विसेस का निर्यातकर्ता है. सेवा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी जी.डी.पी. में सबसे ज्यादा योगदान देता है. रोजगार की दिशा में सेवा उद्योग ने सभी पढ़े-लिखे युवाओं को एक नयी राह दिखायी है. चूंकि यह युग ही सूचना प्रौद्योगिकी का है, सूचना प्रौद्यौगिकी की मदद से हमारे सॉफ्टवेयर इंजिनियर होनहार युवा, खोज कर नित नवीन आयामों के द्वार खोल रहे है. सेवा उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को रक्त की तरह सींच रखा है.

कोविड -19 के बाद - भारतीय अर्थव्यवस्था

कोविड-19 वायरस से संक्रमित बिमारी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर मार्च 2020 के लॉकडाउन के उपरांत प्रारंभ हुआ. केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों और कई राज्यों में यह संक्रमण शुरू हुआ. दूसरे देशों में इसके घातकता का परिणाम देखने पर, हमारी सरकार ने सभी देशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का आह्वान किया. इस लॉकडाउन के अंतर्गत सभी यातायात, दुकानें, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाज़ार आदि को एकाएक बंद करना पड़ा. यह कदम अत्यंत आकस्मिक था परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण भी. इस लॉकडाउन के फलस्वरूप हमने कोविड संक्रमण पर काफी दूर तक रोकने में सक्षम तो रहे, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था अपने तीसरे तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 3% की बढ़त ही जी.डी.पी. में दिखा पायी.

कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हम इन बिन्दुओं को बता सकते है :-

-24% से भी ज्यादा की जी.डी.पी. (अप्रैल-जून 2020-21) में गिरावट.

बेराजगारी में अत्याधिक वृद्धि

सप्लाई चेन में दबाव

सरकारी आय में घटाव

पर्यटन उद्योग का ठप्प हो जाना

उपभोक्ताओं की मांग में कमी

पड़ोसी देशों से मनमुटाव

वर्ल्ड बैंक और क्रिसील जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के इस मंदी के दौर को स्वतंत्रता के पश्चात् की सबसे गंभीर घटना बताया है. 'नॉमयूरा' संस्था ने अपने रिपोर्ट में कुछ आंकड़े कुछ इस प्रकार सामने रखे है :-

बेराजगारीदर 6.7% से बढ़कर 26% हो जाना.

लॉकडाउन के अंदर लगभग 14 करोड़ लोगों का बेरोज़गार होना या आय में कटौती होना.

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक दिन लगभग रु.32,000 करोड़ का नुकसान.

बड़ी कंपनियां जैसे कि लार्सन ट्यूब्रो, बिड़ला, भारत फोर्ज इत्यादि ऑपरेशन में कटौती से स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट.

लगभग 53% व्यवसाय लॉकडाउन के प्रभाव से ग्रसित हुए.

कोविड-19 महामारी ने अकस्मात ही पूरे विश्व को अपने कब्ज़े में कर लिया है. भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर वैसे तो बिन्दु मात्र है, परंतु विश्व की यह पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धराशायी होने पर भी, अपने पैरों पर खड़े होने में अति सक्षम है. कोरोना महामारी के कारण भारत वर्ष ने लगभग 3,00,000 भारतवासियों को खोया है. अनेक परिवार ऐसे भी है जिनको बेराज़गारी और भुखमरी के कारण प्राण त्यागने पड़े है. अनेक लोगों को बैंकों के किश्त न भर पाने के कारण अपनी मेहनत से बनायी हुई दुकान, घर, संस्था से हाथ धोना पड़ा है. कोरोना महामारी ने न केवल अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचायी है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी इस घटना

ने हमें दर्पण दिखाया है.

चुनौतियां : आज भारतीय अर्थव्यवस्था एक अत्यंत अशांत काल से गुज़र रही है. वर्तमान आर्थिक वातावरण आगे आनेवाली मंदी की तरफ इशारा करता है. कोविड-19 महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को एक साथ में कमज़ोर बना दिया है.

जी.डी.पी. के वृद्धि में गिरावट, मुद्रास्फिति में बढ़त या बढ़ती हुई महंगाई, बेराज़गारी की मार-भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मोटे तौर पर चुनौतियां अनेक है. कोविड- 19 के बढ़ते मामले, जो कि अब ग्रामीण और अद्धशहरी इलाकों में ज्यादा पकड़े जा रहे है, इससे आम आदमी मुख्यत: गरीबों के रोज़गार पर अत्यंत भयानक प्रभाव पड़ा है. मैक्रोइकॉनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य से समझा जाये तो कुछ अहम चुनौतियां इस प्रकारहै :-

मंदी मांग - मांग में मंदी या स्टैग्नेटेड डिमांड आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. बुनियादी चीज़े जैसे कि ईंधन, खाद्य पदार्थ, कंज्यूमर पदार्थ तथा बिजली के लिए मांग में बहुत गिरावट आई हैं. बेरोजगारी, धंदे में असफलता, पारिवारिक आय में कमी आने की वजह से उपभोक्ताओं में मांग की कमी हुई है. सी.एम.आई.ई. के रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2019 में केवल 50 लाख नौकरियां गयी है. जहां छोटे-बड़े व्यवसाय काम शुरू कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है, तो उन्हें मंदी की मार का अनुभव करना पड़ रहा है. अर्थशास्त्रज्ञों का भी मानना है कि अनौपचारिक/असंगठित व्यवसाय नौकरीरत

लोगों के आमदनी से ही आगे प्रगति करते है. भविष्य में बेराजगारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बढ़ती हुई बेराजगारी : जैसे कि हमने पहले बताया है. बेरोजगारी के दर में बढ़ोत्तरी हमारी अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत नुकसान देह है. औपचारिक/संगठित क्षेत्रों में लगभग 1.8 करोड़ लोगों की नौकरी से छंटनी का आंकड़ा सी.एम.आई.ई. द्वारा दिया गया है. अनौपचारिक रूप से जहां व्यवसायों ने लॉकडाउन के पश्चात काम शुरू करने की चेष्टा की तो उन्हें भी मांग में गिरावट तथा कर्मचारियों के अभाव से व्यवसाय बंद करना पड़ा. बेराज़गारी इस आर्थिक बदहाली के चक्र में एक हिस्सा है. इसे कम करनेके लिए हमें कुछ सर्जनात्मक कदम उठाने होंगे.

राजस्व प्रोत्साहन (फिस्कल स्टियुलस) - अनेक अर्थशास्त्रज्ञों का यह मानना है कि जब आर्थिक व्यवस्था में मंदी की दशा हो, तब सरकार को लोगों के बीच, उपभोक्ताओं में मांग बढ़ाने हेतु - नियोजित फिस्कल स्टिमुलस पैकेज खर्च करना चाहिए. यह पैकेज विकास को बढ़ावा देने के लिए साधारणत: प्रयोग में लाया जाता है. हमारी सरकार ने भी अनेक बार समय-समय पर राजस्व प्रोत्साहन का प्रयोग किया है, परंतु कोविड-19 के दौरान मुख्यत: यह प्रोत्साहन बैंकों द्वारा व्यवसायों को दी गई अग्रिम राशि के रूप में अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हुए है.

विशेषज्ञों का यह मानना है कि राजकोषीय घाटा - कोविड 19, टैक्स संग्रह में कमी इत्यादि कारणों से अत्यंत ज्यादा होने के कारण, फिस्कल स्टिमुलस भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकता है. हालांकि हमारे वित्त मंत्री ने पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी एवं यात्रा से जुड़े कारोबारों का मदद करने का भरोसा दिलाया है.

बढ़ती मंहगाई - 'मुद्रास्फिति या इंफ्लेशन' ने वर्तमान के अर्थव्यवस्था को और ज्यादा पेंचिदा बना दिया है. जुलाई 2020 में मुद्रासिफीति लगभग 7% के करीब थी, यह आंकड़ा रिज़र्व बैंक के मध्यम अवधि लक्ष्य 4% से अधिक हो गया और सरकार एवं रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति पर विचार करने पर अभी सामान्य दर पर स्थिर है. अर्थशास्त्रज्ञों का यह मानना है कि यह स्थिति अत्यंत जटिल है जहां मांग में मंदी होने पर भी महंगाई दर ज्यादा है.

चूंकि मुद्रास्फिति में बढ़ोत्तरी है तो रिज़र्व बैंक भी अपने मौद्रिक नीतियों एवं ब्याज दरों में अत्याधिक बदलाव नहीं करेगा. फलस्वरूप ज्यादा ब्याज दरों पर कारोबारी अग्रिम/लोन का प्रयोग नहीं करेंगे और इसी प्रकार बा. जारों में निवेश का वातावरण भी मंदा ही रहेगा. यह विषम चक्रव्यूह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है.

इनके अलावा बढ़ती हुई बीमारों की संख्या एवं समय पर सभी का टीकाकरण होना भी एक विराट चुनौती है. एक स्वस्थ भारत से ही एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है. मैक्रोइकॉनोमिक्स की दृष्टि से यह सभी उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान ही अर्थव्यवस्था को पुन: फलता-फूलता बनाने में सक्षम होगा.

समाधान : अर्थशास्त्रज्ञों का यह मानना है कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहें है. उनका जुगाड़ समाधान से हमें आगे भविष्य में फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कोविड-19 द्वारा लाये गये हमारी अर्थव्यवस्था में तमाम चुनौतियों के हमें दीर्घावधि समाधान ढूढ़ने होंगे.

ई.ई.पी.सी. इंडिया एवं एसी आन - भारत ने अपने रिपोर्ट में कुछ सुझाव रखे है. वे इस प्रकार है :-

वर्तमान परिस्थिति में भारतीय सरकार को प्रथमत: शासन प्रबंध में व्यवसायियों के विश्वास को पुख्ता करना होगा. चयनात्मक रूप से कुछ क्षेत्रों के व्यवसायों को परिचालन की अनुमति देनी होगी. इसके साथ ही चयनात्मक रूप से फिस्कल स्टीम्युलस का भी प्रयोग करना होगा.

निर्यातकर्ता जो लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों से लिप्त है उन्हें विशेष प्रोत्साहन देना होगा. कुछ रचनात्मक बदलाव नीतियोंमें लाने हो सकते है, उन्हें बढ़ावा देकर इन उद्योगों में जो असली क्षतिपूर्ति हुई है, उसे संभालना होगा.

कुछ ज़ोन जहां कोविड-19 का कहर बहुत साधारण हो गया हो, उनमें तत्काल बिज़नेस चालू करने की अनुमति देनी चाहिए.

श्रम घनिष्ठ संस्थान या ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के द्वारा काम किया जाता हो, उनमें टीकाकरण के विशेष प्रावधान एवं तेजी दिखानी होगी. कृषि, ट्रान्सपोर्ट, आयात/निर्यात, स्वस्थ इन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना होगा.

इसके साथ ही कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, बीमारी

के लिए औषधी की खोज अत्यंत आवश्यक है, अतएव हमें प्रथमत: दवाई की खोज में अनुसंधान करने हेतु निवेश करना होगा. यह निवेश वैश्विक स्तर पर अनेक देश मिलकर करें तो यह आपदा का निदान संभव है.

इन उपायों के अलावा भी भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को पहले से भी बेहतर बनाने में सक्षम होगी.

टिकाऊ बुनियादी ढ़ांचे के संरचना में निवेश करने से न केवल हम अर्थव्यवस्था में नयी नौकरियां और आर्थिक लेन-देन में तेजी लाएंगे अपितु पर्यावरण सजग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते है. भारत को यह मौका ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर बिजली या रिनियूएबल उर्जा के उत्पादन और पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को बढ़ावा देने में प्रयोग करना चाहिए.

कमज़ोर वर्ग के लोग जो आसानी से इस दुर्व्यवस्था के शिकार हो जाते है, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए. असंगठित वर्ग के कर्मचारियों को संगठित कर औपचारिक धारा में लाना चाहिए. जिनको भी आज भी बैंकों की सेवाओं और उनके बारे में ज्ञान न हो, उन्हें इस कठिन समय में साहुकार/लेनदारों से बचाने के लिए बैंकिंग से जोड़ना चाहिए.

नये तकनीकों के विकास में सरकार को मदद करनी चाहिए, आज इन्हीं प्रौद्योगिकी विकास की वजह से 'वर्क फ्रॉम होम' कर रहे कर्मचारी लोग, बड़ी-बड़ी संस्थाओं का चलने में सहयोग कर रहे है. यही तकनीक भविष्य में आनेवाली ऐसी आपदाओं से दरकार पड़नेपर 'बिज़नेस कन्टूनिटी प्लान' पर हमारी मदद करेंगे.

आज चहु ओर कोविड-19 बीमारी ने जन-मानव में त्राही-त्राही मचा रखी है. स्वस्थ सेवा अर्थव्यवस्था, शासन प्रबंध सभी भाग अस्त-व्यस्त हो रहे है. प्रत्येक परिवार में भय और दु:ख का विचित्र वातावरण बन चुका है. ऐसे में यह एक प्राकृतिक विरोधाभास की कह सकते है जहां एक और असंख्य प्राणियों की मृत्यु हो रही है, तो दूसरी ओर हिमालय पर्वत दूर-दूर तक अपनी श्वेत छटा बिखेर पा रहा है. पक्षी, मछलियां सब आसानी से विचरण कर पा रहे है. प्रकृति का चक्र ही कुछ ऐसा है कि सुर्यास्त के पश्चात् सवेरे का होना ही नियति है. आज मानव जाति के इस युद्ध को हम डॉ. हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचे पढ़े द्वारा कह सकतेहै :-

'धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर,
अग्नि सी धधक-धधक, हिरन सी सजग-सजग
सिंह सी दहाड़ कर, शंक सी पुकार कर
रूके न तू, थके न तू'

अपने बैंक को जानिए दिसम्बर, 2021

KNOW OUR BANK, DECEMBER - 2021

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण DETAILS	इकाई UNIT	मार्च, 2021 अंतिम (31.03.21) March, 2021 FINAL (31.03.21)	नवम्बर, 2021 अंतिम (30.11.21) November, 2021 FINAL (30.11.21)	दिसम्बर, 2021 अंतिम (31.12.21) December 2021 FINAL (31.12.21)
1	**भारत में शाखाएं / BRANCHES IN INDIA**	सं./No.	**4608**	**4545**	**4528**
1.1	ग्रामीण / Rural	सं./No.	1603	1605	1604
1.2	अर्ध शहरी / Semi-Urban	सं./No.	1332	1331	1330
l.3	शहरी / Urban	सं./No.	810	789	783
1.4	महानगरीय / Metropolitan	सं./No.	863	820	811
2	**अनुषंगी कार्यालय / SATELLITE OFFICES**	सं./No.	**10**	**10**	**10**
3	**विस्तार पटल / EXTENSION COUNTERS**	सं./No.	**1**	**1**	**1**
4	**आकारवार शाखाएं / SIZE WISE BRANCHES**	सं./No.	**4608**	**4545**	**4528**
4.1	अत्याधिक बड़ी शाखाएं / ELB	सं./No.	40	22	22
4.2	बहुत बड़ी शाखाएं / VLB	सं./No.	415	551	551
4.3	बड़ी शाखाएं / Large Branches	सं./No.	1274	1637	1637
4.4	मध्यम शाखाएं / Medium Branches	सं./No.	2490	2307	2296
4.5	लघु शाखाएं / Small Branches	सं./No.	311	0	0
4.6	विशेष शाखाएं / Specialised Branches	सं./No.	78	28	22
5	**कुल जमाएं / AGGREGATE DEPOSITS**	₹	**328877**	**333741**	**337016**
5.1	चालू / Current	₹	16259	14550	15972
5.2	बचत / Savings	₹	145667	150683	152585
5.3	मियादी / Time	₹	166951	168508	168459
6	**अनु. वाणि बैंको में से.बैं.इं.का हिस्सा / SHARE OF CBI IN SCBs (DEPOSITS)**	%	**2.16**	**2.10**	**2.07**
7	**प्रति शाखा जमाएं / PER BRANCH DEPOSITS**	₹	**71.37**	**73.43**	**74.43**
8	**औसत जमाएं / AVERAGE DEPOSITS**	₹	**319889**	**330885**	**331223**
9	**पिछले मार्च की तुलना में वृद्धि / GROWTH OVER PREVIOUS MARCH**				
9.1	कुल जमाएं / Aggregate Deposits	%	6.02	1.48	2.47
10	**सीआरआर / CRR:-** ए) अनिवार्य / Obligatory (31.12.2021)	₹	10034	13605	13638
	बी) वास्तविक (औसत) / Actual (Average) (31.12.2021)	₹	10044	13693	13656
11	**एसएलआर / SLR:-** ए) अनिवार्य / Obligatory (31.12.2021)	₹	**60412**	**61280**	**61391**
	बी) वास्तविक / Actual (31.12.2021)	₹	**123697**	**126861**	**123657**
12	**हाथ में नकदी / CASH IN HAND** (31.12.2021)	₹	**1458**	**1718**	**1556**
13	**भारत में स्थित बैंकों में कुल शेष/ BALANCE WITH BANKS IN INDIA** (31.12.2021)	₹	**50**	**81**	**59**
14	**भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCE WITH RBI** (31.12.2021)	₹	**14736**	**13900**	**15301**
15	**निवेश / INVESTMENT**	₹	**153820**	**145075**	**145602**
15.1	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	₹	110414	101543	103915
15.2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities	₹	0	0	0
15.3	अन्य गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां / Other Non SLR Securities	₹	43406	43532	41687
16	**उधार (मांग बाजार) / LENDING (Call Market)**	₹	**200**	**531**	**370**
17	**निवल ऋण (बैंक को छोड़कर ऋण) / NET CREDIT (Excl. Credit to Bank)**	₹	**176913**	**173888**	**182098**
	प्राथमिकता क्षेत्र के लिए समायोजित ऋण (आरआयडीएफ मिलाकर) #	₹	**169787**	**183914**	**183914**
18	**कुल ऋण / TOTAL CREDIT @**	₹	**176913**	**173888**	**182098**
18.1	खाद्य / Food	₹	1775	2640	2667
18.2	गैर-खाद्य / Non Food	₹	175138	171248	179431
18.3	प्राथमिक क्षेत्र / Priority Sector	₹	88222	87705	93689
19	**औसत ऋण / AVERAGE CREDIT**	₹	**175548**	**173174**	**173388**
20	**निर्यात ऋण / EXPORT CREDIT**	₹	**4446**	**4488**	**4362**
21	से.बैं.इं. और अनु.वाणि.बैंक की (31.12.2021) को पिछले मार्च की तुलना में वृध्दि (26.03.2021)		6.22	-4.00	1.18
	कुल ऋण से.बै.इं.	%	5.60	1.94	6.70
	अनु.वाणि बैंक	%			
22	ऋण : जमा अनुपात / CREDIT: DEPOSIT RATIO से.बै.इं. / CBI	%	55.25	52.07	54.05
	अनु. वाणि. बैंक / SCBs	%	72.46	70.74	71.94
	निवल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा (आरआयडीएफ मिलाकर)/ Share of Priority Sector in Adj. Net Credit (incl. RIDF);	%	40.93	40.99	42.66
	निवल ऋण में कृषि का हिस्सा (आरआयडीएफ मिलाकर) / Share of Agriculture in Adj. Net Credir (Incl. RIDF)	%	18.03	18.70	19.16
	निष्क्रिय आस्तियां : कुल जमाएं / Idle Assets: Aggregate Deposits	%	#REF!	#REF!	#REF!
	निवेश : कुल जमाएं / Investment: Aggregate Deposits	%	#REF!	#REF!	#REF!

शाखाओं की कुल संख्या में अनुषंगी कार्यालय शामिल नहीं है.

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकडे 31.12.2021 के हैं (अनुमानित)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नारी शक्ति
को पंख मिलें
सपने उनके अब
उंची उड़ान भरें

महिला उद्यमियों, पेशेवरों, कर्मचारियों
और गृहिणियों के लिए विशेष रियायतें

गृह लक्ष्मी ऋण (6.5%)
और वाहिनी वेहिकल ऋण (7.0%)

www.centralbankofindia.co.in

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

व्हीकल लोन
आपके सपने साकार करने में
आपके साथ

VEHICLE LOAN
With you to make
aspirations come alive

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट आवास ऋण
आपके अपने घर का सपना साकार
करने में आपके साथ

CENT HOME LOAN
With you to make your
dream home come true

बैंकिंग को सरल,
त्वरित एवं सुरक्षित प्रस्तुति

MAKING BANKING
SIMPLER, SMARTER & SAFER

CUSTOMER CARE 1800221911